20 अगस्त, 2022 * वर्ष 31, पृष्ठ संख्या 60, अंक-8

राजस्थान सुजस

आदिवासी कल्याण विशेषांक

आदिवासी लघु कुंभः सीताबाड़ी मेला

हाड़ौती क्षेत्र में बारां जिले के उपखंड शाहबाद के केलवाड़ा कस्बे में प्रतिवर्ष आदिवासी लघु कुंभ के नाम से सुप्रसिद्ध सीताबाड़ी मेला ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष अमावस्या को आयोजित होता है। आध्यात्मिक स्थल सीताबाड़ी में कई राज्यों व जिलों से श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। कई श्रद्धालु कनक दंडवत करते हुए भी यहां आते हैं। बारां जिले के आदिवासी सहरिया समाज की इस पवित्र मेले में गहरी आस्था है। मेला परिसर आदिवासी संस्कृति का दिग्दर्शन कराता है। सीताबाड़ी में स्थित प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर, सीता मंदिर, लव-कुश मंदिर, महर्षि वाल्मीकि मंदिरों के दर्शन भी लोग करते हैं। मंदिरों में जलकुंड बने हैं, जिनमें वाल्मीकि कुंड, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड, सूरज कुंड और लव-कुश कुंड प्रमुख जल कुंड हैं। शिव पार्वती व राधाकृष्ण मंदिर कुंड भी बने हुए हैं। सीताबाड़ी में ही कुछ दूरी पर सीता कुटी बनी हुई है।

आलेख एवं छाया : विनोद मोलपरिया

प्रधान सम्पादक
पुरुषोत्तम शर्मा

सम्पादक
अलका सक्सेना

सह-सम्पादक
डॉ. लोकेश चन्द्र शर्मा

उप-सम्पादक
सम्पत राम चान्दोलिया
आशाराम खटीक

आवरण छाया
अमित सारस्वत

राजस्थान सुजस में प्रकाशित सामग्री में व्यक्त विचार लेखकों के अपने एवं आंकड़े परिवर्तनशील हैं। आवश्यक नहीं कि शासन उनसे सहमत हो। सुजस में प्रकाशित सामग्री का विभाग किसी भी रूप में उपयोग कर सकेगा।

ग्राफिक डिजाइनिंग
कृष्णा प्रिंटर्स

सम्पर्क
सम्पादक
राजस्थान सुजस (मासिक)
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग
सचिवालय, जयपुर-302005
मो. नं. 98292-71189
94136-24352
e-mail :
editorsujas@gmail.com
publication.dipr@rajasthan.gov.in
Website :
www.dipr.rajasthan.gov.in

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान का मासिक

वर्ष : 31 अंक : 08 | अगस्त, 2022

इस अंक में

लोक जीवन	02
सम्पादकीय	04
आदिवासियों के समग्र कल्याण...	11
उच्च शिक्षा	19
आवासीय विद्यालयों का सुदृढ़ीकरण...	23
सूचना तकनीक से हो रहा...	26
जनजातीय जीवन	28
तीज उत्सव	29
75 वर्ष, 75 उपलब्धियां	42
योजना	46
स्वतंत्रता सेनानी	47
स्वतंत्रता आंदोलन	48
राजीविका	50
पर्यावरण संरक्षण	52
संस्कृत दिवस	53
सद्भावना दिवस	54
खेल-खिलाड़ी	58
धरोहर	59
तस्वीर बदलाव की	60

जनजाति कल्याण की ओर...

05

जनजाति कल्याण महोत्सव...

16

साक्षात्कार

20

बातचीत

22

फोटो फीचर

30-31

सामयिकी

32

संग्रहालय

56

राजस्थान सुजस के आगामी अंक के लिए मौलिक, अप्रकाशित सामग्री भिजवायें। कृपया अपने आलेख एवं फोटोग्राफ सम्पादक को e-mail : editorsujas@gmail.com पर अथवा डाक से भेजें।

आदिवासी कल्याण के लिए संकल्पित राज्य सरकार

स्वतंत्रता दिवस का अमृत महोत्सव प्रदेश में धूमधाम एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। घर-घर तिरंगा फहराने के साथ ही राजकीय भवनों पर आकर्षक रोशनी की गई। स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर लोगों में जबरदस्त उमंग दिखाई दी।

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने विश्व आदिवासी दिवस 2022 के मौके पर बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम पर पहुंचकर वहां स्थित स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ 399 करोड़ रुपये के विभिन्न कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रदेश में आदिवासियों के कल्याण के लिए कृत संकल्पित राज्य सरकार ने आदिवासी क्षेत्रों में स्थानीय लोगों के साथ बैठकर आदिवासियों की कठिनाइयों और समस्याओं के समाधान के लिए चिंतन-मनन किया। मुख्यमंत्री ने बांसवाड़ा के मानगढ़ में 291.77 करोड़ रुपये, सांगडूंगरी में 42 करोड़ रुपये और उदयपुर जिले के भीण्डर में 22 करोड़ 23 लाख रुपये के विभिन्न कार्यों का शिलान्यास व लोकार्पण किया।

मुख्यमंत्री ने सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित राज्यस्तरीय समारोह में ध्वजारोहण कर प्रदेशवासियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि वर्तमान में राजस्थान हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। राज्य सरकार ने जनकल्याणकारी योजनाएं शुरू कर स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, विद्युत और सामाजिक सुरक्षा सहित सभी क्षेत्रों के आधारभूत ढांचे को मजबूत किया है। लोक कलाकारों ने जोश और उल्लास के साथ मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किये। लोगों ने उत्साह के साथ समारोह में भागीदारी निभाई। प्रदेश में जगह-जगह स्वतंत्रता दिवस का अमृत महोत्सव मनाया गया।

आदिवासी कल्याण पर आधारित राजस्थान सुजस का अगस्त माह का अंक आपके हाथों में है। स्वतंत्रता दिवस के आयोजनों के साथ सांस्कृतिक पर्वों और राज्य सरकार की योजनाओं व कार्यक्रमों को इस अंक में समावेशित किया गया है।

अभिवादन एवं मंगलकामनाओं सहित,

(पुरुषोत्तम शर्मा)
प्रधान सम्पादक

विश्व आदिवासी दिवस पर मानगढ़ समारोह को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत

जनजाति कल्याण की ओर अग्रसर राजस्थान

विकास योजनाओं के सफल क्रियान्वयन से आसान हो रही जनजाति कल्याण की राह

राजेन्द्र भट्ट, भा.प्र.से.
आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग

किसी भी विकासशील देश के लिए यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि समाज के सभी वर्ग देश की आर्थिक और सामाजिक समृद्धि में हिस्सेदारी करें। यह व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है कि भारतीय आबादी के एक बड़े हिस्से, विशेष रूप से जनजाति समुदायों के उत्थान के लिए प्रभावी रूप से निरंतर कार्य करने की आवश्यकता है। राजस्थान में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की ओर से राज्य के जनजाति के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक उत्थान हेतु कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। विभागों के आपसी समन्वय और आमजन के सहयोग से योजनाओं से जनजाति लोगों के जीवन में काफी सुधार हुआ है। विभिन्न योजनाओं की सफलता से जनजाति कल्याण की राह आसान होकर सरकार की मंशा सार्थक हो रही है।

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के राज्य मंत्री श्री अर्जुन सिंह बामनिया द्वारा इस अंचल में पूरी निष्ठा व समर्पण के साथ विकास योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में नेतृत्व व निर्देशन प्रदान किया जा रहा है। जनजाति कल्याण की राज्य सरकार की मंशाओं को सार्थक करने की दृष्टि से राज्य मंत्री द्वारा इन विकास योजनाओं व लोककल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए ग्राम पंचायत स्तर से लेकर राज्य मुख्यालय तक भ्रमण कर व बैठकें लेते हुए लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है।

शिक्षा से साकार हो रहा जनजाति कल्याण का सपना

जनजाति समुदाय में स्तरीय शिक्षा मुहैया करवाने एवं बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के प्रयासों, तकनीकी नवाचारों एवं अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ जनजाति विद्यार्थियों को दी जा रही शिक्षा भी हाईटेक हुई है। दूसरी तरफ शैक्षिक प्रोत्साहन की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जनजाति प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में विभाग के माध्यम से कुल 408 आश्रम छात्रावासों एवं 44 आवासीय विद्यालयों व ईएमआरएस छात्रावासों का संचालन कर 96,622 छात्रों व 37,795 छात्राओं को लाभान्वित किया गया। कक्षा 10वीं व 12वीं में 65 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाली 7,341 छात्राओं को प्रोत्साहन स्वरूप स्कूटियां दी जा चुकी हैं वहीं 82,583 जनजाति छात्राओं को महाविद्यालय में अध्ययन हेतु तथा 84,032 जनजाति छात्राओं को कक्षा 11 व 12 में अध्ययन के लिए आर्थिक सहायता

प्रोजेक्टर से अध्ययन करती हुई जनजाति क्षेत्र के राजकीय विद्यालय की छात्राएं

प्रदान की गई है। इसी प्रकार 33,903 छात्रों का गृह किराया पुनर्भरण किया गया है, वहीं 7,953 जनजाति छात्रों को बोर्ड व विश्वविद्यालय में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर प्रतिभावान छात्रवृत्ति राशि दी गई।

इंटीग्रेटेड स्मार्ट क्लासरूम में शिक्षण

जनजाति अंचल के विद्यार्थियों को इक्कीसवीं सदी के अनुरूप स्तरीय शिक्षा प्रदान करने की दृष्टि से जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा संचालित 36 आवासीय विद्यालयों में 72 स्मार्ट क्लास एवं 87 आश्रम छात्रावासों में कुल 160 इंटीग्रेटेड स्मार्ट क्लासरूम विकसित किये गये हैं। विषय विशेषज्ञों की अनुपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान के उद्देश्य एवं प्रभावी विषयाध्यापन शिक्षण हेतु शिक्षकों, छात्रावास अधीक्षकों एवं 5 विद्यार्थियों को संचालन तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान कर शिक्षण करवाया जा रहा है। इस योजना में 6 करोड़ 40 लाख का बजट प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार एडू ट्राइब एप को भी विकसित करते हुए शिक्षण में नवाचार अपनाया गया है।

कोचिंग के साथ स्तरीय सुविधाएं भी

विभाग द्वारा 718 जनजाति विद्यार्थियों को नीट, जेईई, आईआईटी में प्रवेश परीक्षा हेतु स्तरीय कोचिंग उपलब्ध कराई गई। जनजाति वर्ग के 84 हजार 389 विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म एवं स्टेशनरी हेतु डीबीटी के माध्यम से व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं से लाभान्वित किया गया। आवास के साथ शुद्ध व शीतल पेयजल के लिए जनजाति छात्रावासों व विद्यालयों में से 100 छात्रावासों में आर.ओ.वाटर कूलर स्थापित किये गये हैं, वहीं 63 जनजाति कन्या छात्रावासों व विद्यालयों में सेनेटरी नेपकिन्स निस्तारण संयंत्र स्थापित किये गये हैं। सहरिया क्षेत्र के प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों के 39,345 विद्यार्थियों को पोशाक, पुस्तकें व स्टेशनरी प्रदान की गई तथा इस क्षेत्र के विद्यार्थियों को यूनिफार्म इत्यादि क्रय करने हेतु राशि बढ़ाकर कक्षा 1 से 5 तक 1000 रुपये एवं कक्षा 6 से 12 तक 2,500 रुपये किया गया। सहरिया क्षेत्र के कॉलेज स्तर के 2,482 विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान कर लाभान्वित किया गया।

प्रशासनिक व नीट परीक्षा की कोचिंग

जनजाति विद्यार्थी भी प्रशासनिक व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हासिल कर सकें, इस दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना में यूपीएससी व आरपीएससी एवं राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं की कोचिंग कराई जा रही है। इसी योजना में प्रतिष्ठित संस्था के माध्यम से उदयपुर मुख्यालय पर गत सत्र में 200 जनजाति छात्राओं को नीट की आवासीय कोचिंग प्रदान की गई।

जनजाति उपयोजना क्षेत्र के राजकीय विद्यालय की स्मार्ट क्लास

शैक्षिक सुविधाओं का विस्तार

बारां जिले के सहरिया क्षेत्र-खुशियारा, कोयला, कवाई एवं परानिया में सहरिया जनजाति हेतु संचालित 4 आवासीय विद्यालयों को माध्यमिक से उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत किया गया। राजकीय जनजाति बहुउद्देशीय छात्रावास कोटा में रहकर 1 छात्रा का आईआईटी, 2 का एनआईटी एवं 5 का नीट में चयन हुआ है। नवीन आश्रम छात्रावास टीमरवा, खजुरा-जिला बांसवाड़ा, पई, सेमारी-जिला उदयपुर, वरली-जिला सिरोही, धोलापानी-जिला प्रतापगढ़, राजसमन्द-जिला राजसमन्द में प्रारंभ किये गये। आश्रम छात्रावासों तलवाड़ा-जिला बांसवाड़ा, पादरबड़ी, सितारामपुर, बिछीवाड़ा, चुण्डावाड़ा एवं पीठ-जिला डूंगरपुर, अपरीखेड़ा-जिला सिरोही में क्षमता वृद्धि की गई।

मां-बाड़ी केन्द्र

वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल में अनुसूचित क्षेत्र, माडा क्षेत्र तथा सहरिया क्षेत्र के 82 हजार 590 विद्यार्थियों को 2753 मां-बाड़ी केन्द्रों में प्रतिवर्ष अनौपचारिक शिक्षा प्रदान कर लाभान्वित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री की 250 नवीन मां-बाड़ी केन्द्र प्रारंभ करने की बजट घोषणा क्रम में 214 मां-बाड़ी केन्द्र प्रारंभ कर दिये गये हैं।

मां-बाड़ी केन्द्र

सेंटर ऑफ एक्सीलेंस

जनजाति छात्र-छात्राओं को नीट, जेईई, आर.ए.एस., आई.ए.एस. व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग हेतु सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स का निर्माण कराया जा रहा हैं। अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (जनजाति बालिका छात्रावास निर्माण) उदयपुर में बनाये जाने के लिए आयुक्तालय द्वारा 20 सितंबर 2019 को 1776 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई थी। वर्तमान में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस चित्रकूट नगर भुवाणा में निर्माणाधीन है।

ऑपरेशन विद्या भूमि

बांसवाड़ा जिले में विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों को आवंटित भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कराने हेतु ''ऑपरेशन विद्या भूमि'' के नाम से विशेष अभियान 2 अक्टूबर 2020 से 14 नवम्बर 2020 तक चलाया गया, जिसके अन्तर्गत विभागीय आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया गया।

कौशल विकास से संवरा कॅरियर

शिक्षा की सुविधाओं के बाद कॅरियर निर्माण की दिशा में भी प्रयास किए जा रहे हैं। विभाग द्वारा जनजाति क्षेत्र के युवाओं को विभिन्न प्रशिक्षण एवं प्रोफेशनल कोर्स के माध्यम से स्वरोजगार के जोड़ने का कार्य हो रहा है। विभाग द्वारा आयोजित रोजगार मेले में लगभग 1043 जनजाति युवक-युवतियों ने भाग लिया जिसमें से 394 योग्य उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र प्रदान किये गये। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के सहयोग से उदयपुर एवं जयपुर में जनजाति छात्राओं हेतु रोजगार शिविर का आयोजन कर 81 जनजाति छात्राओं का चयन किया गया है। इसके अतिरिक्त आरएसएलडीसी, सीपेट एवं एमएसएमई के माध्यम से 2260 युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण दिया गया।

खेलों में निखर रही हैं जनजाति प्रतिभाएं

अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुके जनजाति खेल रत्न श्री लिम्बाराम व श्री धूलचंद डामोर के क्षेत्र में जनजाति प्रतिभाओं को निखारने के लिए जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के माध्यम से राज्य सरकार सतत प्रयासरत हैं। इन खिलाड़ियों को विभिन्न अकादमियों व खेल छात्रावासों के माध्यम से अन्तरराष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही हैं वहीं अव्वल आने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि व सरकारी नौकरी जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं।

खेल प्रतिभाओं से चर्चा करते हुए जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्यमंत्री श्री अर्जुन सिंह बामनिया

अन्तरराष्ट्रीय स्तर की हॉकी अकादमी

राज्य सरकार द्वारा जनजाति विद्यार्थियों को अन्तरराष्ट्रीय स्तर के हॉकी प्रशिक्षण हेतु उदयपुर में बालक एवं बालिकाओं की हॉकी अकादमी प्रारंभ की गई है। इस अकादमी में अन्तरराष्ट्रीय स्तर के एस्ट्रो टर्फ मैदान पर राष्ट्रीय स्तर के कोच द्वारा 70 जनजाति छात्र-छात्राओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। राज्य क्रीड़ा परिषद्, जयपुर द्वारा खेलगांव उदयपुर में निर्मित हॉकी एस्ट्रोटर्फ पर जनजाति वर्ग के 40 बालक एवं 30 बालिकाओं को विभाग द्वारा नियुक्त मुख्य कोच ओलम्पियन अर्जुन अवार्डी हॉकी प्रशिक्षक श्री अशोक ध्यानचन्द द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

खेल छात्रावासों से संबल

राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में क्षेत्र में 13 खेल छात्रावासों का संचालन किया जा रहा है। जिसमें 3 हजार 428 विद्यार्थियों को राज्य सरकार ने लाभान्वित किया है। प्रतापगढ़ एवं बांसवाड़ा जिला मुख्यालय पर इंडोर खेल स्टेडियम प्रारंभ कर दिया गया है। विभाग द्वारा संचालित खेल छात्रावासों में पूरक पोषाहार उपलब्ध कराने हेतु भोजन सामग्री की राशि में वृद्धि करते हुए 2600 रुपये प्रतिमाह प्रति विद्यार्थी किया गया है। अनुसूचित क्षेत्र में जनजाति छात्रों को खेलकूद हेतु प्रोत्साहित करने व उन्हें राष्ट्रीय-अन्तरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं हेतु तैयार करने के उद्देश्य से 1 खेल अकादमी व 12 खेल छात्रावास संचालित किये जा रहे हैं। खेल छात्रावास-खेल अकादमी में सम्पूर्ण राज्य के कक्षा 6 से 12वीं तक जनजाति खिलाड़ियों को प्रवेश दिया जाता है। छात्रावास में विद्यार्थियों का चयन विशिष्ट प्रकार के कौशल परीक्षणों के आधार पर किया जाता है।

मेलों-पर्वों पर खेल स्पर्धाएं

उदयपुर अंचल में आयोजित होने वाले विभिन्न मेलों, पर्वो व त्योहारों पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कर परंपरागत खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। अनुसूचित क्षेत्र में जनजाति समुदाय के लिए बांसवाड़ा जिले की पंचायत समिति, आनन्दपुरी, बागीदौरा, तलवाड़ा तथा प्रतापगढ़ जिले में पंचायत समिति अरनोद एवं धरियावद में प्रतिवर्ष आयोजित मेलों में जनजाति खेलकूद प्रतियोगिता एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है। आदिवासियों के सबसे बड़े तीर्थ बेणेश्वर धाम पर आयोजित होने वाले मेले में जनजाति उपयोजना क्षेत्र के सभी जिलों से

आने वाले जनजाति लोगों के लिए परम्परागत खेल प्रतियोगिताएं व गैर नृत्य प्रतियोगिता आयोजित होती हैं। इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए जनजाति लोग आकर्षक वेशभूषा व धनुष-बाण आदि लेकर आते हैं। जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर, जिला प्रशासन डूंगरपुर एवं राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, जयपुर के संयुक्त तत्वावधान में मेला स्थल पर इन पारम्परिक खेलों के आयोजन के साथ विजेता, उपविजेताओं को पुरस्कार देकर प्रोत्साहित किया जाता है।

उत्कृष्ट प्रदर्शन पर नकद पुरस्कार

राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेलकूद प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जनजाति प्रतिभावान बालक-बालिकाओं को प्रोत्साहन स्वरूप नकद राशि दिये जाने का प्रावधान है। इसके तहत किसी भी अन्तरराष्ट्रीय खेल या क्रीड़ा में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर 5 लाख रुपये तक, द्वितीय स्थान प्राप्त करने पर 3 लाख रुपये तक व तृतीय स्थान प्राप्त करने पर 2.5 लाख रुपये तक नकद राशि दी जाती है। इसी प्रकार किसी भी राष्ट्रीय स्तर पर खेल या क्रीड़ा में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर 2 लाख रुपये तक, द्वितीय स्थान प्राप्त करने पर 1.5 लाख रुपये तक तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने पर 1.25 लाख रुपये तक राशि दी जाती है। इसके साथ ही राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने पर 1 लाख रुपये तक, द्वितीय स्थान प्राप्त करने पर 50,000 एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने पर 30,000 रुपये तक राशि प्रदान की जाती है।

आधारभूत संरचनाओं का विकास

जनजाति कल्याण के उद्देश्य से जनजाति उपयोजना क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा आधारभूत साधन-सुविधाओं में अभिवृद्धि करते हुए राहत दी जा रही है। वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल में विभाग के माध्यम से कई विकास कार्यो की सौगात दी गई है। जनजाति क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए सामुदायिक जलोत्थान परियोजना में 50 सौर ऊर्जा आधारित सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजना का कार्य पूर्ण किया गया। आवागमन सुविधा के लिए बांसवाड़ा के मलवासा, खानपुरा में 2.89 करोड़ रुपये के डामर सड़क निर्माण कार्य पूर्ण किए गए हैं वहीं बांसवाड़ा के आम्बापुरा, उदयपुर के सराड़ा, प्रतापगढ़ के पीपलखूंट व डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर डूंगरपुर में 94.69 करोड़ रुपये के 4 नवीन एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का कार्य लगभग पूर्ण है। राजसमंद जिला मुख्यालय व बांसवाड़ा के कुशलगढ़ में दो नवीन आश्रम छात्रावास का संचालन शूरू किया गया है।

जनजाति महत्त्व के धार्मिक स्थलों के विकास हेतु बेणेश्वर-जिला डूंगरपुर, सवाईमाता-जिला बांसवाड़ा एवं मंचीद-जिला राजसमन्द हेतु राशि 3 करोड़ रुपये की स्वीकृत जारी की गई है। जनजाति अंचल के 4 आईटीआई परिसर में जनजाति छात्र-छात्राओं हेतु विशेष बैच चलाने के लिये प्रशिक्षण भवनों का निर्माण कराया गया। छात्रावासों में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु 10 करोड़ रुपये के फर्नीचर क्रय किये गये।

किसानों को आधुनिक तकनीक का संबल, कृषकों को मिला रोजगार

जनजाति क्षेत्रों के कृषकों के सुदृढ़ीकरण एवं कृषि व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम संचालित किये जा रहे है। कृषकों को उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध कराए जा रहे हैं एवं विभिन्न योजनाओं में अनुदान के माध्यम से आधुनिक कृषि उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उन्नत कृषि के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से कृषकों के सुदृढ़ीकरण के साथ कृषि व्यवसाय को बढ़ावा दिया जा रहा है। विभिन्न वन एवं कृषि उपज के माध्यम से कृषकों को रोजगार भी मुहैया करवाया गया है।

कृषि विकास कार्यक्रम में 33 हजार 192, उद्यानिकी कार्यक्रम से 3370 एवं पशुपालन कार्यक्रम से 20 हजार 942 परिवारों को लाभान्वित किया गया। पांच लाख 90 हजार कृषकों को कृषि विभाग

विश्व आदिवासी दिवस समारोह में आदिवासी महिला का अभिनंदन करते हुए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत

उदयपुर में विश्व आदिवासी दिवस समारोह में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत

के माध्यम से नि:शुल्क संकर मक्का बीज मिनी-किट (5 किलोग्राम प्रति कृषक) का वितरण खरीफ-2020 में किया गया। वर्ष 2022 में उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही एवं बारां में 5 लाख 90 हजार जनजाति कृषकों को 89 करोड़ रुपये के नि:शुल्क हाइब्रिड मक्का बीज मिनी किट वितरण किये गये।

मुख्यमंत्री बजट घोषणा वर्ष 2022-23 के तहत जनजाति कल्याण कोष खरीफ-2022 में जनजातीय कृषकों को नि:शुल्क हाइब्रिड मक्का बीज मिनी किट वितरण योजनान्तर्गत 8 लाख कृषकों को लाभान्वित किया जा रहा है। योजनान्तर्गत प्रत्येक लाभार्थी कृषक को 5 किलो संकर मक्का बीज उपलब्ध कराया गया है।

सामुदायिक वनाधिकार विकास योजना लाई रंग

वनाधिकार अधिनियम की प्रक्रिया के सरलीकरण हेतु ऑनलाइन दावे प्राप्त कर निस्तारण की कार्यवाही प्रारम्भ की गई है। वनाधिकार अधिनियमों के अंतर्गत सामुदायिक पट्टों पर विकास कार्य हेतु नवीन "सामुदायिक वनाधिकार विकास योजना" लागू की गई है। जनजाति क्षेत्रों में सामुदायिक वन अधिकार पट्टों उपलब्ध कराने के लिए विशेष अभियान चलाया जाकर पट्टे वितरित किये गये। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी अधिनियम 2006 के अंतर्गत 1 लाख 12 हजार 356 दावे प्राप्त किये जाकर 46 हजार 487 व्यक्तिगत एवं 579 सामुदायिक वनाधिकार कुल 47 हजार 66 हक पत्र जारी किये गये, जिनका राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जा रहा है।

वन धन विकास केन्द्र दे रहे रोजगार

जनजाति परिवारों को उनके द्वारा संग्रहित लघु वन उपजों का मूल्य संवर्धन कर मार्केटिंग के बेहतर अवसर सृजित करने हेतु वनधन विकास योजनान्तर्गत अब तक 479 वनधन विकास केन्द्रों का गठन किया जा चुका है। इन केन्द्रों को ट्राइफेड द्वारा स्वीकृति भी प्रदान की जा चुकी है। इस योजना के संचालन से प्रति वनधन विकास केन्द्र औसतन लगभग 300 सदस्यों सहित 8 जिलों में 1,44,803 सदस्य लाभान्वित होंगे। बजट वर्ष 2021-22 में अनुसूचित जनजाति के समावेशी विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा 100 करोड़ रुपये का जनजाति विकास कोष बनाया गया है। इस कोष के माध्यम से जनजाति क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, ढांचागत विकास आदि क्षेत्रों में अतिरिक्त विकास कार्य स्वीकृत कर अंतराल की पूर्ति की गयी। इसी प्रकार वर्ष 2022-23 में राशि 500 करोड़ (200 करोड़ रुपये रोजगारोन्मुखी गतिविधियों एवं कृषि के लिए, 150 करोड़ रुपये शिक्षा एवं सामाजिक सुरक्षा के लिए तथा 150 करोड़ रुपये आधारभूत संरचना एवं जनसहभागिता से कराये जाने वाले कार्यों के लिए) व्यय किये जा रहे हैं।

जल पहुंचाने के लिए कटिबद्ध सरकार

सुदूर गांवों की जनजातियों बस्तियों में शुद्ध पेयजल सुलभ कराने के लिए सरकार प्रयासरत है। संभाग में जनजाति बस्तियां बिखरी हुई और पहाड़ी क्षेत्र में निवासरत हैं। सरकार की दूरदर्शी योजनाओं से अब इन सुदूर इलाकों में भी शुद्ध जल पहुंच रहा है, जिससे जनजाति लोगों को राहत मिली है।

जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा जनजाति उपयोजना, गैर उपयोजना क्षेत्र में पाइप्ड योजना संचालित है। वंचित जनजाति बाहुल्य ग्रामों-ढाणियों में पम्प एण्ड टैंक योजना, पाइप्ड योजना, पनघट योजना, ट्यूबवेल, ओपनवेल मय एसेसरिज (विद्युत कनेक्शन सहित) पाइप लाइन घरों में पेयजल, हैण्डपम्प निर्माण कराया गया है।

जनजाति उपयोजना एवं अन्य क्षेत्र में वृहद, मध्यम एवं लघु सिंचाई योजनाओं की नहर प्रणालियों के रखरखाव एवं संधारण हेतु बजट उपलब्ध कराया गया ताकि जनजाति कृषकों के खेतों की सिंचाई निर्बाध रूप से होती रहे। इसी प्रकार जनजाति क्षेत्र में कृषक हित में भूमि के कटाव को रोकने एवं वर्षा के पानी के संग्रहण के उद्देश्य से जल संग्रहण ढांचों (एनिकट इत्यादि) का निर्माण किया जा रहा है। योजनान्तर्गत पूर्व वर्षों में निर्मित जल संग्रहण ढांचों के सम्पूर्ण उपयोग हेतु उनकी मरम्मत/जीर्णोद्धार के कार्य भी कराये गए हैं। जनजाति कृषकों को सौर ऊर्जा पम्प संयंत्र स्थापना हेतु 45 हजार रुपये दिए जा रहे हैं।

विभिन्न योजनाओं से दे रहे राहत

राज्य सरकार द्वारा जोधपुर संभाग में जनजाति वर्ग के सर्वांगीण विकास हेतु मारवाड़ जनजाति विकास बोर्ड का गठन किया गया है वहीं जनजाति क्षेत्र में जन सहयोग से सर्वांगीण विकास हेतु जनजाति

भागीदारी योजना भी प्रारंभ की गई। जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा पूर्व में संचालित 31 आश्रम छात्रावासों एवं 2 कॉलेज छात्रावासों को और अधिक सुचारु रूप से चलाने के लिये विभाग को हस्तान्तरित किया गया है।

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के माध्यम से उपयोजना क्षेत्र में जनजाति महत्त्व के ऐतिहासिक स्थलों पर दर्शनार्थियों के लिए आधारभूत सुविधाओं का निर्माण यथा सामुदायिक भवन, पेयजल, एप्रोच रोड आदि का निर्माण किया जा रहा है।

जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में भौगोलिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए जनजाति उपयोजना क्षेत्र में अवस्थित विभिन्न संस्थानों को मुख्य सड़क अथवा मुख्य ग्राम से सम्पर्क सड़क व पुल (जो सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अपने नॉर्म्स के अंतर्गत नहीं करवाए जाते हैं), से जोड़ा जाकर आवागमन को समुचित सुविधा का विकास किया जा रहा है।

अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में क्षय रोग उन्मूलन योजना जनजाति क्षेत्रीय विकास मद से संचालित की जा रही है। ऐसे गांवों में जहां पर चिकित्सा सुविधा की पहुंच का अभाव है, वहां पर स्वास्थ्य सहयोगी महिला को इस योजना से जोड़ा गया है। गांव वालों द्वारा उनके गांव की ऐसी महिला को स्वास्थ्य सहयोगी बनाया जाता है, जो गांव की जानकारी रखती है तथा गांव वाले उससे परिचित होते हैं। वर्तमान में जनजाति क्षेत्र में उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही, राजसमंद, पाली जिलों में 4984 गांवों में स्वीकृति मिली है जिनमें से 4622 गांवों में स्वास्थ्य सहयोगिनी सेवाएं दे रही हैं।

जनजाति क्षेत्र उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, आबूरोड, माडा क्षेत्र में जयपुर, दौसा, टोंक, सवाईमाधोपुर एवं सहरिया क्षेत्र बारां जिले के आवासीय विद्यालय, एकलव्य मॉडल रेजिडेन्सियल स्कूल में सोलर पनघट, आर.सी.सी टैंक, सी.सी.टी.वी इत्यादि का कार्य स्वच्छ परियोजना द्वारा करवाये गए जिसमें सभी (लगभग 221) कार्य पूर्ण हो चुके हैं।

जनजातीय परिवारों को कुपोषण से निवारण हेतु प्रतिमाह, प्रति व्यक्ति 250 मिली लीटर देशी घी, 500 ग्राम दाल एवं 500 मिली लीटर सोया तेल नि:शुल्क उपलब्ध करवाया जाकर अनुमानित 3,253 यूनिट कथौड़ी, 1,17,750 यूनिट सहरिया एवं 9,066 यूनिट खैरवा जनजाति के परिवारों को लाभान्वित किया जा रहा है।

वर्ष 2022-23 में किये जाने वाले प्रमुख कार्य

जनजाति कल्याण की दृष्टि से राज्य सरकार की मंशाओं के अनुरूप जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए कार्ययोजना तैयार की गई है। इसके तहत प्रतापगढ़ के नागदी में आश्रम छात्रावास का पुन: निर्माण कराया जाएगा। सिरोही के मानपुर में एक बहुउद्देश्यीय छात्रावास भवन का निर्माण व सिरोही जिला मुख्यालय पर एक खेल छात्रावास का निर्माण कराया जाएगा। अंचल के 40 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों एवं 10 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों की सुविधार्थ 107 कक्षा-कक्षों का निर्माण कराया जाएगा। अनुसूचित क्षेत्र के 10 राजकीय महाविद्यालयों में प्रवेश की मांग के दृष्टिगत 50 कक्षा-कक्षों का निर्माण कराया जाएगा। वन क्षेत्र में स्थित ग्राम पंचायत छापा की नाल उदयपुर के 6 ग्रामों का विद्युतीकरण कराया जाएगा। क्षेत्र में आवागमन सुविधा के लिए 56 सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। इसी प्रकार 10 जलग्रहण संरचनाओं का निर्माण एवं 2 नहरों के आधुनिकीकरण एवं मरम्मत का कार्य कराया जाएगा। बांसवाड़ा जिले के समाई माता एवं घाटोल में नर्सरी एवं आधारभूत सुविधाओं का विकास करवाया जाएगा। स्वच्छ पेयजल हेतु 137 जनजाति बाहुल्य स्थलों पर सोलर/विद्युत आधारित पम्प एवं टेंक योजना स्थापित की जाएगी।

मानगढ़ धाम में गोविन्द गुरु के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत

अनुसूचित क्षेत्र के लघु एवं सीमान्त जनजाति कृषकों को खरीफ फसल हेतु हाइब्रिड मक्का बीज मिनी किट वितरित किए जाएंगे। मारवाड़ क्षेत्र के जनजाति छात्र-छात्राओं को शिक्षा प्रोत्साहन हेतु जोधपुर में नवीन जनजातीय आवासीय विद्यालय प्रारंभ किया जा रहा है वहीं मारवाड़ क्षेत्र के जालौर, पाली, सिरोही एवं बाड़मेर जिलों में 6 नवीन छात्रावास प्रारंभ किये जायेंगे।

योजना के तहत तिवरी (जोधपुर), नाथद्वारा (राजसमन्द) एवं सवाईमाधोपुर में नवीन जनजाति छात्रावास प्रारंभ किये जायेंगे। जनजाति भागीदारी योजना अन्तर्गत 30 प्रतिशत जनसहयोग-जनभागीदारी के साथ जनजाति क्षेत्र में आधारभूत संरचना विकास के कार्य कराये जायेंगे। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना अन्तर्गत 5 वर्षों में 4302 जनजाति बाहुल्य वाले ऐसे ग्रामों जिनमें न्यूनतम 50 प्रतिशत आबादी जनजाति हो एवं न्यूनतम जनजाति संख्या 500 है, का समग्र विकास कर इन्हें आदर्श ग्राम के रूप में विकसित किया जायेगा।

उदयपुर में विश्व आदिवासी दिवस पर लोक कलाकारों के साथ मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत

आदिवासियों के समग्र कल्याण को समर्पित राजस्थान

महेश चंद्र शर्मा
वरिष्ठ पत्रकार

नौ अगस्त को पूरे विश्व ने आदिवासी दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया। संयुक्त राष्ट्र ने इस वर्ष 2022 की धारणा- 'पारम्परिक ज्ञान के संरक्षण और प्रसारण में स्वदेशी आदिवासी महिलाओं की भूमिका' तय की है। सिर्फ यही नहीं, वर्ष 2022 से 32 के बीच पूरे एक दशक को 'आदिवासी भाषा दशक' के रूप में मनाए जाने की घोषणा भी की है।

आदिवासी वे समूह हैं जो प्रकृति और वन्य जीव-जंतुओं के साथ सह-जीवन जीते आए हैं। विश्व में आज यदि कहीं पर्यावरण सुरक्षित है, तो वह आदिवासी क्षेत्रों में ही है। आदिवासियों का जीवन धरती, जल, जंगल, पहाड़, वन्यजीवों के साथ गुजरता है, वे उसके प्रति समर्पित रहते आए हैं।

आज विश्व में नब्बे देशों में पचास करोड़ आदिवासी हैं। उनकी सात हजार मातृभाषाएं और बोलियां भी हैं। हमारे देश में ऐसी जनजातियों की आबादी करीब अठारह करोड़ के आसपास होगी। राजस्थान में आदिवासियों की आबादी, कुल जनसंख्या का करीब चौदह फीसदी है। राज्य के आठ जिले ऐसे हैं जहां आदिवासियों की आबादी सत्तर फीसदी से अधिक है।

सेवा हमारा कर्म और धर्म

इनके समग्र विकास एवं कल्याण के लिए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत पूरी तरह समर्पित हैं। उन्होंने विश्व आदिवासी दिवस बांसवाड़ा के मानगढ़ और सांगडूंगरी इलाके में समारोह पूर्वक मनाया। वहां आयोजित मुख्य समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने बड़े मर्म की बात कही जो इन पंक्तियों में निहित है- ' यह दिन आदिवासियों की कठिनाइयों और समस्याओं के समाधान के लिए चिंतन और मनन करने का अवसर देता है। सेवा ही हमारा कर्म और धर्म है।'

तीन सौ निन्यानवें करोड़ के विकास कार्य

मुख्यमंत्री ने इस मौके पर आदिवासी क्षेत्रों के विकास को समर्पित तीन सौ निन्यानवें करोड़ रुपये के विभिन्न कार्यो का लोकार्पण व शिलान्यास किया।

मानगढ़

मुख्यमंत्री ने शहीद स्मारक पर नमन किया और पुष्पांजलि अर्पित की। गोविंद गुरु तथा मानगढ़ के शहीदों की याद में श्रद्धांजलि दी।

मानगढ़ में 291.77 करोड़ रुपये के विभिन्न कार्यो का शिलान्यास किया। जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के 88.30 करोड़ की लागत के 33 कार्य, सार्वजनिक निर्माण विभाग के लगभग 74 करोड़ के 6 कार्य, जलसंसाधन विभाग के 129 करोड़ रुपये के कार्यो का शिलान्यास किया। इसके अलावा 65 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न कार्यो का भी लोकार्पण किया।

मानगढ़ धाम का विकास, मेडिकल कॉलेज और अंग्रेजी स्कूल

वर्तमान राज्य सरकार आदिवासी तीर्थ मानगढ़ धाम के विकास पर निरंतर कार्य कर रही है। जनजाति क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज, अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले गए। बागीदोरा और आनंदपुरी के अस्पताल की क्षमता का विस्तार कर उसे सौ शैय्याओं का किए जाने की घोषणा की गई।

अनास पुल का शिलान्यास

सांगडूंगरी में 42 करोड़ रुपये की लागत से बनाए जाने वाले अनास पुल की आधारशिला रखी गई है। इससे लोगों को जिला मुख्यालय बांसवाड़ा और गुजरात में आवागमन की सुविधा होगी। इससे बागीदोरा पंचायत समिति और गांगड़ तलाई के बीच दस किलोमीटर और गुजरात राज्य जाने के लिए 15 किलोमीटर की दूरी कम होगी।

संवेदनशील और समर्पित

यह अवसर विशेष पर की गई घोषणाएं भर नहीं है बल्कि पहले से ही मुख्यमंत्री ने अपने शासन के पिछले तीन सालों में और इस वित्तीय वर्ष 2022-23 के वार्षिक बजट में आदिवासी क्षेत्रों के विकास से जुड़ी अनेक घोषणाएं की हैं, जो यह प्रमाण है कि वे किस हद तक इस वर्ग विशेष के प्रति कितने संवेदनशील और समर्पित रहे हैं।

पांच सौ करोड़ का विशेष विकास कोष

मुख्यमंत्री ने वर्ष 2022-23 के वार्षिक बजट में जनजाति कल्याण के लिए विशेष राजस्थान पैटर्न लागू करने व सौ-सौ करोड़ रुपये के विकास कोष बनाने की घोषणा की गई थी। इस बार राजस्थान स्टेट एससी एंड एसटी डवलपमेंट फंड प्लानिंग, एलोकेशन और यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज बिल पेश किया। इसके तहत यह राशि सौ से बढ़ाकर पांच सौ करोड़ रुपये कर दी गई है।

योजना के तहत दो सौ करोड़ रोजगारोन्मुखी गतिविधियों एवं कृषि के लिए, डेढ़ सौ करोड़ शिक्षा एवं सामाजिक सुरक्षा के लिए, डेढ़ सौ करोड़ आधारभूत संरचना एवं जन सहभागिता के लिए प्रावधान किए गए हैं।

प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, बारां जिलों में इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना शुरू की गई है। इसमें दूसरी संतान के जन्म पर छह हजार रुपये की सहायता योजना का दायरा बढ़ाया गया। इससे साढ़े तीन लाख गर्भवती महिलाएं प्रतिवर्ष लाभान्वित होंगी। इस योजना पर 210 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा

पश्चिमी राजस्थान में गैर-अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में छात्र-

उदयपुर में विश्व आदिवासी दिवस पर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत

पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी राजस्थान में एक आदिवासी समारोह में

छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की सुविधा के लिए तीस करोड़ की लागत से 400 छात्र-छात्राओं के लिए पाली, सिरोही, जालौर, बाड़मेर और जैसलमेर में जनजाति छात्रावासों का संचालन किया जाएगा।

पालनहार योजना में शून्य से छह वर्ष आयुवर्ग के अनाथ बच्चों को मिलने वाली सहायता राशि 500 से बढ़ाकर डेढ़ हजार की गई है तो 6 से 18 वर्ष की एक हजार से बढ़ाकर दो हजार पांच सौ रुपये की गई है। बीस करोड़ की लागत से 14 हजार बच्चों को लाभान्वित किया गया।

यही नहीं, आदिवासी क्षेत्रों में उद्यम विकास के निमित्त डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एससी-एसटी उद्यमी प्रोत्साहन विशेष पैकेज में नौ तरह की राहत दी गई हैं।

वागड़ ट्यूरिस्ट सर्किट

डूंगरपुर-बांसवाड़ा क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मानगढ़धाम, देव सोमनाथ, बेणेश्वर, गलियाकोट, अर्थूना-त्रिपुरा सुंदरी, कड़ाना-माही बजाज सागर, कागजी पिकअप, घोटिया अम्बा आदि पर्यटन एवं धार्मिक स्थलों को सम्मिलित कर वागड़ टूरिस्ट सर्किट बनाया गया है।

आदिवासी विश्वविद्यालय

गुरु गोविंद जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा में दस करोड़ की लागत से वैदिक गुरुकुल की स्थापना की गई है। लोक कलाकारों के मानदेय और भत्तों में पच्चीस फीसदी बढ़ोतरी की गई है।

सौर ऊर्जा के लिए अनुदान

एससी-एसटी वर्ग के किसानों को 45 हजार रुपये तक का सौर ऊर्जा उपयोग पर अनुदान दिया जाने की घोषणा की गई थी।

जल संसाधन की कई परियोजनाएं

बांसवाड़ा में माही परियोजना के नहरी तंत्र वितरिकाओं के सुदृढ़ीकरण के जीर्णोद्धार पर 545 करोड़ का प्रावधान किया गया है। घाटोल-बांसवाड़ा में खमेसरा नहर प्रणाली में लघु सिंचाई योजना प्रथम से चतुर्थ, फव्वारा सिंचाई पद्धति आधारित वितरण प्रणाली का सौ करोड़ की लागत से करवाया गया।

चित्तौड़, प्रतापगढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर लिंक में सिंचाई परियोजनाओं के सुदृढ़ीकरण एवं जीर्णोद्धार परियोजना में 121 अतिरिक्त गांवों को भी कमांड क्षेत्र में शामिल किया गया है।

दो हजार पांच सौ करोड़ की लागत से बांसवाड़ा, कुशलगढ़ एवं बागीदोरा के कुल 338 गांवों के चालीस हजार 905 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है।

माही बेसिन के अधिशेष जल से पीपलखूंट तहसील, प्रतापगढ़ के अनकमांड क्षेत्र में सिंचाई के लिए, पीपलखूंट हाइलेवल कैनाल का दो चरणों में निर्माण कराया जाएगा। इस पर बीस हजार करोड़ की लागत आएगी। इससे पांच हजार हैक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

भीखाभाई सागवाड़ा नहर-बांसवाड़ा की लघु सिंचाई योजना सप्तम, अष्टम एवं नवम लघु वितरिकाओं के कार्य करवाये जाएंगे। दसवीं व ग्यारहवीं वितरण प्रणाली की डीपीआर बनायी जाएगी। हरिदेव जोशी नहर तंत्र बांसवाड़ा में करीब एक सौ बीस करोड़ रुपये की लागत से रखरखाव एवं जीर्णोद्धार का कार्य करवाया जाएगा।

अन्य शिक्षण संस्थान

प्रतापगढ़-खैरवाड़ा, उदयपुर-खेड़ला बुजुर्ग महुआ, करौली-टोड़ाभीम में कृषि महाविद्यालय खोले गये। नाथद्वारा, राजसमंद में पशुपालन प्रशिक्षण संस्थान और राजसमंद में तीस करोड़ की लागत से

उदयपुर में विश्व आदिवासी दिवस समारोह में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत

मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया जा रहा है।

जनजाति विकास के लिए किए गए तीन वर्षों की गतिविधियों पर एक नजर–

शिक्षा

दसवीं–बारहवीं कक्षा में 65 फीसदी से अधिक अंक पाने वाली 7246 छात्राओं को स्कूटियां वितरित की गईं। महाविद्यालय में अध्ययन करने पर 63,371 एवं कक्षा 11 और 12 में अध्ययन करने पर 57,103 जनजाति की छात्राओं को आर्थिक सहायता दी गई।

जनजाति छात्र–छात्राओं को व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने तथा सरकारी नौकरियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना प्रारंभ की गई। यूपीएससी, आरपीएससी एवं राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं की कोचिंग कराई जा रही है। उदयपुर में 200 जनजाति छात्राओं को नीट की आवासीय कोचिंग प्रदान की जा रही है।

महारानी कॉलेज जयपुर की सौ और मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर की 200 जनजाति छात्राओं को राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा की कोचिंग दिसंबर, 2021 से प्रारंभ की गई।

राजकीय जनजाति बहुउद्देश्यीय छात्रावास कोटा में रहकर 1 छात्रा का आईआईटी, 2 का एनआईटी एवं 5 का नीट में चयन हुआ।

सहरिया क्षेत्र के प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के 39,345 विद्यार्थियों को पोशाक, पुस्तकें व स्टेशनरी प्रदान की गई।

सहरिया क्षेत्र के छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति यूनिफॉर्म इत्यादि क्रय करने के लिए कक्षा 1 से 5 तक राशि बढ़ाकर 1 हजार रुपये एवं कक्षा 6 से 12 तक दो हजार पांच सौ रुपये की गई। सहरिया क्षेत्र के कॉलेज स्तर के 1233 विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान की।

बारां जिले के सहरिया क्षेत्र–खुशियारा, कोयला, कवाई एवं परानिया में सहरिया जनजाति के लिए संचालित 4 आवासीय विद्यालयों को माध्यमिक से उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत किया।

खेल–कूद

प्रतापगढ़ एवं बांसवाड़ा जिला मुख्यालय पर इंडोर खेल स्टेडियम निर्माण कार्य पूर्ण कर स्टेडियम शुरू।

खेल छात्रावासों में पूरक पोषाहार उपलब्ध कराने के लिए भोजन सामग्री की राशि में वृद्धि छब्बीस सौ रुपये प्रतिमाह प्रति विद्यार्थी की गई।

जनजाति छात्र–छात्राओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर के हॉकी प्रशिक्षण के लिए उदयपुर में हॉकी अकादमी प्रारंभ कर राष्ट्रीय स्तर के कोच द्वारा 70 जनजाति छात्र–छात्राओं को एस्ट्रो टर्फ मैदान पर प्रशिक्षण शुरू।

सिंचाई

जनजाति क्षेत्र में सामुदायिक जलोत्थान परियोजना के माध्यम से 50 सौर ऊर्जा आधारित सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजना की मंजूरी जारी। 32 कार्य पूर्ण, शेष प्रगतिरत। चार नवीन एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय आम्बापुरा–बांसवाड़ा, सराड़ा–उदयपुर, पीपलखूंट–प्रतापगढ़ एवं डूंगरपुर में प्रारंभ। दो नवीन आश्रम छात्रावास

बालिका छात्रावास राजसमंद तथा बालक छात्रावास खजूरा, कुशलगढ़-बांसवाड़ा का संचालन प्रारंभ।

आवासीय विद्यालय

434 आवासीय विद्यालयों-छात्रावासों के लिए सुपोषण वाटिका एवं पंचफल उद्यान के तहत स्वीकृति।

अनुसूचित क्षेत्र सलूंबर, झाड़ोल, खैरवाड़ा, लसाड़िया-उदयपुर, धरियावाद, अरनोद-प्रतापगढ़, सागवाड़ा-डूंगरपुर, गढ़ी-बांसवाड़ा में 8 नवीन एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय स्वीकृति।

कृषि

वर्ष 2020 में खरीफ फसल के लिए 5.90 लाख किसानों को कृषि विभाग के माध्यम से नि:शुल्क संकर मक्का बीज मिनी किट 5 किलोग्राम प्रति कृषक को वितरित।

वन

वनाधिकार अधिनियम की प्रक्रिया के सरलीकरण के लिए ऑनलाइन दावे प्राप्त कर निस्तारण की कार्यवाही प्रारंभ। वनाधिकार अधिनियम के अंतर्गत 8,294 दावे मिले। 6,133 दावों को पुन: समीक्षा कर 4,751 दावे स्वीकृत। वनाधिकार हक पत्र जारी।

उदयपुर में विश्व आदिवासी दिवस समारोह में पौधारोपण करते हुए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत

उदयपुर में विश्व आदिवासी दिवस पर लोक कलाकारों के साथ मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत

वनाधिकार अधिनियम के अंतर्गत सामुदायिक पट्टों पर विकास कार्य के लिए नवीन सामुदायिक वनाधिकार विकास योजना लागू।

जनजाति प्रतिभा सम्मान

वर्ष 2019-20 में जनजाति प्रतिभा सम्मान समारोह जिला मुख्यालय बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़ एवं आबूरोड़ जिला सिरोही में 9 अगस्त 2019 को आयोजित कर विश्व आदिवासी समारोह में 335 जनजाति प्रतिभावान छात्र-छात्राएं सम्मानित। वर्ष 2020-21 में जनजाति प्रतिभा सम्मान समारोह में 213 अभ्यर्थियों के लिए स्वीकृति जारी।

जनजाति विकास बोर्ड

जोधपुर संभाग में जनजाति वर्ग के सर्वांगीण विकास के लिए मारवाड़ जनजाति विकास बोर्ड का गठन। वर्ष 2021-22 में अनुसूचित जनजाति के समावेशी विकास के लिए सौ करोड़ रुपये के जनजाति विकास कोष की स्थापना।

कुल मिलाकर आदिवासी क्षेत्रों के विकास के प्रति वर्तमान सरकार गंभीर और संवेदनशील है। अब आदिवासी क्षेत्रों में उनकी संस्कृति, मातृभाषाओं के संरक्षण देने की ओर भी ध्यान केंद्रित करना होगा ताकि हमारे पर्यावरण संरक्षण कार्यों को निरंतर बढ़ावा मिलता रहे।

उदयपुर में विश्व आदिवासी दिवस समारोह को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत

जनजाति कल्याण महोत्सव : विश्व आदिवासी दिवस

डॉ. कमलेश शर्मा
उपनिदेशक, जनसंपर्क, उदयपुर

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने विश्व आदिवासी दिवस, 2022 के मौके पर बांसवाड़ा के मानगढ़ व सांगडूंगरी में 399 करोड़ रुपये के विभिन्न कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास किया। उन्होंने विश्व आदिवासी दिवस की बधाई देते हुए कहा की यह दिन हमें आदिवासियों की कठिनाइयों और समस्याओं के समाधान के लिए चिंतन और मनन करने का अवसर प्रदान करता है। राज्य सरकार ने इसके महत्त्व को ध्यान में रखते हुए विश्व आदिवासी दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है।

मानगढ़ में 356 करोड़ के लोकार्पण एवं शिलान्यास

मुख्यमंत्री ने मानगढ़ में 291.77 करोड़ रुपये के विभिन्न कार्यों का शिलान्यास किया। उन्होंने जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के 88.30 करोड़ रुपये की लागत के 33 कार्य, सार्वजनिक निर्माण विभाग के लगभग 74 करोड़ रुपये के 6 कार्य, जल संसाधन विभाग का 129 करोड़ रुपये के कार्यो का शिलान्यास किया। इसके अलावा उन्होंने 65 करोड़ रुपये की लागत के विभिन्न कार्यो का लोकार्पण भी किया।

सांगडूंगरी में 42 करोड़ रुपये की लागत से 18 माह में बनेगा पुल

मुख्यमंत्री ने बांसवाड़ा के सांगडूंगरी में 42 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले अनास पुल की आधारशिला रखी। इससे लोगों को जिला मुख्यालय बांसवाड़ा और गुजरात में आवागमन में सुविधा होगी। अनास नदी पर सांगडूंगरी से बोरखंडी को जोड़ने वाले पुल के निर्माण के लिए इसी बजट में घोषणा की थी। इससे बांसवाड़ा जिले की बागीदोरा पंचायत समिति और गांगड़ तलाई के बीच 10 किलोमीटर और गुजरात जाने के लिए 15 किलोमीटर दूरी कम हो सकेगी।

मुख्यमंत्री ने भींडर में दी सौगातें

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने उदयपुर जिले के भींडर में 22 करोड़ 23 लाख रुपये के चार विकास कार्यो का शिलान्यास किया। यहां श्री गहलोत ने महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) वल्लभनगर में बालकों एवं बालिकाओं के लिए अलग-अलग छात्रावास भवन निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इसका निर्माण 8.83 करोड़ की लागत से होगा। साथ ही लगभग 4.50 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले राजकीय महाविद्यालय भवन कुराबड़ एवं 4.50 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले श्री गजेन्द्र सिंह शक्तावत राजकीय कन्या महाविद्यालय भवन भींडर का भी शिलान्यास किया। उन्होंने सीएचसी मेनार के विस्तार कार्य का शिलान्यास किया। यहां 4.40 करोड़ रुपये के कार्य होंगे। इससे 30 बेड्स की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

मुख्यमंत्री ने कलाकारों को किया प्रोत्साहित

हेलीपैड पर जनजाति कलाकारों ने आकर्षक वेशभूषा में परंपरागत वाद्ययंत्रों की स्वर लहरियों के साथ गैर नृत्य करते हुए मुख्यमंत्री का स्वागत किया। जनजाति वाद्य ढोल, कुंडी व थाली की ताल पर डांडियों के साथ थिरकते लोक कलाकारों के साथ मुख्यमंत्री ने भी डांडिये थाम और ढोल पर ताल देकर कलाकारों को प्रोत्साहित किया।

मानगढ़ स्मारक स्थल पर मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत

उदयपुर में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत

जनजाति हॉकी अकादमी

जनजाति अंचल की खेल प्रतिभाओं को उचित मंच उपलब्ध कराने की दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा विश्व आदिवासी दिवस पर प्रदेश की पहली जनजाति बालक-बालिका हॉकी अकादमी की सौगात दी गई। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने विश्व आदिवासी दिवस, 2021 पर वर्चुअल समारोह में राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा नवनिर्मित उदयपुर के खेलगांव में हॉकी एस्ट्रो टर्फ खेल मैदान पर संचालित अकादमी का शुभारंभ कर खिलाड़ियों को यह सौगात दी।

5.40 करोड़ से बना हॉकी एस्ट्रो टर्फ

उदयपुर के महाराणा प्रताप खेल गांव में नवनिर्मित प्रदेश का तीसरा हॉकी एस्ट्रो टर्फ जिस पर अकादमी का संचालन होगा, का निर्माण राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा कार्यकारी एजेंसी आरएसआरटीसी ने करवाया। इसके निर्माण में कुल 5.40 करोड़ रुपये की लागत आई है। इस अकादमी में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों के लिए पूर्व में जनजाति बालक-बालिकाओं की चयन स्पर्धा रखी गई। इसमें संभाग स्तर पर 40 बालक तथा 30 बालिकाओं का चयन किया गया है। चयनित खिलाड़ियों को विभाग द्वारा नियुक्त मुख्य प्रशिक्षक अर्जुन अवार्डी एवं ओलंपियन श्री अशोक ध्यानचंद द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा।

मिशन कोटड़ा

शिक्षा व जागरूकता का अभाव तथा विषम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण क्षेत्र विशेष विकास की मूलधारा से दूर होता जाता है। ऐसी स्थितियों में सरकार की लोकहितकारी योजनाओं का पूरा-पूरा लाभ दिलाना सरकार और स्थानीय प्रशासन के लिए चुनौती भरा साबित होता है। उदयपुर जिले का सुदूर कोटड़ा क्षेत्र 'काला पानी' संज्ञा को लिए हुए इन्हीं स्थितियों से जूझता प्रतीत होता था परंतु राज्य सरकार के निर्देशानुसार सुशासन के लिए नवाचार शृंखला में जिला कलक्टर द्वारा शुरू किया गया 'मिशन कोटड़ा' ऐसा ही प्रयास है जिसके सुपरिणाम इन दिनों नज़र आ रहे हैं।

पालनहार से शुरू हुआ राहत का सिलसिला

'मिशन कोटड़ा' की शुरूआत पालनहार योजना से वंचित अनाथ, जरूरतमंद बच्चों व महिलाओं को लाभांवित करने से हुई। जिला कलक्टर को जब क्षेत्र में हजारों की संख्या में पात्र बच्चों के पालनहार योजना से वंचित होने की जानकारी मिली तो उन्होंने क्षेत्र में ऐसे बच्चों की सर्वे से अपने मिशन की शुरूआत की। उस वक्त क्षेत्र में मात्र 1 हजार बच्चे इससे जुड़े हुए थे और सर्वे में इतने ही नये पात्र बच्चों की जानकारी मिली। फिर इन बच्चों को चिन्हित करते हुए उनके अपेक्षित प्रमाण पत्र तैयार करवाने के लिए घर-घर कर्मचारियों को भेजा, विशेष शिविर लगाए और हर पात्र को इस योजना से जोड़ा। इस क्षेत्र में 1,956 बच्चों को पालनहार योजना से जोड़ा जा चुका है। कोटड़ा में 37,603 पेंशनर्स, 1,156 को दिव्यांग प्रमाणपत्र व 159 को सिलिकोसिस प्रमाणपत्र जारी किये गये हैं।

आधारभूत सुविधाओं से पहुंची विकास की किरण

दूरस्थ अंचल होने के कारण बिजली, पानी, सड़क, आवागमन सहित अन्य आधारभूत सुविधाओं के अभाव के कारण सही मायनों में विकास नहीं हो पा रहा था। जिला प्रशासन ने इन्हीं आवश्यकताओं को अनुभूत करते हुए समस्याओं के चिह्नीकरण कर उनके समाधान की दिशा में एक-एक कर प्रयास किए। क्षेत्रवासियों की आवागमन सुविधा के लिए रोड़वेज की 5 बसें प्रारंभ की गई। इसी प्रकार आदिवासी कृषकों को उनकी उपज का पूरा-पूरा दाम मिले। इसके लिए कृषि उपज मण्डी का शुभारंभ भी किया गया। लंबे समय से क्षतिग्रस्त सड़क के सुदृढ़ीकरण के लिए विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए 25 किमी क्षतिग्रस्त सड़क का डामरीकरण करवाया गया। स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कौशल विकास के तहत प्रशिक्षण शुरू किया गया है। कोटड़ा में औद्योगिक विकास की संभावनाओं को देखते हुए रीको औद्योगिक क्षेत्र से प्रस्ताव निगम मुख्यालय जयपुर भिजवाए गये हैं वहीं राजीविका के माध्यम से उदयपुर डेयरी के 9 बूथ संचालित किये जा रहे हैं।

मिशन कोटड़ा के तहत संचालित सार्वजनिक परिवहन सेवा

शहर जैसी सुविधाओं को उपलब्ध कराने की पहल

अब तक विभिन्न सुविधाओं से वंचित रहे कोटड़ा क्षेत्र में शहर जैसी स्तरीय सुविधाओं को उपलब्ध कराने की पहल इस मिशन के तहत की गई है। इस अभियान के दौरान 17 हजार 352 ई-श्रम कार्ड बनाये गये वहीं पीएचसी, आदर्श पीएचसी व सब सेंटर निर्माण के कार्यादेश जारी किए गए। क्षेत्र में खेल सुविधाओं के विस्तार व विकास के तहत डिंगारी फला में 46 लाख की स्वीकृति तथा 176 लाख रुपये की लागत से 9 नये खेल मैदानों का विकास कार्य प्रारंभ किया गया है। क्षेत्र में नरेगा के तहत वनपथ निर्माण का कार्य शुरू किया गया है। इसी तरह कोटड़ा को गुजरात नेटवर्क से जोड़कर रिंग कनेक्टिविटी प्रदान की गई है ताकि ऑनलाइन उपलब्ध हो रही विभिन्न विकास योजनाओं का लाभ मिल सके। दो बसों को पुन: प्रारम्भ कर सबसे पिछड़े राजस्व गांवों में प्रशासन एवं ई-गवर्नेन्स घर-घर तक पहुंचाने की कार्यवाही भी की जा रही है।

जारी है मिशन की गतिविधियां

वर्तमान में डोर स्टेप सेवा के तहत आधार, जन-आधार व अन्य नामांकन की सुविधा ग्राम स्तर पर प्रदान कर व आवश्यक दस्तावेज तैयार करने एवं समस्त कार्यवाही कर लाभ से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही कोटड़ा क्षेत्र के खिलाड़ियों एवं लोक कलाकारों को संबल देने के लिए जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं एवं कार्यक्रमों में सम्मिलित किया जा रहा है। जिला कलक्टर ने योजनाओं की प्रभावी क्रियान्विति एवं समीक्षा हेतु नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की है और जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ प्रति दो माह में पंचायत समिति मुख्यालय पर बैठक आयोजित कर प्रगति की समीक्षा की जा रही है। क्षेत्र के विकास के लिए कार्यरत स्वयंसेवी संगठन एवं हितधारकों के साथ निरन्तर बैठक आयोजित की जा रही है तथा जनप्रतिनिधियों से निरन्तर संवाद कर योजनाओं की क्रियान्विति एवं प्रचार-प्रसार सहयोग प्राप्त किया जा रहा है।

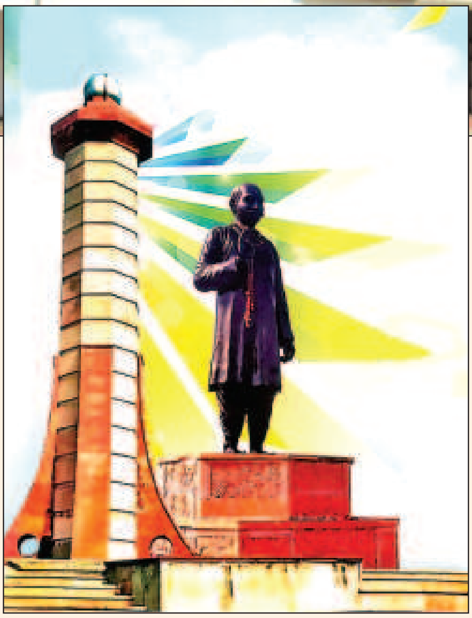

गोविन्द गुरू जनजाति विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा

जनजाति प्रतिभाओं के लिए हुआ असीमित अवसरों का सृजन

कल्पना डिण्डोर
सहायक निदेशक, जनसम्पर्क

बांसवाड़ा जिला मुख्यालय पर गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना से जनजाति क्षेत्र में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सपने साकार होने लगे हैं तथा यहां की जनजाति प्रतिभाओं को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नई शोध एवं पाठ्यक्रमों के माध्यम से शिक्षा की ऊंचाइयों को छूने की दिशा में असीमित अवसरों का सृजन होने लगा है। यहां के गरीब एवं वंचित वर्ग की प्रतिभाएं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नई उपलब्धियां अर्जित करने की ओर अग्रसर हैं। विश्वविद्यालय की स्थापना एवं जनजाति वर्ग की प्रतिभाओं को अब जिला मुख्यालय पर भी पीएचडी के अवसर सुलभ होने लगे है वहीं विश्वविद्यालय द्वारा शुरू किए गए नवीन पाठ्यक्रमों से भी प्रतिभाएं लाभान्वित हो रही हैं। आदिवासियों की शहादत के प्रेरक गोविन्द गुरु के नाम से स्थापित गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, बाँसवाड़ा इस क्षेत्र के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। विश्वविद्यालय अपने वर्तमान स्वरूप में जनजाति अंचल के युवाओं में नई आशा, उम्मीद और चेतना का संचार कर रहा है। गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय क्षेत्र के 156 सम्बद्ध महाविद्यालयों के माध्यम से लगभग सवा लाख से भी अधिक विद्यार्थियों में उच्च शिक्षा की अलख जगा रहा है। जनजाति क्षेत्र का यह विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा में नये आयाम स्थापित करेगा।

नये पाठ्यक्रमों की सौगात

विश्वविद्यालय कैम्पस में विभिन्न विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम, जनजाति कला एवं संस्कृति, संस्कृत शिक्षण, योग, कर्मकाण्ड, ज्योतिष, वास्तुशास्त्र आदि पाठ्यक्रम संचालित किये जा रहे है। साथ ही वेद-विद्यापीठ के तहत आचार्य, वैदिक साहित्य, ज्योतिर्विज्ञान, योग एवं त्रिवर्षीय शास्त्री पाठ्यक्रम भी संचालित है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने बजट 2022-23 में वैदिक गुरुकुल की स्थापना किये जाने की घोषणा की है।

गांवों तक पहुची कॉलेज शिक्षा की राह

विश्वविद्यालय से बांसवाड़ा, डूंगरपुर एवं प्रतापगढ़ जिलों के 156 राजकीय एवं निजी महाविद्यालय सम्बद्ध है। बांसवाड़ा जिले में स्नातक में 35,705 एवं स्नातकोत्तर में 11,947 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। प्रतापगढ़ में स्नातक में 16,468 एवं स्नातकोत्तर में 3,385 विद्यार्थी एवं डूंगरपुर में स्नातक में 31,835 एवं स्नातकोत्तर में 5,149 विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं। गांव- गांव में उच्च शिक्षा के लिए राह खुली है। जनजाति बालक-बालिकाओं का भविष्य संवरने लगा है।

रोजगारपरक लघु अवधि कौशल प्रशिक्षणों से विभिन्न ट्रेड्स में प्रशिक्षित किया जा रहा है युवाओं को

"जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा अनुसूचित क्षेत्र एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र के बेरोजगार जनजाति युवक-युवतियो को जीविकोपार्जन हेतु कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत रोजगारपरक लघु अवधि कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम विभिन्न राजकीय व केन्द्रीय संस्थानों के माध्यम से आयोजित कर (आवासीय एवं गैर आवासीय) विभिन्न ट्रेड्स में प्रशिक्षित किया जा रहा है। राजस्थान कौशल विकास एवं आजीविका निगम जयपुर, एम.एस.एम.ई. भिवाड़ी, सीपेट एवं आर.के.सी.एल. के माध्यम से कौशल विकास प्रशिक्षण दिलवाकर रोजगार या स्वरोजगार से जोड़ा जा रहा है।"

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री अर्जुन सिंह बामनिया से जनसम्पर्क अधिकारी राजेश यादव द्वारा किए गए साक्षात्कार के महत्त्वपूर्ण अंश...

जनजाति क्षेत्र का विकास राज्य सरकार की प्राथमिकता में है। इस दिशा में क्या नए कदम उठाए जा रहे हैं?

प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में निवास कर रहे जनजातीय लोगों के सर्वांगीण विकास को प्राथमिकता देकर राज्य सरकार प्रतिबद्धता से काम कर रही है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने पिछले साढ़े तीन वर्षों में जनजातीय क्षेत्र की अलग-अलग आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित कर उन्हें कई महत्त्वपूर्ण सौगातें दी हैं। इसमें विभिन्न योजनाओं के साथ-साथ जनजातीय भागीदारी योजना, सामुदायिक वनाधिकार विकास योजना और उदयपुर में हॉकी एकेडमी की शुरुआत शामिल हैं।

राजधानी जयपुर में 18 करोड़ की लागत से जनजाति भवन का निर्माण किया गया, जिसमें प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में रह रही अलग-अलग जनजातियों के रहन-सहन, खान-पान व संस्कृति में समन्वय हेतु विभिन्न जनजातियों के युवा वर्ग एक साथ एक ही छत के नीचे अपनी-अपनी संस्कृति और अपनी-अपनी सामाजिक विचारधारा के साथ विकास की मुख्यधारा से जुड़कर कार्य कर सकेंगे।

जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिये क्या कार्य किये जा रहे हैं?

गरीब प्रतिभाशाली जनजाति वर्ग के छात्र-छात्राओं के नियमित अध्ययन हेतु 46 आवासीय विद्यालय, 410 आश्रम छात्रावास व 9 कॉलेज छात्रावास संचालित किये जा रहे हैं। इसी प्रकार नीट व आई.आई.टी. प्रवेश परीक्षा एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाली छात्राओं हेतु कुल 6 बहुउद्देश्यीय छात्रावासों का संचालन किया जा रहा है। इस वर्ष विभाग द्वारा गैर अनुसूचित क्षेत्र के जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों हेतु 4 नवीन छात्रावास एवं जोधपुर मुख्यालय पर 1 नवीन आवासीय विद्यालय प्रारम्भ किया गया है।

विभाग द्वारा विद्यालय एवं कॉलेज स्तर के जनजाति वर्ग के नियमित अध्ययन हेतु क्या योजना संचालित है?

विभाग द्वारा विद्यालय व कॉलेज स्तर पर जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को नियमित अध्ययन हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष कॉलेज स्तर की जनजाति छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु 5000 रु. व स्कूल स्तर पर जनजाति छात्राओं को उच्च माध्यमिक शिक्षा हेतु 3500 रुपये एकमुश्त आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। इसी प्रकार बोर्ड एवं विश्वविद्यालय में प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण जनजाति प्रतिभावान छात्रों को 3500 रुपये की एकमुश्त छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। साथ ही जनजाति वर्ग की बालिकाओं को नियमित अध्ययन हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के तहत जनजाति वर्ग की छात्राओं को प्रतिवर्ष 6000 स्कूटियां दी जा रही हैं।

विभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति के समावेशी विकास हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

बजट वर्ष 2021-22 में अनुसूचित जनजाति के समावेशी विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा 100 करोड़ रुपये का जनजाति विकास कोष बनाया गया है। इस कोष के माध्यम से जनजाति क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका आदि क्षेत्रों में अतिरिक्त विकास कार्य स्वीकृत कर अंतराल की पूर्ति की गयी। वर्ष 2022-23 के बजट में उक्त कोष की राशि के 100 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 500 करोड़ किये जाने की घोषणा की गई। इस क्रम में राशि 500 करोड़ (200 करोड़ रुपये रोजगारोन्मुखी गतिविधियों एवं कृषि के लिए, 150 करोड़ रुपये शिक्षा एवं सामाजिक सुरक्षा के लिए तथा 150 करोड़ रुपये आधारभूत संरचना एवं जनसहभागिता) की गई है।

जनजाति बहुल बांसवाड़ा में गोविन्द गुरु जनजाति विश्वविद्यालय से क्या फायदा पहुंच रहा है?

बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर जिले के लगभग एक लाख दस हजार विद्यार्थियों को उच्च अध्ययन सुविधा उपलब्ध करा जनजाति संस्कृति, लोक कला एवं लोक जीवन पर शोध कार्य करने हेतु जनजाति शोध पीठ का गठन कर जनजाति छात्रों को अवसर प्रदान किया जा रहा है। विश्वविद्यालय द्वारा वैदिक विद्यापीठ की स्थापना कर वेद की सांख्यायन शाखा का संरक्षण एवं संवर्धन एवं छात्रों से संबंधित अकादमिक प्रमाण पत्रों को प्राप्त करने में सुविधा तथा उदयपुर आवागमन एवं अनावश्यक व्यय से राहत प्राप्त हो रही है।

युवाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा अनुसूचित क्षेत्र एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र के बेरोजगार जनजाति युवक-युवतियों को जीविकोपार्जन हेतु कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत रोजगारपरक लघु अवधि कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम विभिन्न राजकीय व केन्द्रीय संस्थानों के माध्यम से आयोजित कर (आवासीय एवं गैर आवासीय) विभिन्न ट्रेड्स में प्रशिक्षित किया जा रहा है। राजस्थान कौशल विकास एवं आजीविका निगम जयपुर, एम.एस.एम.ई. भिवाड़ी, सीपेट एवं आर.के.सी.एल. के माध्यम से कौशल विकास प्रशिक्षण दिलवाकर रोजगार या स्वरोजगार से जोड़ा जा रहा है।

लघु वन उपजों के मूल्य संवर्द्धन हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

जनजाति परिवारों को उनके द्वारा संग्रहित लघु वन उपजों का मूल्य संवर्द्धन कर मार्केटिंग के बेहतर अवसर सृजित करने हेतु वनधन विकास योजनान्तर्गत अब तक 479 वनधन विकास केन्द्रों का गठन किया जा चुका है, जिन्हें ट्राईफेड द्वारा स्वीकृति भी प्रदान की जा चुकी है। योजना के संचालन से प्रति वनधन विकास केन्द्र औसतन लगभग 300 सदस्यों सहित 8 जिलो में 1 लाख 44 हजार 803 सदस्य लाभान्वित होंगे।

जनजातीय कृषकों को उन्नत मक्का बीज से फसल उत्पादन बढ़ोतरी हेतु क्या कदम उठाये जा रहे है?

जनजातीय कृषकों को नि:शुल्क हाईब्रिड मक्का बीज मिनी किट वितरण कार्यक्रम खरीफ 2022 के अंतर्गत लगभग 8 लाख जनजातीय कृषकों को लाभान्वित किया गया। जनजातीय कृषकों को प्रति परिवार 5 किलोग्राम मिनी किट नि:शुल्क वितरित किये गये, जिससे इनके उत्पादन में काफी वृद्धि होने की संभावना है।

जनजाति क्षेत्र में जन सहयोग से सर्वांगीण विकास हेतु विभाग द्वारा क्या कदम उठाये गये?

राजस्थान में रहने वाले जनजाति समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए इनके उन्नयन हेतु नवीन जनजाति भागीदारी योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के तहत कार्य एवं गतिविधियों हेतु आवश्यक राशि का कम से कम 30 प्रतिशत की राशि जन सहयोग, स्वयं सेवी संस्थाओं, दानदाताओं या अन्य किसी सरकारी योजना, कार्यक्रम, फंड के तहत उपलब्ध कराए जाने पर शेष राशि इस योजना के माध्यम से उपलब्ध करवाई जा रही है।

वर्ष 2022-23 की राशि के विरुद्ध कुल 270 कार्य कुल लागत राशि रुपये 32.45 करोड़ जिसमें से टीएडी से देय राशि रुपये 22.73 करोड़ है, का अनुमोदन प्राप्त हुआ है। अनुमोदन पश्चात् कुल 229 कार्यो की कुल राशि रुपये 28.53 करोड़ (जिसमें से टीएडी से देय राशि रुपये 19.97 करोड़) की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गयी है।

बारां जिले के सहरिया क्षेत्र में जनजातीय विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाये गये?

बारां जिले के सहरिया क्षेत्र के छात्र-छात्राओं को अपनी उच्च शिक्षा पूर्ण करने हेतु प्रोत्साहित करने के साथ-साथ ही गुणात्मक शिक्षा हेतु खुशियारा, कोयला, कवाई एवं परानिया में सहरिया जनजाति हेतु संचालित 4 आवासीय विद्यालयों को माध्यमिक से उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत किया गया। जिससे चारों आवासीय विद्यालयों में प्रत्येक में 120-120 छात्र-छात्राओं की क्षमता वृद्धि की गई।

खेल सुविधाओं के विस्तार के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग में खेल सुविधाओं के लिए 5 जिलों में (बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, सिरोही तथा उदयपुर) 7 बालक तथा 6 बालिकाओं कुल 875 की क्षमता से पूर्व में 13 संचालित खेल छात्रावासों को राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के समकक्ष 13 प्रशिक्षण केन्द्रों में उच्च प्रशिक्षण कार्य एवं उच्च खेल सुविधाओं हेतु खेल अकादमियों में परिवर्तित किया गया।

जनजाति क्षेत्रों में खेल सुविधाओं का हो रहा विस्तार

"विभाग द्वारा बांसवाड़ा तथा प्रतापगढ़ में 6-6 करोड़ की लागत से मल्टीपरपज इण्डोर हॉल का निर्माण करवाया गया, साथ ही बांसवाड़ा में अन्तरराष्ट्रीय स्तर का 50 मीटर का तरणताल निर्माण एवं समस्त खेल अकादमियों में विभिन्न खेलों हेतु खेल मैदान कार्यकारी एजेन्सी कृषि विपणन द्वारा बनाये जा रहे हैं। बास्केटबॉल सिन्थेटिक कोर्ट का भी निर्माण कराया जा रहा है।"

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री आलोक गुप्ता से सहायक निदेशक सम्पत राम चान्दोलिया द्वारा की गई बातचीत के महत्त्वपूर्ण अंश...

जनजाति वर्ग के खिलाड़ियों को प्रशिक्षण की क्या व्यवस्था है ?

जनजाति वर्ग के उत्कर्ष खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने के क्रम में प्रदेश की पहली 40 बालक एवं 30 बालिकाओं की हॉकी अकादमी महाराणा प्रताप खेल गांव की हॉकी एस्ट्रोटर्फ पर प्रारम्भ की गई। ऑलम्पियन एवं अर्जुन अवार्डी श्री अशोक ध्यानचंद मुख्य हॉकी प्रशिक्षक द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ओलम्पियन एवं अर्जुन अवार्डी श्री धूलचंद डामोर द्वारा तीरंदाजी का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। समस्त खेल अकादमियों में विभाग द्वारा आवंटित खेलों के अनुसार खेल सामग्री भी उपलब्ध करवाई गई है।

खेल सुविधाओं के विकास हेतु कौनसे निर्माण कार्य करवाये गये ?

विभाग द्वारा बांसवाड़ा तथा प्रतापगढ़ में 6-6 करोड़ की लागत से मल्टीपरपज इण्डोर हॉल का निर्माण करवाया गया। साथ ही बांसवाड़ा में अन्तरराष्ट्रीय स्तर का 50 मीटर का तरणताल निर्माण एवं समस्त खेल अकादमियों में विभिन्न खेलों हेतु खेल मैदान कार्यकारी एजेन्सी कृषि विपणन द्वारा बनाये जा रहे हैं। इसके अन्तर्गत बास्केटबॉल सिन्थेटिक कोर्ट का भी निर्माण कराया जा रहा है।

खिलाड़ियों को दी जाने वाली सुविधाओं में क्या सुधार किये गये ?

खेल अकादमियों में निवास कर रहे 875 बालक-बालिका खिलाड़ियों को आवास, बिस्तर, अध्ययन, स्टेशनरी समस्त सुविधाएं साथ ही खाद्य सामग्री हेतु प्रति माह राशि रुपये 2400 दिये जा रहे थे, उसमें 200 रुपये की बढ़ोतरी कर प्रति खिलाड़ी राशि 2600 रुपये प्रति माह की गई। विभाग द्वारा भारत सरकार से प्राप्त रुपये 5 करोड़ की राशि से आम्बापुरा बांसवाड़ा में सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स ऑफ स्पोर्ट्स को स्थापित करने के क्रम में एक फुटबॉल स्टेडियम एवं तीरंदाजी रेंज कर निर्माण किया जाने हेतु प्रस्ताव जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित किये गये हैं।

छोटे किसानों हेतु सिंचाई के लिए क्या कोई सहायता दी जा रही है ?

विभाग द्वारा वर्ष 2021-22 के दौरान बजट घोषणा संख्या 329 में यह प्रावधित किया गया कि उपयोजना क्षेत्र में सोलर ऊर्जा से कृषि हेतु जनजाति कृषकों को बिना किसी हिस्सा राशि के सोलर कनेक्शन उपलब्ध करवाया जायेगा। योजना क्रियान्वयन हेतु 45 हजार रुपये का अतिरिक्त अनुदान विशेष सहायता अन्तर्गत प्रावधित किया गया है व शेष कृषक हिस्सा राशि का भुगतान जनजाति कल्याण कोष के अन्तर्गत प्रावधित किया गया है।

कुसुम योजना के तहत क्या कार्य किए गए ?

विभाग द्वारा कुसुम योजना (कम्पोनेन्ट बी) के तहत वर्ष 2021-22 में 1750 पम्प स्थापित किये जाने थे जिनमें से 1750 पम्प हेतु राशि 1540 लाख हस्तांतरित की जा चुकी है व 1113 पम्प हेतु कार्यादेश दिये जा चुके हैं। इनके विरुद्ध 942 पम्प स्थापित किये जा चुके हैं, जिन पर अब तक कुल 715.41 लाख रुपये का व्यय हुआ है।

सिकल सेल एनीमिया समस्या का क्या प्रबंधन किया जा रहा है ?

विभाग द्वारा जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिये राज्य सरकार तत्पर है। जनजातीय क्षेत्र में सिकल सेल एनीमिया से निजात पाने हेतु विभाग द्वारा राष्ट्रीय असंचारी रोग कार्यान्वयन अनुसधान संस्थान, जोधपुर के साथ मिलकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिसके तहत उपयोजना क्षेत्र के समस्त जनजातीय आवासीय विद्यालय, आश्रम छात्रावासों एवं मां-बाड़ियों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की सिकल सेल हेतु स्क्रीनिंग की जायेगी एवं रोग प्रसार रोकने हेतु समुचित परामर्श की व्यवस्था की गई है। सिकल सेल एनीमिया रोग के प्रबन्धन हेतु उपयोजना क्षेत्र के 5 जिलों में बच्चों के जन्म लेते ही सिकल सेल स्क्रीनिंग के लिये आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जा रहा है।

आवासीय विद्यालयों का सुदृढ़ीकरण व नवाचार

सुभाष शर्मा
वरिष्ठ शिक्षा सलाहकार

बुद्धिसागर उपाध्याय
प्रभारी अधिकारी, शिक्षा

राज्य सरकार के निर्देशानुसार जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा संचालित एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, मॉडल पब्लिक रेजिडेंशियल स्कूल, जनजाति आवासीय विद्यालयों एवं आश्रम छात्रावासों के सुदृढ़ीकरण के लिए भौतिक सुविधाओं को विकसित करने एवं गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करने हेतु विभिन्न नवाचारों को अपनाया जा रहा है। इससे विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के साथ अकादमिक विकास भी परिलक्षित हो रहा है।

स्मार्ट साइंस लैब

आवासीय विद्यालयों में नवीनतम एवं उच्च गुणवत्ता वाली विज्ञान प्रयोगशालाएं विकसित की गई हैं। विज्ञान के प्रभावी शिक्षण एवं प्रायोगिक कार्य करवाने हेतु उक्त प्रयोगशालाओं में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान एवं सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुरूप समस्त प्रायोगिक उपकरण उपलब्ध कराये गये हैं। विभिन्न वैज्ञानिक सिद्धान्तों और अवधारणाओं को सिखाने को सुदृढ़ करने हेतु समस्त आवासीय विद्यालयों में भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला में आवश्यक समस्त उपकरण, शिक्षण सामग्री, फर्नीचर, मॉडल, विज्ञान किट एवं अन्य प्रायोगिक सामग्री उपलब्ध करवाई है।

विभागीय छात्रावास अधीक्षक कैडर

विभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं के शैक्षणिक उन्नयन हेतु विभिन्न प्रकार के छात्रावासों का संचालन किया जा रहा है। वर्तमान में इन छात्रावासों के संचालन हेतु अधीक्षक के स्वीकृत पदों पर शिक्षा विभाग के शिक्षकों की सेवाएं प्रतिनियुक्ति पर ली जाती हैं। प्रतिनियुक्ति प्रक्रिया में शिक्षा विभाग में भी अध्यापकों की कमी होने के कारण उनके द्वारा विभागीय आवश्यकता अनुसार अधीक्षक उपलब्ध कराने में काफी समय लग जाता है। जिससे छात्रावासों की व्यवस्था प्रभावित होती है। प्रतिनियुक्ति पर सेवाएं देने वाले शिक्षकों के वेतनमान के अनुसार अधिक राशि भुगतान का व्यय भार बचाने हेतु विभाग के स्तर पर अधीक्षकों का कैडर बनाया गया है। इसके अन्तर्गत राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा चयन प्रक्रिया के तहत नये अधीक्षक लगाये जायेंगे। इस हेतु सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की जा चुकी है। विभागीय अधीक्षक उपलब्ध होने से उनके स्थानांतरण एवं रिक्त पदों जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा तथा स्थायी व्यवस्था

सुनिश्चित हो सकेगी। नवीन व्यवस्था के सृजन से प्रतिवर्ष स्थापना लागत में 4 करोड़ रुपये की शुद्ध बचत संभव हो सकेगी। पदों के विभागीय कैडर में सृजन व समायोजन से कार्मिकों पर प्रभावी नियंत्रण संभव होगा व उनके कार्य सम्पादन की दक्षता प्रभावी रूप से प्रबोधित की जा सकेगी।

आवासीय विद्यालयों एवं आश्रम छात्रावासों में मरम्मत एवं रखरखाव

विभाग द्वारा संचालित एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, मॉडल पब्लिक रेजिडेंशियल स्कूल, आवासीय स्कूल एवं आश्रम छात्रावासों के पुराने भवनों में सामान्य रखरखाव एवं लघु मरम्मत के कार्य को अभियान रूप में पूर्ण कराने के लिए प्रत्येक विद्यालय एवं आश्रम छात्रावास को मांग एवं प्राथमिकता के आधार पर अधीक्षक एवं संस्था प्रधानों को अधिकार प्रदान किए गए। लघु मरम्मत एवं रखरखाव के कार्य प्राथमिकता से संपादित करवाने हेतु प्रति विद्यार्थी 2000 रुपये की ग्रांट स्वीकृत की गई। परिणामस्वरूप भवनों में खिड़कियों के कांच, विद्युत फिटिंग, नल फिटिंग कार्य, खिड़कियों के वायरनेट, पलंग, फर्नीचर मरम्मत, शौचालय एवं स्नानघर के रखरखाव के साथ-साथ जल निकास व्यवस्था के कार्य प्राथमिकता से करवाये गये।

विद्यालयों एवं छात्रावासों की रैंकिंग

विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों एवं छात्रावासों में भौतिक विकास एवं सुविधा सम्पन्न करने हेतु बोर्ड के परीक्षा के परिणाम, शिक्षकों की स्थिति, फर्नीचर की उपलब्धता, बिजली एवं पानी की समुचित व्यवस्था, प्रयोगशाला, वाचनालय एवं पुस्तकालय, कम्प्यूटर लैब के साथ-साथ आवास व्यवस्था, खेल मैदानों व खेल गतिविधियों के विभिन्न पैरामीटर के आधार पर रैंकिंग की गई तथा A B C D ग्रेड प्रदान किये गये। C व D ग्रेड वाले विद्यालय एवं आश्रम छात्रावासों को वित्तीय सहायता प्रदान कर ग्रेड सुधार किया गया है।

विद्यालयों एवं छात्रावासों में व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर सघन मॉनिटरिंग

विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों में व्यवस्थाओं के सुदृढ़ीकरण अंतर्गत स्टाफ की उपस्थिति, दैनिक शिक्षण कार्य, कक्षा-कक्ष में कालांशवार शिक्षण व्यवस्था, प्रयोगशालाओं एवं कम्प्यूटर लैब, वाचनालय एवं पुस्तकालय का उपयोग सुनिश्चित करने हेतु जीओ टेग्ड फोटो विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप में मंगवाकर राज्यस्तरीय टीम द्वारा मॉनिटरिंग की व्यवस्था की गई। छात्रावासों के संचालन व्यवस्था में सुधार लाने हेतु विद्यार्थियों की दैनिक गतिविधियों की पालना निर्धारित टाइम-टेबल के अनुसार करने हेतु जनजाति व गैर जनजाति क्षेत्र, खेल छात्रावास एवं माडा क्षेत्र के छात्रावासों में दैनिक गतिविधियों यथा प्रात:कालीन व्यायाम, नाश्ता, लंच, सायंकालीन चाय, फल वितरण, रात्रिकालीन भोजन एवं स्वाध्याय के फोटोग्राफ्स जीओ टेग्ड करवाकर मंगवाये जा रहे हैं।

विद्या संबल

विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में प्रतिनियुक्ति पर शैक्षणिक स्टाफ की सेवाएं ली जाती हैं। शिक्षकों के विभिन्न पदों पर चयन, पदस्थापन प्रक्रिया एवं कार्यग्रहण में होने वाली देरी से विद्यार्थियों की शैक्षिक व्यवस्थाएं एवं परिणाम प्रभावित नहीं हो इस हेतु वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित योग्यताधारी शिक्षकों की सेवाएं राजस्थान सरकार की विद्या संबल योजना के अंतर्गत विभाग द्वारा विद्यालयों एवं छात्रावासों में शैक्षिक गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये बहुआयामी कार्य योजना बनाई गई जिसके अन्तर्गत रिक्त पदों पर विद्या संबल योजना अन्तर्गत गेस्ट फेकल्टी द्वारा शिक्षण कार्य करवाया गया।

बहुउद्देश्यीय छात्रावासों का संचालन

जिला मुख्यालय उदयपुर में 200 व कोटा में 150 बालिकाओं की क्षमता का बहुउद्देश्यीय बालिका छात्रावास संचालित है, जिसमें मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के अन्तर्गत NEET व IIT-JEE प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने वाली छात्राओं को प्रवेश दिया जा कर नि:शुल्क आवास व भोजन की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय पर 100-100 बालिकाओं की क्षमता एवं बारां जिला मुख्यालय पर 50 बालिकाओं की क्षमता वाले बहुउद्देश्यीय छात्रावासों का संचालन किया जा रहा है। इन विभागीय बालिका बहुउद्देश्यीय छात्रावास में 50 प्रतिशत सीटें महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं हेतु तथा शेष 50 प्रतिशत सीटें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाली छात्राओं हेतु आरक्षित रखी गयी हैं। इनमें प्रवेशित छात्राओं को नि:शुल्क आवास व भोजन की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। वर्तमान में विभाग द्वारा 6 बहुउद्देश्यीय छात्रावासों का संचालन किया जा रहा है, जिनकी कुल छात्रा क्षमता 700 है। जिसमें छात्राओं को प्रवेश दिया जाकर लाभान्वित किया जा रहा है।

कॉलेज छात्रावासों का संचालन

कक्षा 12 तक विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के उपरांत अध्ययन में निरंतरता बनाये रखने के लिये महाविद्यालयों में अध्ययन करने हेतु महाविद्यालय स्थल पर नि:शुल्क आवासीय सुविधा उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से कॉलेज छात्रावासों का संचालन किया जा रहा है। आठ कॉलेज छात्रावासों का संचालन विभाग द्वारा किया जा रहा है। योजना अंतर्गत 425 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जा रहा है। इन छात्रावासों में निवासरत विद्यार्थियों को राज्य सरकार द्वारा नि:शुल्क आवास, अल्पाहार एवं भोजन की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।

नि:शुल्क स्कूटी वितरण योजना

जनजाति क्षेत्र की प्रतिभावान छात्राओं के अध्ययन में निरंतरता रखने हेतु प्रोत्साहन स्वरूप कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के तहत राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एवं केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अन्तर्गत राजकीय विद्यालयों एवं आरटीई के तहत निजी विद्यालयों में अध्ययनरत जनजाति वर्ग की छात्राओं को राज्य सरकार की गाइडलाइन अनुसार नि:शुल्क स्कूटियां वितरित की जा रही है। योजना का नोडल विभाग आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग है। उक्त योजना के तहत जनजाति क्षेत्रीय विभाग के अन्तर्गत राज्य की अनुसूचित जनजाति छात्राओं हेतु 6000 स्कूटियां वितरित की जा रही हैं, जिसमें 5000 स्कूटी सीनियर सैकण्डरी उत्तीर्ण छात्राओं एवं 1000 स्कूटी सैकण्डरी उत्तीर्ण छात्राओं के लिए आरक्षित की गयी है।

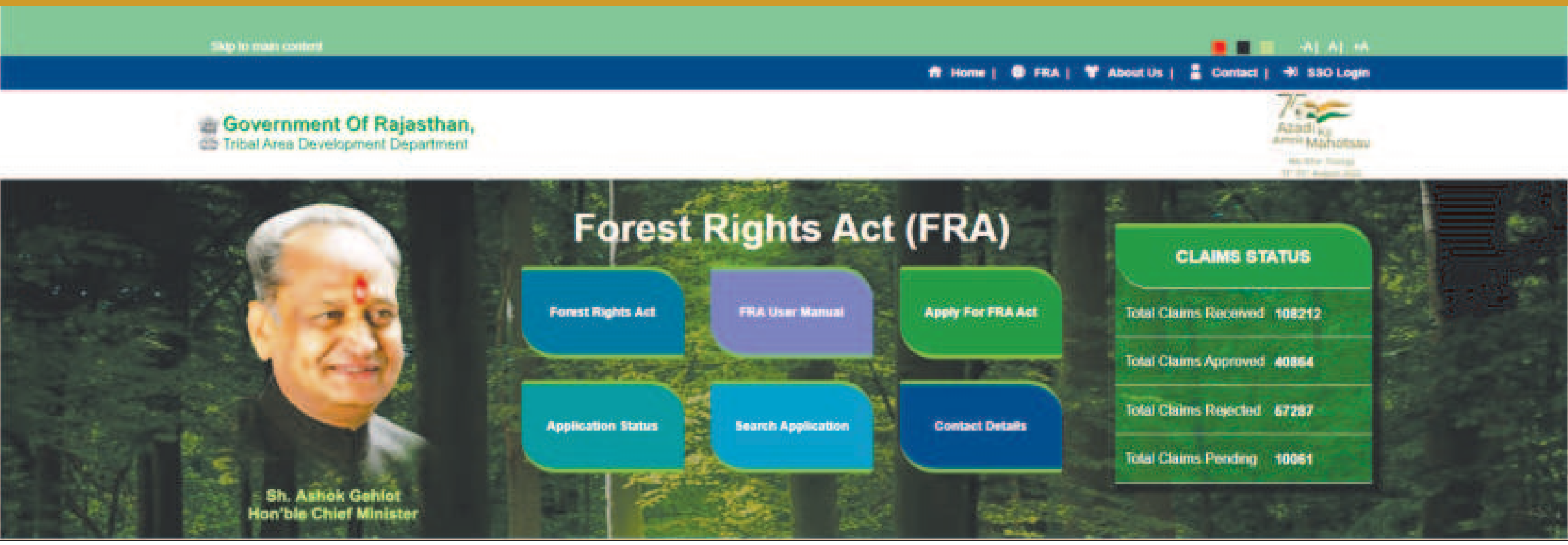

सूचना तकनीक से हो रहा जनजाति छात्रों का शैक्षणिक उन्नयन

गिरिराज कतीरिया
संयुक्त निदेशक (आई.टी.)

राज्य सरकार के निर्देशानुसार जनजाति उपयोजना क्षेत्र में विद्यार्थियों के शैक्षणिक उन्नयन के लिए आईटी का उपयोग किया जा रहा है और इसके सुखद परिणाम भी सामने आ रहे हैं।

मोबाइल एप से आंतरिक मूल्यांकन व्यवस्था

शैक्षणिक सत्र 2021-22 में विभाग द्वारा राज्य में संचालित समस्त आवासीय विद्यालयों एवं आश्रम छात्रावासों में Edu Tribe App के माध्यम से सतत मूल्यांकन प्रक्रिया लागू की गई है। इसके अन्तर्गत 3 टेस्ट सफलतापूर्वक आयोजित किये जा चुके हैं। छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों को प्रश्न पत्रों के साथ 3 छिद्रित OMR Sheet उपलब्ध कराई गई हैं। बहुविकल्प प्रश्नों को मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से OMR Sheet को स्केन करके त्वरित परिणामों से विद्यार्थियों को अवगत कराया जा रहा है। इस हेतु कक्षा 9 से 12 तक के 22,900 विद्यार्थियों के लिये 3 टेस्ट की प्रश्न पत्र बुकलेट तैयार की गई जिसमें 3 छिद्रित OMR Sheet जोड़कर विद्यार्थियों को दी गई। तीन आंतरिक मूल्यांकन परीक्षाओं का आयोजन किया गया। इस Edu Tribe App के उपयोग हेतु दो चरण में प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रथम चरण में Master Trainer Training तथा द्वितीय चरण में शिक्षकों एवं वार्डन को प्रशिक्षण दिया गया। इस एप के उपयोग से Real Time Monitoring कर उनके शैक्षणिक स्तर की पहचान एवं मूल्यांकन किया जाना संभव हुआ है। परिणामों का विश्लेषण राज्य स्तर पर कर पठन-पाठन के कमजोर क्षेत्रों को चिह्नित कर पुन: अध्यापन हेतु निर्देश प्रदान किये गये। साथ ही विद्यार्थियों के परिणामों को उनके अभिभावकों को SMS के माध्यम से अवगत कराया गया। परीक्षाओं में प्रश्नोत्तर को जांचने की प्रक्रिया के लिए मोबाइल एप का उपयोग किया जा रहा है।

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा

जनजाति क्षेत्रों में विषय अध्यापकों के पद रिक्त रहने के परिणामस्वरूप परीक्षा परिणाम प्रभावित होते हैं। अध्ययन-अध्यापन में शैक्षिक गुणवत्ता सुनिश्चित करने एवं ई-कन्टेन्ट लर्निंग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विभाग द्वारा जनजाति आश्रम छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों में Integrated Smart Classrooms की स्थापना की गई है। प्रथम चरण में चयनित 14 जिलों, जिनमें मुख्य रूप से अनुसूचित क्षेत्र के उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ जिले सम्मिलित हैं, में संचालित 123 आश्रम छात्रावासों व आवासीय विद्यालयों में इंटीग्रेटेड स्मार्ट क्लासरूम्स की स्थापना की गयी, जिससे 36 आवासीय विद्यालयों एवं 87 आश्रम छात्रावासों के लगभग 20 हजार विद्यार्थियों को शिक्षण करवाया जा रहा है। इसके माध्यम से किसी भी Location से Real Time संवाद किया जाना संभव हुआ है। शिक्षकों के Lectures को रिकॉर्ड कर छात्र-छात्राओं को पुन: दिखाया जा सकता है। विद्यार्थियों को अध्ययन में आने वाली समस्या का समाधान शिक्षकों द्वारा त्वरित रूप से किया जा रहा है।

HSMS पोर्टल से बेहतर प्रबंधन

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा संचालित समस्त जनजाति छात्रावासों, आवासीय विद्यालयों, खेल छात्रावासों एवं एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की प्रभावी मॉनिटरिंग हेतु HSMS पोर्टल लागू किया गया है। जिसमें विभिन्न मॉड्यूल्स के माध्यम से जनजाति छात्रावासों व आवासीय विद्यालयों का प्रबंधन किया जा रहा है।

इसी तरह विद्यार्थियों के आवेदन ऑनलाइन लिये जाकर मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जा रहा है। इससे प्रवेश प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ी है। छात्रावासों, विद्यालयों में भौतिक सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु पोर्टल का उपयोग किया जा रहा है। छात्रावास अधीक्षकों द्वारा आय-व्यय विवरण, खाद्य सामग्री व खेल सामग्री की मांग पोर्टल के माध्यम से की जाती है।

शैक्षणिक प्रोत्साहन योजनाओं का लाभ डीबीटी के माध्यम से

विभाग द्वारा जनजाति विद्यार्थियों हेतु संचालित 4 शैक्षणिक प्रोत्साहन योजनाओं यथा- बोर्ड एवं विश्वविद्यालय में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण जनजाति छात्रों को आर्थिक सहायता, महाविद्यालय स्तर की शिक्षा हेतु जनजाति छात्राओं को प्रोत्साहन राशि, कक्षा 11 एवं 12 में अध्ययनरत जनजाति छात्राओं को प्रोत्साहन राशि व जनजाति छात्रों को रिसर्च फैलोशिप का लाभ Scholarship Portal पर विद्यार्थियों के जनाधार लिंक बैंक खाते में DBT के माध्यम से किया जा रहा है।

साथ ही सहरिया छात्र-छात्राओं हेतु संचालित 7 महत्त्वपूर्ण व्यक्तिगत सहरिया योजनाओं यथा- कक्षा 11 से 12 में अध्ययनरत सहरिया छात्राओं को आर्थिक सहायता, सहरिया छात्र-छात्राओं का शैक्षणिक उत्प्रेरण (कक्षा 1 से 12), बोर्ड कक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण सहरिया छात्र/छात्राओं को प्रोत्साहन राशि, सहरिया प्रशिक्षणार्थियों को बीएड हेतु आर्थिक सहायता, सहरिया छात्राओं को नर्सिंग हेतु आर्थिक सहायता, सहरिया प्रशिक्षणार्थियों को बीएसटीसी हेतु आर्थिक सहायता व महाविद्यालय में सामान्य शिक्षा में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को आर्थिक सहायता का लाभ पोर्टल पर विद्यार्थियों के जनाधार लिंक बैंक खाते में DBT के माध्यम से किया जा रहा है। ऑनलाईन आवेदन प्राप्त करने से विगत 3 वर्षो में आवेदनों की संख्या में वृद्धि होने के साथ ही आवेदनों की मॉनिटरिंग भी बेहतर हुई है। जनजाति विद्यार्थियों को पोशाक एवं स्टेशनरी राशि का भुगतान DBT राशि का हस्तांतरण विद्यार्थियों के जनाधार से लिंक खाते में किया जा रहा है।

FRA MIS Portal द्वारा वनाधिकार अधिनियम का लाभ

उक्त के अतिरिक्त वनाधिकार अधिनियम अन्तर्गत प्राप्त वनाधिकार दावों के निस्तारण में पारदर्शिता लाने, वनाधिकार दावों की प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने एवं संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिये FRA MIS Portal विकसित कर प्रारम्भ किया गया है। इसके माध्यम से दावेदार स्वयं की सिटीजन आईडी., ई-मित्र एवं ग्राम पंचायत के माध्यम से वनाधिकार दावा ऑनलाइन प्रस्तुत कर आवेदन की वस्तुस्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। दावे की जांच से लेकर वनाधिकार पत्र जारी करने की सम्पूर्ण प्रक्रिया पोर्टल के माध्यम से सक्षम प्राधिकारी समिति द्वारा ऑनलाइन की जा रही है। जिसकी सूचना आवेदक एवं संबंधित अधिकारी SMS, E-mail के द्वारा प्रेषित की जाती है। जिला कलक्टर के Approval पश्चात् Generated को जिला कलक्टर, उप वन संरक्षक एवं उपायुक्त (टीएडी), मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जिला परिषद) द्वारा e-sign से प्रमाणित किया जाता है।

योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन हेतु इंटरनेट कनेक्टिविटी की सुविधा

विभाग द्वारा संचालित समस्त जनजाति आश्रम छात्रावासों, आवासीय विद्यालयों एवं खेल छात्रावासों की प्रभावी मॉनिटरिंग एवं योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन हेतु इंटरनेट कनेक्टिविटी की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इससे वर्तमान परिदृश्य के अनुसार डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा एवं जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को ई-लर्निंग की सुविधा उपलब्ध हो रही है। वहीं विद्यार्थियों एवं छात्रावासों की बेहतर मॉनिटरिंग भी की जा रही है। ●

जनजातीय जीवन

छाया: कल्पना डिंडोर, लक्ष्मण पारंगी

तीज उत्सव

श्रावणी तीज जयपुर में हर्ष और उल्लास के साथ मनाई गई। तीज माता की पारम्परिक सवारी जनानी ड्योढ़ी में पूजा अर्चना के बाद त्रिपोलिया गेट से लवाजमे के साथ निकाली गई। सांस्कृतिक छटा बिखेरते लोक कलाकारों ने राजस्थानी संस्कृति को साकार किया। कच्छी घोड़ी, कालबेलिया, बहुरूपिया, अलगोजा आदि पारम्परिक नृत्यों की मनमोहक प्रस्तुतियों के साथ गज सवार, तोप गाड़ी, सुसज्जित रथ, घोड़े और ऊंट भी उत्सव में शामिल हुए। बैंड वादकों ने मधुर स्वर लहरियां बिखेरी। तीज माता के दर्शनों के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। **छाया: राजेन्द्र शर्मा**

फोटो फीचर

76वां स्वतंत्रता दिवस

76वें स्वतंत्रता दिवस का राज्यस्तरीय समारोह जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया।

छाया: सूजस

जयपुर में देशभक्ति गीतों के सामूहिक गायन समारोह में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत

देशभक्ति गीतों के सामूहिक गायन का बना विश्व रिकॉर्ड

अरूण जोशी
अतिरिक्त निदेशक, जनसम्पर्क

राजस्थान में प्रदेश के सरकारी व निजी स्कूलों के 1 करोड़ बच्चों ने देशभक्ति गीतों का सामूहिक गान कर विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया। मुख्य समारोह मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की उपस्थिति में सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित हुआ। आजादी का अमृत महोत्सव के अन्तर्गत चल रहे कार्यक्रमों की श्रृंखला में शिक्षा विभाग तथा कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश के सभी स्कूलों के विद्यार्थियों ने भाग लेकर देशभक्ति गीतों का सामूहिक गान किया।

आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे अमृत महोत्सव के तहत राज्य, जिला, ब्लॉक व विद्यालय स्तर पर शिक्षा विभाग व कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेशभर से 1 करोड़ बच्चों ने एक साथ देशभक्ति गीतों का गायन किया। बच्चों ने झण्डा ऊंचा रहे हमारा, सारे जहां से अच्छा, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, हम होंगे कामयाब जैसे देशभक्ति से ओत-प्रोत गीतों के साथ राष्ट्रीय गीत 'वन्दे मातरम' व राष्ट्रगान 'जन गण मन' का भी गायन किया। इस अवसर पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के उपाध्यक्ष श्री प्रथम भल्ला ने मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत को विश्व रिकॉर्ड का प्रोविजनल सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया, जिसे मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों व समस्त प्रदेशवासियों को समर्पित किया।

कार्यक्रम से प्रदेश में तैयार होगा नया वातावरण

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने शिक्षा विभाग को बधाई दी। एक करोड़ से अधिक बच्चों द्वारा देशभक्ति गीतों के सामूहिक गायन से प्रदेश में एक नया वातावरण तैयार हुआ है। इन तरानों में संविधान की रक्षा, आपसी भाईचारे व देश की आजादी में दिए गए बलिदानों सहित तमाम भावनाएं समाहित हैं। आज भारत में तीन चौथाई आबादी नौजवानों की है। नई पीढ़ी को इन गीतों के माध्यम से देशभक्ति की भावनाओं को आत्मसात करने का मौका मिलेगा। इससे प्रदेश के युवाओं में देश की आजादी के लिए महात्मा गांधी के सान्निध्य में पं. जवाहर लाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे नेताओं द्वारा किए गए स्वतंत्रता आंदोलनों, भगतसिंह, चन्द्रशेखर आजाद जैसे नौजवानों द्वारा दिए गए बलिदानों के प्रति श्रद्धा, डॉ. भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित संविधान की रक्षा व साम्प्रदायिक सौहार्द की भावना मजबूत होगी। पं. जवाहर लाल नेहरू द्वारा 31 दिसंबर, 1929 को देश का राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। आजादी की 75वीं वर्षगाठ पर घर पर

- **एक करोड़ बच्चों ने एक साथ देशभक्ति गीत गाकर बनाया विश्व रिकॉर्ड**
- **कार्यक्रम से जन-जन तक पहुंचा देशभक्ति, भाईचारे और तरक्की का संदेश**
- **स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान व संघर्षों से हासिल हुई आजादी**
- **75 वर्षों में देश ने हर क्षेत्र में हासिल की शानदार उपलब्धियां**
- **शिक्षा एवं स्वास्थ्य में राजस्थान बन रहा मॉडल स्टेट**

सामूहिक गायन में विश्व रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र लेते हुए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत

तिरंगा फहराकर लोगों ने राष्ट्रभक्ति के संकल्प को मजबूत किया। प्रदेशवासियों ने अपने घरों पर तिरंगा फहराकर दुनिया को संदेश दिया कि हिंदुस्तान में राष्ट्रभक्ति का अनूठा जज्बा है।

75 वर्षों में देश ने हासिल की शानदार उपलब्धियां

गत 75 वर्षों में देश ने अभूतपूर्व तरक्की की है। जहां आजादी के समय देश में सुई का भी उत्पादन नहीं हो रहा था वहां आज विश्वभर में भारतीय उत्पादों का निर्यात हो रहा है। आईआईटी, आईआईएम, एम्स जैसे संस्थानों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं से लेकर विज्ञान और तकनीकी शिक्षा में देश ने शानदार तरक्की की है। बड़े-बड़े बांधों के निर्माण से किसानों को सिंचाई जल मिला है और उनका जीवन स्तर सुधरा है। गत 75 वर्षों में देश में लोकतंत्र की जड़ें लगातार गहरी हुई हैं। पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने प्राणों का बलिदान देकर विघटनकारी शक्तियों से देश की अखण्डता की रक्षा की। आजादी के 75वें वर्ष में राजस्थान शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में मॉडल स्टेट बनकर उभरा है। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के माध्यम से गरीब विद्यार्थियों को निःशुल्क अंग्रेजी शिक्षा दी जा रही है। वहीं चिरंजीवी योजना से आम जनता को मंहगे से मंहगा इलाज निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है।

शांति और भाईचारे से ही विकास संभव

शांति व भाईचारे के माहौल में ही प्रदेश का समुचित विकास संभव है। नेहरु, गांधी, पटेल व मौलाना आजाद जैसे स्वतंत्रता

देशभक्ति गीतों के सामूहिक गायन में शामिल छात्र-छात्राएं

सेनानियों के नेतृत्व में देश ने अंग्रेजों से लड़कर स्वतंत्रता हासिल की है। एकजुटता, शान्ति, पारदर्शिता व विकासशीलता से ही देश की प्रगति का मार्ग प्रशस्त होगा। प्रदेशवासियों को आपसी प्रेम तथा भाईचारे को मजबूत करने का आह्वान किया। शांति व भाईचारे के अभाव में विकास ठप हो जाता है। देश में सभी जाति, धर्म व अलग-अलग भाषाएं बोलने वाले लोग एकजुट होकर देश के तिरंगे झण्डे को मान-सम्मान के साथ फहराते रहे।

सामूहिक गायन कार्यक्रम उपरांत मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत एसएमएस स्टेडियम में उपस्थित बच्चों के बीच जाकर उनसे मिले तथा उनकी हौसला अफजाई की।

राष्ट्र आमजन की आस्था का सबसे बड़ा केन्द्र है। स्वतंत्रता सेनानियों के कड़े संघर्ष से देश को अंग्रेजों, राजशाही व जागीरदारों से आजादी मिली। देश के प्रथम प्रधानमंत्री व स्वतंत्रता सेनानी पंडित जवाहरलाल नेहरु की उनके समेत तीन पीढ़ियां स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी तथा आनंद भवन व स्वराज्य भवन जैसी इमारतें देश को समर्पित कर दी।

तिरंगा देश की आन, बान व शान है। देशभक्ति गीत के इस सामूहिक गायन से नई पीढ़ी को आजादी के संघर्षों से रूबरू करवाया गया है।

उच्च न्यायालय जोधपुर परिसर में बनेगा बार काउंसिल ऑफ राजस्थान का नवीन भवन

- 14.37 करोड़ रुपये की लागत से बनेगा बार काउंसिल भवन
- 500 व्यक्तियों की क्षमता वाले ऑडिटोरियम का होगा निर्माण
- 4 मंजिला इमारत में होंगे मीटिंग हॉल, लाइब्रेरी, चेम्बर व अन्य सुविधाएं

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने जोधपुर स्थित राजस्थान उच्च न्यायालय के परिसर में बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के नवीन भवन, निर्माण के लिए 14.37 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

मुख्यमंत्री की इस मंजूरी से बार काउंसिल के नवीन भवन के भूतल पर 500 व्यक्तियों की क्षमता वाला ऑडिटोरियम, स्ट्रॉन्ग रूम, विद्युत कक्ष व स्टाफ रूम आदि का निर्माण तथा भूतल पर बार काउंसिल के सचिव व पदाधिकारियों के कक्ष व अन्य सुविधाएं विकसित की जाएंगी।

इसके प्रथम व द्वितीय तल पर काउंसिल के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन के कक्ष, मीटिंग हॉल, लाइब्रेरी, ड्राइवर डोरमेटरी, मल्टीपरपज़ हॉल तथा ऑफिस आदि का निर्माण कराया जाएगा। इस भवन का निर्माण राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम (आरएसआरडीसी) द्वारा किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2022-23 के बजट में इस संबंध में 8.53 करोड़ रुपये के वित्तीय प्रावधान की घोषणा की गई थी। ऑडिटोरियम एवं निर्माण क्षेत्र में बढ़ोतरी होने के कारण सुविधाओं का विस्तार करते हुए श्री गहलोत ने 14.37 करोड़ रुपये की संशोधित राशि के लिए स्वीकृति प्रदान की है।

जामडोली के पुनर्वास गृह में बनेगा 125 आवासीय क्षमता का भवन

- 7.85 करोड़ रुपये की लागत से होगा भवन निर्माण

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने जयपुर के जामडोली में स्थित मानसिक विमन्दित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह का विस्तार करते हुए 125 आवासीय क्षमता का नवीन भवन बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस नवीन भवन के निर्माण के लिए 7.85 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति भी श्री गहलोत द्वारा दी गई है।

मुख्यमंत्री की मंजूरी से प्रस्तावित भवन में भूतल पर 16 बालकों की 5 तथा 12 बालकों की 4 इकाइयों का निर्माण किया जाएगा जिसमें केयर टेकर व आवश्यक सुविधाओं सहित 24 घण्टे चिकित्सकीय सुविधा एवं नर्सिंग केयर का प्रावधान होगा। इस भवन में बालकों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु खेलकूद की सुविधा के लिए उचित आकार के 4 हवादार प्रांगण भी होंगे। भवन के प्रथम तल पर प्रशासकीय कक्ष तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा। इस भवन का निर्माण विमंदित व्यक्तियों के नेशनल ट्रस्ट द्वारा अनुशंसित नियमावली को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। इस भवन में एक बड़ा डायनिंग हॉल मय रसोई, स्टोर तथा ऑक्यूपेशनल थैरेपी हेतु कक्ष भी होगा।

18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जंबूरी के पोस्टर का विमोचन करते हुए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत

उल्लेखनीय है कि वर्तमान में 250 क्षमता का एक पुनर्वास गृह जामडोली में संचालित है जिसमें लगभग 340 आवासी गृह सुविधा से लाभान्वित हो रहे हैं। लेकिन इस पुनर्वास गृह में अन्य संस्थाओं से भी आवासियों का स्थानान्तरण किए जाने के कारण प्रवेश का दवाब बना रहता है। इस आवश्यकता को देखते हुए मुख्यमंत्री द्वारा विमंदित जन के हित में 125 आवासीय क्षमता के एक नए भवन के निर्माण का संवेदनशील निर्णय लिया गया है।

18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जंबूरी

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जंबूरी के पोस्टर का विमोचन किया। श्री गहलोत को राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड के पदाधिकारियों ने आयोजन की तैयारियों से अवगत कराया। राष्ट्रीय जंबूरी 4 से 10 जनवरी 2023 तक पाली जिले के रोहट में आयोजित होगी। राजस्थान को 66 साल बाद पुनः राष्ट्रीय जंबूरी की मेजबानी मिली है। इस अवसर पर राज्य मुख्य आयुक्त श्री निरंजन आर्य, राज्य आयुक्त (रोवर) श्री निर्मल पंवार, राज्य आयुक्त (शांति एवं अहिंसा) श्री मनीष शर्मा एवं राज्य सचिव डॉ. पी.सी. जैन सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने बजट 2022-23 में जंबूरी के आयोजन के लिए 25 करोड़ रुपये की घोषणा की थी। इस 7 दिवसीय जंबूरी में स्टेट द्वार, पायोनियरिंग प्रोजेक्ट, एडवेंचर वैली, ग्लोबल विलेज डवलपमेंट, इंटीग्रेशन गेम्स, मार्च पास्ट, कलर पार्टी, लोक नृत्य, शारीरिक प्रदर्शन, राज्य दिवस प्रदर्शनी, बैंड प्रदर्शन, रॉक क्लाइंबिंग, पैरासेलिंग एवं वाटर एक्टिविटीज़ जैसी कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। इस जंबूरी में 1500 विदेशी सहभागियों सहित लगभग 35 हजार स्काउट व गाइड शामिल होंगे।

इंदिरा रसोई के जरिए भोजन की व्यवस्था

जलभराव से प्रभावित क्षेत्रों के लोगों के लिए इन्दिरा रसोई के जरिए भोजन पैकेट्स की व्यवस्था की जा रही है। अतिवृष्टि के मद्देनजर संभाग मुख्यालय पर जिला कलक्ट्रेट एवं नगर निगम स्तर पर एक-एक नियंत्रण कक्ष 24 घंटे संचालित हैं। जोधपुर जिला प्रशासन एवं विभिन्न विभागों की संभावित बाढ़ नियंत्रण कार्ययोजना के अंतर्गत एहतियात के तौर पर एसडीआरएफ भी तैनात है। असुरक्षित मकानों में रहने वालों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाकर जरूरी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं।

सहायता राशि के लिए जिला प्रशासन को निर्देश

मुख्यमंत्री ने जोधपुर की बावड़ी तहसील में जलभराव में डूबने से चार बच्चों की मृत्यु पर दुःख जताया। उन्होंने मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत मृतक बच्चों के परिजनों को 5 लाख रुपये प्रति परिवार और घायल एक बच्चे के परिजनों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से 20 हजार रुपये सहायता राशि दिलाने के लिए जिला प्रशासन को निर्देश दिए।

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम-2017 के विभिन्न नियमों में संशोधन

- निश्चित प्रीमियम के भुगतान पर मार्च, 2040 तक बढ़ सकेगी खनन पट्टों की अवधि
- खनन पट्टा हस्तान्तरण पर देय प्रीमियम अब हुआ आधा
- खातेदारी भूमि में खनन पट्टों के लिए 4 हेक्टेयर की अधिकतम सीमा खत्म
- खनन पट्टों के लिए मासिक के स्थान पर त्रैमासिक ऑनलाइन रिटर्न

हाड़ौती में बह रही विकास की गंगा

- 974 करोड़ रुपये की चम्बल पेयजल परियोजना से हिण्डोली-नैनवां की जनता को होगा लाभ
- जिले को मिली नर्सिंग कॉलेज, कृषि महाविद्यालय, आईटीआई व 3 प्रमुख सड़कों सहित कई सौगात
- प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में दो वर्ष की छूट की घोषणा
- केदारनाथ त्रासदी के पीड़ितों के पात्र परिजनों को पुनः अनुकंपा नियुक्ति
- अगला बजट युवाओं और छात्रों को होगा समर्पित

राज्य सरकार आमजन को सभी क्षेत्रों में सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। इसी क्रम में हाड़ौती के सर्वांगीण विकास के लिए घोषित परियोजनाओं से क्षेत्र में विकास की गंगा बह रही है। राज्य सरकार ने कोरोना के दौरान भी विकास की गति को रुकने नहीं दिया। शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी, सिंचाई, सड़क, नगरीय विकास व खेलकूद विकास के साथ समाज के सभी कमजोर तबकों को पेंशन, कर्मचारी वर्ग के लिए पुरानी पेंशन योजना जैसे अनेकों जन कल्याणकारी फैसले लिए गए।

बूंदी जिले के हिण्डोली में लगभग 1132.83 करोड़ के विकास कार्यों के शिलान्यास समारोह में 974 करोड़ रुपये लागत की हिण्डोली-नैनवां चम्बल पेयजल परियोजना, 21 करोड़ लागत के नर्सिंग कॉलेज, 10.50 करोड़ की लागत के आईटीआई, 6.50 करोड़ की लागत के कृषि महाविद्यालय व 4.50 करोड़ की लागत के राजकीय महाविद्यालय का शिलान्यास किया। वहीं 117 करोड़ की तीन प्रमुख सड़कों का भी मुख्यमंत्री ने शिलान्यास किया।

हिण्डोली-नैनवां चम्बल पेयजल परियोजना से हिंडोली के 185 गांव और 198 ढाणियां तथा नैनवां शहर में 101 गांव और 89 ढाणियों को पेयजल उपलब्ध होगा। परियोजना के तहत 7 स्वच्छ जलाशय और पम्प हाउस, 70 उच्च जलाशय मुख्य स्वच्छ जल की करीब 575 किलोमीटर पाइप लाइन और मुख्य वितरण की करीब 742 किलोमीटर पाइप लाइन बिछाई जाएगी और 82 हजार से अधिक घरेलू कनेक्शन दिए जा सकेंगे।

बूंदी में समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। संशोधनों से खनिजों का वैज्ञानिक एवं पर्यावरण-अनुकूल तरीके से समुचित खनन हो सकेगा तथा प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी।

प्रस्ताव के अनुसार, राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम-2017 के विभिन्न नियमों में बदलाव किया गया है। संशोधित नियमों के अनुसार, अप्रधान खनिजों के खनन पट्टों व लाइसेन्सों की अवधि निश्चित प्रीमियम के भुगतान की शर्त पर 31 मार्च, 2025 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2040 तक हो सकेगी।

संशोधित नियमावली में अप्रधान खनिजों के खनन पट्टों के हस्तान्तरण पर लिये जाने वाला प्रीमियम अब डेड रेन्ट एवं लाइसेन्स फीस के 10 गुना व अधिकतम 10 लाख रुपये के स्थान पर 5 गुना व अधिकतम 5 लाख रुपये तक लिया जाएगा तथा पट्टाधारियों को अप्रधान खनिजों के खनन पट्टों के लिए मासिक की जगह त्रैमासिक ऑनलाइन रिटर्न भरना होगा।

नए नियमों में खातेदारी भूमि में अप्रधान खनिज खनन पट्टा जारी करने की 4 हैक्टेयर की अधिकतम सीमा को भी हटाया जा सकेगा ताकि वैज्ञानिक और सुरक्षित खनन को बढ़ावा मिल सके। साथ ही, निर्धारित प्रीमियम के भुगतान पर अप्रधान खनिज के खनन पट्टों व लाइसेन्स के समीप उपलब्ध भूमि एक निश्चित क्षेत्रफल तक खनन पट्टा व लाइसेन्सधारी को आवंटित की जा सकेगी। सुगमता की दृष्टि से नवीन प्रावधान के अनुसार खानों का पंजीयन बिना पर्यावरण अनुमति के हो सकेगा, लेकिन खनन कार्य पर्यावरण अनुमति प्राप्त करने के बाद ही शुरू होगा।

ई.आर.सी.पी. राज्य की जरूरत

राज्य के 13 जिलों में सिंचाई व पेयजल जलापूर्ति के लिए ई.आर.सी.पी बेहद महत्त्वपूर्ण है।

केदारनाथ त्रासदी के पीड़ितों के परिजनों को पुनः अनुकंपा नियुक्ति

वर्ष 2013 की केदारनाथ त्रासदी में जान गंवाने वाले एवं स्थायी रूप से लापता हुए राजस्थान के निवासियों के परिजनों को सम्बल देने के लिए केदारनाथ त्रासदी के पीड़ितों के पात्र परिजन को अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी।

अभ्यर्थियों को आयु सीमा में दो वर्ष की छूट

कोविड के कारण दो वर्षों तक नौकरी के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं समय पर आयोजित नहीं हो सकी। इसलिए आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में से वंचित अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में दो वर्षों की छूट दी जाएगी। सरकार की विभिन्न योजनाओं के केन्द्र में युवा और छात्र हैं। प्रदेश का अगला बजट भी इन्हीं को समर्पित होगा। सरकार शहरों में भी सौ दिन का रोजगार देने का कार्य कर रही है।

29 अगस्त से शुरू होंगे ग्रामीण ओलंपिक खेल

ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन 29 अगस्त, 2022 से

शुरू होने जा रहे हैं। जिसमें 30 लाख खिलाड़ी भाग लेंगे। इसमें गांवों की खेल प्रतिभाओं को खेलने का मौका मिलेगा और उन्हें खेल जगत में अपना भविष्य बनाने के नए अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। ग्रामीण ओलंपिक पूरे देश में खेलों का एक नया माहौल तैयार होगा।

राजस्थान बन रहा एजुकेशन हब

बूंदी में नए मेडिकल कॉलेज के लिए 63 बीघा जमीन आवंटन के साथ 147 करोड़ से अधिक की राशि मंजूर की जा चुकी है। वहीं हिण्डोली कॉलेज के लिए 15 एकड़ भूमि के साथ 4.50 करोड़ का बजट उपलब्ध कराया गया है। राज्य सरकार शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। जहां 1998 में प्रदेश में मात्र 6 विश्वविद्यालय थे आज बढ़कर 28 हो गए हैं। सरकार द्वारा 210 नए राजकीय महाविद्यालय खोले गए हैं, जिनमें 96 कन्या महाविद्यालय शामिल हैं। वहीं 675 नए निजी महाविद्यालयों के लिए एनओसी जारी की गई है। हर जिले में सरकारी नर्सिंग कॉलेज तथा हर संभाग में पब्लिक हेल्थ कॉलेज खोले जा रहे हैं। होनहार बच्चों को राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के तहत पढ़ाई के लिए विदेश भेजा जा रहा है। दिव्यांग विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के तहत 10 हजार रुपये की छात्रवृत्ति दी जा रही है।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में राजस्थान बन रहा अग्रणी

स्वास्थ्य सेवाओं और मेडिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर में राजस्थान एक अग्रणी राज्य बनता जा रहा है। आज पूरे देश में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की चर्चा हो रही है। इस योजना में प्रति परिवार 10 लाख तक के सालाना बीमे का प्रावधान है। इसमें कॉकलियर इम्पलांट, बोन कैंसर जैसी महंगी बीमारियों के भी निःशुल्क इलाज की व्यवस्था की गई है। इसमें ट्रांसप्लांट में 10 लाख रुपये की सीमा लागू नहीं होती है। ट्रांसप्लांट का सारा खर्चा सरकार द्वारा वहन किया जाता है। अब तक 18 लाख से अधिक मरीजों को 2202 करोड़ रुपये की कैशलेस सुविधा दी गई है। एसएमएस अस्पताल में आईपीडी टॉवर तथा हृदय रोग संस्थान का कार्य तेजी से किया जा रहा है।

राज्य सरकार ने 1.35 करोड़ महिलाओं को घर का मुखिया बनाने का कार्य किया है। अब इन्हें निःशुल्क स्मार्ट फोन वितरित किए जाएंगे। इनमें 3 साल के लिए इंटरनेट की सुविधा भी मुफ्त रहेगी। राज्य में पहली बार अलग से कृषि बजट पेश किया गया। किसान मित्र ऊर्जा योजना से लाखों किसानों के बिजली बिल शून्य हो गए हैं।

राज्य सरकार संविधान के प्रति समर्पित

किसी भी क्षेत्र का जनप्रतिनिधि यदि जागरूक होता है, तो क्षेत्र का विकास होने से कोई नहीं रोक सकता। विकास कार्यों का शिलान्यास इस बात को चरितार्थ करता है। राज्य सरकार संवैधानिक दायित्वों के साथ प्रदेश के चहुंमुखी विकास को लेकर प्रतिबद्ध है। जन समस्याओं का निराकरण संसदीय लोकतंत्र का अभिन्न अंग है और प्रदेश सरकार इसके प्रति समर्पित है।

आमजन को मिल रही राहत

चम्बल पेयजल परियोजना से हिण्डोली-नैनवां क्षेत्र में पेयजल समस्या का स्थाई समाधान सुनिश्चित हो गया है। प्रदेश की विषम परिस्थितियों के बावजूद राज्य सरकार जल जीवन मिशन के कार्यों को पूर्ण करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है।

राज्य सरकार की महत्त्वाकांक्षी चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से प्रदेश के हर गरीब को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं। राज्य सरकार कृषि, चिकित्सा, स्वास्थ्य और सड़क विकास के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य कर रही है। इन कार्यों से आमजन को राहत मिल रही है।

विकास कार्यों से बदलेगी क्षेत्र की तस्वीर

हिण्डोली-नैनवां विधानसभा क्षेत्र में 1133 करोड़ के कार्यों की एक साथ सौगात से इलाके में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कों और पेयजल की तस्वीर बदल जाएगी। लोगों को पानी लाने के लिए दूर-दूर तक जाना पड़ता था, लेकिन अब चंबल नदी का पानी लोगों के घरों तक पहुंचेगा। इससे इलाके में पेयजल की समस्या का स्थाई समाधान हो सकेगा। नर्सिंग, एग्रीकल्चर और आईटीआई सहित चार कॉलेज खुलने से शिक्षा की अलख जगेगी। इससे हिण्डोली-नैनवां हाड़ौती क्षेत्र में शिक्षा के हब के रूप में उभरेगा। तीन बड़ी सड़कें बनने से लोगों को आवाजाही में आसानी होने के साथ क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी।

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। संशोधनों से खनिजों का वैज्ञानिक एवं पर्यावरण-अनुकूल तरीके से समुचित खनन हो सकेगा तथा प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी।

वंशावली लेखन भारत की महान परम्परा

- वंशावलियों के संरक्षण के लिए माइक्रोफिल्म बनाने में सहयोग करेगी राज्य सरकार
- जयपुर में बनेगा वंशावली संरक्षण एवं संवर्धन अकादमी का कार्यालय

मानव वंश लेखन परंपरा सभ्यता और संस्कृति का महत्त्वपूर्ण अंग है। वंश लेखकों के पास विरासत के महत्त्वपूर्ण भंडार है। वंशावली लेखन की परंपरा भारत में ही है। वंशावलियां अपने गौरवशाली अतीत की जानकारी देती है। वंश लेखक संसाधनों के अभाव में भी लेखन

वंश लेखक सम्मेलन में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत

कार्य कर रहे है, यह बड़ी उपलब्धि है। राज्य सरकार वंश लेखकों के हितों के लिए योजनाएं बना रही हैं। शीघ्र ही जयपुर में वंशावली संरक्षण एवं संवर्धन अकादमी का कार्यालय शुरू किया जाएगा। यहां से प्रदेश के वंश लेखकों के उत्थान में कार्य संपादित होंगे।

हरिश्चन्द्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान के सभागार में वंश लेखक सम्मेलन और प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। राज्य सरकार का वंश लेखकों के साथ हमेशा जुड़ाव रहेगा। समारोह में वंश लेखकों के प्रतिभावान बच्चों को स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ वंश लेखकों से बातचीत कर लेखन पद्धति की जानकारी ली।

वंशावली संरक्षण के लिए अपनाएं नवाचार

जिस तरह राज्य सरकार द्वारा ऐतिहासिक अभिलेखों का डिजिटाइजेशन किया गया है, उसी तरह वंश लेखक लेखन में नवाचार अपनाएं। अकादमी द्वारा परम्परागत वंशालियों के संरक्षण और संधारण के लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाए। वंश लेखक शब्द के साथ स्वर, संगीत, साहित्य के सोरठा, दोहा, कवित्त, चौपाई, छप्पय आदि छंद की जानकारी रखने वाला होता है। यह खजाना विभिन्न वंश लेखकों के पास है। वंश लेखक पुराणों की कथा, लोक कथा, वंशावली लेखन, वंशावली वाचन और नई बहियों का निर्माण करता है।

34 लाख ऐतिहासिक अभिलेखों की बनाई माइक्रोफिल्म

बीकानेर स्थित राजस्थान राज्य अभिलेखागार देश का पहला डिजिटल अभिलेखागार है। यहां पूर्व रियासतों के 1.50 करोड़ से अधिक ऐतिहासिक और प्रशासनिक अभिलेखों के डिजिटाइजेशन का कार्य पूर्ण कर वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन कर दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा अभी तक 34 लाख ऐतिहासिक अभिलेखों की माइक्रोफिल्म बनाई जा चुकी है और 25 लाख अभिलेखों की शीघ्र बनाई जाएगी।

राज्य की योजनाओं की पूरे देश में चर्चा

राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की पूरे देश में चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 10 लाख रुपये तक का निःशुल्क इलाज दिया जा रहा है। इस राशि के अलावा किडनी, लीवर, हार्ट ट्रांसप्लांट में होने वाला खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। राज्य सरकार महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और उनके उत्थान के लिए प्रतिबद्धता के साथ निर्णय ले रही है। प्रदेश की 1.33 करोड़ महिलाओं को स्मार्टफोन वितरित किए जाएंगे, जिनके जरिए वे बातचीत ही नहीं बल्कि सरकारी योजनाओं की जानकारी भी प्राप्त कर सकेंगी और उनके बच्चे ऑनलाइन क्लास ले पाएंगे।

वंशावली में लिखा जाता है सिर्फ सत्य

प्रदेश में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में निःशुल्क इलाज की तरह यह अकादमी वंश लेखकों के लिए चिरंजीवी साबित होगी। वंशावलियों में सिर्फ सत्य लिखा जाता है। वंश लेखक किसी भी प्रलोभन से परे पूरी निष्ठा के साथ लेखन कार्य करते हैं। युवा पीढ़ी का

वंश लेखक सम्मेलन में पारितोषिक प्रदान करते हुए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत

वंशावली का अवलोकन करते हुए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत

वंश लेखन परम्परा से भी जुड़ाव रखने का आह्वान किया गया। राज्य सरकार द्वारा वंश लेखकों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। वंश लेखक लेखन के दौरान राज्य सरकार की योजनाओं का भी घर-घर जाकर प्रचार-प्रसार किया जायेगा। वंशावली अभूतपूर्व कला है। इसे संरक्षित करने की आवश्यकता है, इसके लिए राज्य सरकार कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री से मिला साधुओं और ग्रामीणों का प्रतिनिधिमंडल

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने भरतपुर के पसोपा व आस-पास के गांवों से आए साधु, महंत, जनप्रतिनिधि तथा ग्रामीणों के प्रतिनिधिमंडल से मिलकर महंत श्री विजयदास के निधन पर संवेदना व्यक्त की।

आदिबद्री धाम के महंत श्री शिवराम दास एवं पशुपति नाथ मंदिर के नवनियुक्त महंत श्री भूरा बाबा ने खनन क्षेत्र को वन क्षेत्र में परिवर्तित करने के आदेश पारित करने के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। राज्य सरकार के निर्देश से प्रशासन ने पसोपा व आस-पास के क्षेत्र में सड़क के निर्माण कार्यों हेतु स्वीकृति जारी की है। प्रतिनिधिमंडल भरतपुर के पसोपा में बृज क्षेत्र के पर्वतों की रक्षा करने के लिए तथा विभिन्न विकास कार्यों के लिए मुख्यमंत्री से मिला।

पसोपा व आस-पास की स्थानीय जनता प्रशासन के कार्यों से संतुष्ट है। आदिबद्री तथा कनकांचल को वन विभाग को हस्तातंरित करने के ऐतिहासिक निर्णय के लिए प्रदेश सरकार का संतों ने आभार व्यक्त किया।

क्रीड़ा परिषद के कर्मियों को पेंशन लाभ

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने जयपुर स्थित राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के सेवानिवृत्त कार्मिकों को पेंशन परिलाभ तथा पेंशन के भुगतान के लिए 13.40 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है।

प्रस्ताव के अनुसार, परिषद के समस्त सेवानिवृत्त कार्मिकों की पेंशन तथा परिलाभों का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा तथा परिषद की समस्त संपत्तियां राज्य सरकार में निहित होंगी।

उल्लेखनीय है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सवाई मानसिंह स्टेडियम में व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक लगी होने के कारण राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की आय नगण्य है। ऐसे में परिषद एक अलाभकारी संस्था है तथा राज्य सरकार के अनुदान से संचालित होती है। संस्था के कार्मिकों के समस्त वेतन-भत्ते आदि राजकीय अनुदान से ही वहन होते हैं।

बजट घोषणाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाने हेतु कार्यशाला

समाज के वंचित तबके के लिए काम करने तथा उनकी जमीनी जरूरतों को समझने में सिविल सोसाइटी व स्वयंसेवी संगठनों की अहम भूमिका है। सरकार द्वारा लोक कल्याण के लिए बनाई योजनाओं को कारगर तथा उपयोगी बनाने में इन संगठनों का महत्त्वपूर्ण योगदान रहता है। सिविल सोसाइटी सरकार को आत्मावलोकन करने में भी सहायता करती हैं तथा सरकार की योजनाओं, नीतियों और कार्यक्रमों की समीक्षा कर उन्हें और बेहतर बनाने में सहयोग करती हैं। सिविल सोसाइटी के सुझावों के बाद ही देश में आरटीआई, आरटीई, मनरेगा, खाद्य सुरक्षा जैसे महत्त्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। लोकतंत्र में सिविल सोसाइटी का अपना महत्त्व है, इसको नकारने वाले लोगों का निश्चित रूप से लोकतंत्र में विश्वास नहीं होता है।

बिड़ला ऑडिटोरियम में 'बजट का लाभ आमजन तक पहुंचाने के लिए आयोजित कार्यशाला' का आयोजन किया गया। सिविल सोसाइटी द्वारा राज्य बजट की प्रशंसा करने तथा बजट पर विश्वास जताया। कार्यशाला की रिपोर्ट पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में चर्चा होगी तथा सुझावों का क्रियान्वयन किया जाएगा। लोकतंत्र में संवाद की बड़ी महत्त्वता होती है। कार्य में सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है, इसलिए सिविल सोसाइटी के सदस्यों के सुझावों का हमारी सरकार हमेशा स्वागत करती है, ताकि कमियों को दूर कर योजनाओं को जनता के लिए अधिक लाभकारी बनाया जा सके। बहुमूल्य सुझावों की जरूरत हमेशा रहती है जिससे राज्य सरकार लक्ष्य को अर्जित करने में सफल हो सके।

शांति एवं अहिंसा निदेशालय बना विभाग

मुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी शांति एवं अहिंसा निदेशालय को एक विभाग के रूप में स्थापित करने की घोषणा की। वर्तमान में महात्मा गांधी के सिद्धांत, आदर्श एवं दर्शन की पहले से ज्यादा आवश्यकता है। गांधीजी के जीवन दर्शन को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से इस विभाग की स्थापना की गई है। आज देश एवं प्रदेश में काफी हिंसात्मक घटनाएं देखी जा रही हैं। इन घटनाओं को रोकने तथा शांति, सद्भाव एवं भाईचारा कायम करने के लिए गांधीजी के सिद्धांतों की आवश्यकता है।

राज्य सरकार पूरी संवेदनशीलता, पारदर्शिता एवं प्रतिबद्धता के साथ प्रदेशवासियों को सुशासन देने के ध्येय से कार्य कर रही है। राजस्थान जन आधार योजना के माध्यम से विभिन्न योजनाओं, सेवाओं का प्रत्यक्ष लाभ आमजन को पहुंचाना सुनिश्चित किया जा रहा है। प्रदेश के लगभग 45 लाख घरेलू उपभोक्ताओं का बिजली बिल शून्य हो गया है। राज्य के करीब 5 लाख कार्मिकों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किया गया। इसके साथ ही पुलिस थानों में निर्बाध पंजीयन सुनिश्चित किया गया है।

कोरोनाकाल में मनरेगा से मिला श्रमिकों को संबल

महात्मा गांधी नरेगा योजना एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसका लाभ कोरोना के समय देखने को मिला। कोरोनाकाल में इस योजना के माध्यम से लाखों श्रमिकों को रोजगार मिल सका तथा उनकी आर्थिक समस्या का समाधान भी हुआ। अब इस योजना की तर्ज पर राज्य सरकार द्वारा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत जॉब कार्ड भी जारी किए जा चुके हैं। राज्य सरकार की योजनाओं एवं फैसलों से प्रदेश के श्रमिकों का जीवनस्तर बेहतर हुआ है। प्रदेश में नई सिलिकोसिस नीति लागू की गई है जिसके तहत कार्यस्थल पर बेहतर कार्यपरिस्थितियों के लिए खान मालिकों को पाबंद किया गया है। सिलिकोसिस से होने वाली मृत्यु पर आर्थिक सहायता को भी सुनिश्चित किया गया है तथा 10 करोड़ रुपये के प्रवासी राजस्थानी श्रमिक कल्याण कोष का भी गठन किया जा रहा है।

पहली बार सिविल सोसाइटी की भागीदारी के साथ बजट क्रियान्वयन पर चर्चा हुई है। सिविल सोसाइटी इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए जन-जन तक जनता के बजट को पहुंचाने में सरकार की सहायता करेगी।

भारत के स्वतंत्रता संग्राम में स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। इन्होंने अपनी नौजवानी में स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और आजादी की लड़ाई लड़ी। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के संघर्ष की बदौलत ही हम आज आजादी की हवा में सांस ले रहे हैं।

सिविल सोसाइटी की बैठक जैसे कार्यक्रम पूरे देश में आयोजित हो सकें इस तरह का ढांचा तैयार किया जाएगा। सिविल सोसाइटी द्वारा कुल 13 विषयों पर विभिन्न सुझाव दिए गए हैं, इन्हें कैसे लागू किया जाए इस पर चर्चा की जाएगी।

वित्त विभाग की ओर से बिड़ला ऑडिटोरियम में 'जनता का बजट, जन-जन तक' कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें विभिन्न विभाग के अधिकारियों ने सामाजिक संगठनों व सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन पर चर्चा की। कार्यशाला में महात्मा गांधी नरेगा योजना, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, कृषि बजट, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच एवं दवा योजना, राइट टू हेल्थ बिल, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा मित्र योजना, पालनहार योजना, इंदिरा रसोई योजना आदि पर सामाजिक संगठनों व सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से चर्चा की गई।

युवाओं की सक्रिय भागीदारी एवं उनको ध्यान में रखकर, उनके सुझावों के आधार पर नवीन राजस्थान राज्य युवा नीति बनायी जाएगी।

स्वतंत्रता सेनानियों के घर पहुंचे मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देश की आजादी में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के घर पहुंचे तथा उन्हें सूत की माला पहनाकर, शॉल ओढ़ाकर व श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया।

मुख्यमंत्री सबसे पहले मानसरोवर के दादूदयाल नगर स्थित स्वतंत्रता सेनानी श्री रामू सैनी के घर पहुंचे तथा श्रीफल भेंट कर तथा माला व शॉल पहनाकर उनका सम्मान किया। मुख्यमंत्री ने श्री सैनी के साथ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चित्र के आगे दीप प्रज्ज्वलित कर पुष्पांजलि अर्पित की तथा ध्वजारोहण किया। इसके उपरांत मुख्यमंत्री ने निवारू रोड पर गणेश नगर स्थित स्वतंत्रता सेनानी श्री उमराव सिंह के घर पहुंचकर उनसे मुलाकात की और उन्हें माला व शॉल पहनाकर तथा श्रीफल भेंट कर उनका सम्मान किया। श्री गहलोत ने उनके आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। श्री गहलोत ने सी-स्कीम स्थित स्वतंत्रता सेनानी श्री सुभद्र कुमार पाटनी के आवास पर पहुंचकर उनसे मुलाकात की तथा शॉल ओढ़ाकर, माला पहनाकर एवं श्रीफल भेंट कर उन्हें सम्मानित किया तथा श्री पाटनी के आवास पर भी ध्वजारोहण किया।

भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इन स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। इन्होंने अपनी नौजवानी में स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और आजादी की लड़ाई लड़ी। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में शहीद हुए स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धासुमन अर्पित किया। उनकी बदौलत ही हम आज आजादी की हवा में सांस ले रहे हैं। हमारा कर्तव्य है कि आजादी की लड़ाई में योगदान देने वाले जो स्वतंत्रता सेनानी आज भी जीवित हैं, लोगों को उनके घर पहुंचकर उनका सम्मान करना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने इस दौरान स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारजनों से मिलकर उनकी कुशलक्षेम पूछी। स्थानीय लोगों ने जगह-जगह पर मुख्यमंत्री का तिरंगे झंडे फहराकर तथा मालाएं पहनाकर स्वागत किया तथा मुख्यमंत्री ने लोगों से मिलकर उनका अभिवादन स्वीकार किया।

स्वतंत्रता संनानी के घर पहुचकर उन्हें सम्मानित करते हुए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत

स्वतंत्रता सेनानी के घर पहुंचकर उन्हें सम्मानित करते हुए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत

स्वतंत्रता संनानी के घर पहुचकर उन्हें सम्मानित करते हुए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत

'बजट का लाभ आमजन तक' कार्यशाला में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत

आजादी का अमृत महोत्सव

75 वर्ष, 75 उपलब्धियां

लक्ष्मण चौहान
सहायक प्रोग्रामर

राजस्थान वीरों की भूमि है, इसका गौरवशाली इतिहास रहा है। एक ओर देश की आजादी के संघर्ष में यहां के महाराणा प्रताप, वीर दुर्गादास राठौड़, पन्ना धाय जैसे नायकों ने स्वाधीनता, बलिदान, त्याग की प्रेरणा का संचार किया। वही दूसरी ओर यहां के किले, महल, बावड़ियां आदि ऐतिहासिक स्थलों का स्थापत्य, लोक कला एवं संस्कृति ने विश्व पटल पर विशेष पहचान दिलाकर दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित किया।

आजादी से पूर्व बीकानेर के गंगासिंह द्वारा निर्मित गंगनहर, जयपुर के सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित जंतर मंतर वेधशाला, बाल विवाह के खिलाफ श्री हरबिलास शारदा द्वारा 1929 में पारित शारदा अधिनियम जैसे अनेकों कार्यों ने राजस्थान के आर्थिक व सामाजिक विकास की नींव रखी। इस विरासत को आगे बढ़ाते हुए राज्य में गत 75 वर्षों में प्रमुख 75 मील के पत्थर स्थापित किए-

1. **पंचायती राज की स्थापना :-** सत्ता विकेन्द्रीकरण के उद्देश्य से 2 अक्टूबर, 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर में देश में पहली बार पंचायती राज की स्थापना की गई।
2. **राजस्थान काश्तकारी अधिनियम:-** आजादी से पूर्व जमीदारी प्रथा में किसानों के पास अधिकार नहीं थे जिससे उनका शोषण होता था। किसानों को अधिकार देने के लिए और कृषि सुधार के लिए 15 अक्टूबर, 1955 को काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया। वर्ष 2020 से इस दिन को राजस्व दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है।
3. **राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम:-** कृषि भूमि का सुव्यवस्थित रिकॉर्ड रखने के उद्देश्य से 23 मई, 1956 को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम पारित किया गया। इसके पारित होने से किसानों को अपनी भूमि का हक मिला।
4. **1965 का भारत-पाक युद्धः-** बाड़मेर के मुनाबाव और गडरा रोड पोस्ट से भारतीय सेना ने स्थानीय लोगों के सहयोग से पाकिस्तानी सेना को परास्त किया।
5. **1971 का भारत-पाक युद्धः-** जैसलमेर के लोंगेवाला में भारतीय सेना की एक छोटी सी टुकड़ी मेजर कुलदीपसिंह के नेतृत्व में पाकिस्तान की बड़ी फौज को शिकस्त दी। पश्चिमी सेक्टर पर भारतीय सेना के मजबूत प्रहार ने पाकिस्तानी सेना को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया। इस युद्ध में विशेष योगदान के लिए जयपुर के भवानीसिंह को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया।
6. **प्रथम परमाणु परीक्षण :-** 18 मई, 1974 को जैसलमेर के पोकरण में ''स्माइलिंग बुद्धा'' नाम से देश का पहला परमाणु परीक्षण किया गया।
7. **द्वितीय परमाणु परीक्षण :-** 11 मई, 1998 को पुन: पोकरण-2 के नाम से परमाणु परीक्षण कर गया। इस परीक्षण से भारत विश्व पटल पर परमाणु शक्ति के रूप में उभरा।
8. **इंदिरा गांधी नहर परियोजना :-** पूर्व में निर्मित गंगनहर की तर्ज पर पश्चिमी राजस्थान में जल आपूर्ति के लिए पंजाब के हरिके बांध से राजस्थान नहर का निर्माण करवाया। 1984 में इसका नामकरण पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के नाम से किया।

9. **नर्मदा नहर परियोजना :–** सरदार सरोवर बांध गुजरात से 532 किमी लम्बी नहर का निर्माण कर जालोर के सांचौर में पानी लाया गया। यह राजस्थान की दूसरी बड़ी नहर है। इस नहर से सिंचाई के लिए सूक्ष्म सिंचाई पद्धति का इस्तेमाल करना अनिवार्य है।
10. **माही बजाज सागर परियोजना :–** बांसवाड़ा जिले में माही नदी पर निर्मित माही बजाज सागर बांध एक बहुउद्देश्यीय परियोजना है। इस पर विद्युत् उत्पादन संयंत्र भी स्थापित है। यह बांध आदिवासियों के लिए वरदान है।
11. **बीसलपुर बांध :–** टोंक जिले में बनास नदी पर बीसलपुर बांध का निर्माण वर्ष 1999 में पूर्ण हुआ। इस बांध से जयपुर, अजमेर आदि प्रमुख शहरों में जल आपूर्ति होती है।
12. **पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना :–** पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में पेयजल और सिचांई जल की आपूर्ति के लिए एक वृहद पेयजल परियोजना है। इस परियोजना से चंबल सहित इसकी सहायक नदियों का जो जल समुद्र में व्यर्थ बह जाता था उसका सदुपयोग हो सकेगा। इस परियोजना का कार्य प्रगतिरत है।
13. **रावतभाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र:–** राजस्थान परमाणु उर्जा परियोजना द्वारा कोटा के रावतभाटा में प्रदेश का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र दिसम्बर, 1999 में स्थापित किया गया।
14. **सूरतगढ़ तापीय संयंत्र:–** बीकानेर के सूरतगढ़ में कोयला आधारित प्रदेश का सर्वाधिक तापीय ऊर्जा उत्पादन संयंत्र।
15. **कालीसिंध तापीय संयंत्र :–** झालावाड़ में कालीसिंध नदी पर सामान्य व सुपर क्रिटिकल तापीय संयंत्रों से कुल 2440 मेगावॉट विद्युत उत्पादन हो रहा है।
16. **छबड़ा तापीय संयंत्र :–** बारां में कुल 6 सामान्य व सुपर क्रिटिकल तापीय संयंत्रों से कुल 2320 मेगावाट विद्युत उत्पादन हो रहा है।
17. **सौर ऊर्जा में सिरमौर :–** राजस्थान 17,040 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता के साथ देश में प्रथम स्थान पर है।
18. **भड़ला सोलर पार्क :–** जोधपुर के फलोदी में 2245 मेगावॉट उत्पादन क्षमता के साथ विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित किया गया है।
19. **कच्चे तेल के कुओं की खोज :–** प्रदेश में 4 पेट्रोलियम बेसिन उपलब्ध हैं, जिसमें बाड़मेर-सांचौर सबसे बड़ा है। इस बेसिन में क्रेयॉन्स इंडिया द्वारा मंगला, शक्ति, विजया, भाग्य, ऐश्वर्य आदि प्रमुख कुओं की खोज की गई है।
20. **प्राकृतिक गैस भण्डार की खोज :–** जैसलमेर और बाड़मेर बेसिन में कामेश्वरी, सरस्वती, रागेश्वरी आदि प्रमुख कुओं से प्राकृतिक गैस निकाली जा रही है।
21. **कोयला उत्खनन:–** राजस्थान में लिग्नाइट प्रकार का कोयला बाड़मेर के गिरल, कपूरड़ी, जालिपा, भदरेस नागौर के मातासुख व कसनाऊ, बीकानेर के बरसिंगसर, करणीमाता आदि स्थानों पर प्रमुखता से निकाला जाता है।
22. **रिफाइनरी की स्थापना :–** बाड़मेर के पचपदरा में एचपीसीएल और राजस्थान सरकार के संयुक्त उपक्रम में 9 एमएमटीपीए क्षमता वाली रिफाइनरी मय पेट्रोकेमिकल कॉम्पलेक्स का कार्य प्रगतिरत है।
23. **बायो ईंधन नीति :–** राजस्थान करंज, रतनजोत आदि तेलीय वनस्पति से बायो ईंधन बनाने के लिए बायो ईंधन नीति लाने वाला पहला राज्य है।
24. **गौमूत्र रिफाइनरी :–** जालौर के सांचौर में पथमेड़ा गौशाला में गौमूत्र से विभिन्न औषधि बनाने के लिए देश की पहली गौमूत्र रिफाइनरी स्थापित की गई।
25. **केन्द्रीय इलेक्ट्रोनिक अभियांत्रिकी शोध संस्थान:–** 1974 में पिलानी में इलेक्ट्रोनिक के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए राष्ट्रीय स्तर के संस्थान की स्थापना।
26. **सौर वेधशाला :–** 1976 में उदयपुर के फतेहसागर में इसरो द्वारा सौर वेधशाला की स्थापना।
27. **प्रादेशिक सुदूर संवेदिक केन्द:–** अन्तरिक्ष से पृथ्वी के छायाचित्र के माध्यम से जानकारी प्राप्त करने के लिए इसरो द्वारा जोधपुर में प्रादेशिक सुदूर संवेदन केन्द्र की स्थापना।
28. **भारतीय तकनीकी संस्थान:–** तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2008 में जोधपुर में आईआईटी की स्थापना की गई।
29. **भारतीय प्रबंधन संस्थान:–** प्रबंधन में उच्च शिक्षा के लिए उदयपुर में वर्ष 2011 में आईआईएम की स्थापना की गई।
30. **भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान:–** कम्प्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े उच्च अध्ययन के लिए कोटा में वर्ष 2013 में आईआईआईटी की स्थापना।
31. **अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान:–** चिकित्सा क्षेत्र के सर्वोच्च संस्थान एम्स की वर्ष 2012 में जोधपुर में स्थापना।
32. **डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय:–** आयुष से लोगों को राहत देने के लिए वर्ष 2003 में जोधपुर में स्थापना।

33. **31 जिलों में मेडिकल कॉलेज:–** राजस्थान के 33 में से 31 जिलों में मेडिकल कॉलेजों की स्वीकृति, राज्य को चिकित्सा क्षेत्र में अग्रणी बनाता है।

34. **सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय:–** पुलिस और अपराध के सम्बन्ध में अध्ययन और अनुसंधान के लिए वर्ष 2012 में जोधपुर में स्थापना।

35. **हरदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय:–** मीडिया और जनसंचार के लगातार बढ़ते आकार, विविधता और महत्त्व को देखते हुए वर्ष 2019 में जयपुर में स्थापना।

36. **मनरेगा:–** महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम वर्ष 2006 में सर्वप्रथम लागू होने वाले देश में राजस्थान अग्रणी है। वर्ष 2022 में रोजगार देने के विभिन्न पैमानों पर राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर रहा।

37. **इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना:–** शहरी क्षेत्र में 100 दिन के रोजगार की गारंटी प्रदान करने की अनुपम पहल।

38. **सूचना का अधिकार:–** अजमेर के ब्यावर से किसान मजदूर शक्ति संगठन की मांग के आधार पर सरकारी कार्य में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए वर्ष 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम देश में लागू किया गया।

39. **लोक सेवा गारंटी अधिनियम:–** समयबद्ध सरकारी सेवाओं को उपलब्ध के लिए 14 नवम्बर, 2011को राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम लागू किया गया।

40. **सुनवाई का अधिकार:–** जनता की शिकायत और सुझाव को समयबद्ध सुनना और उसका निराकरण करने का सुनवाई का अधिकार अधिनियम 1 अगस्त, 2012 को लागू किया।

41. **मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना:–** राजकीय चिकित्सालयों में सभी मरीजों को नि:शुल्क दवा उपलब्ध करवाने के लिए यह योजना 2 अक्टूबर, 2011 से लागू।

42. **मुख्यमंत्री नि:शुल्क जांच योजना:–** राजकीय चिकित्सालयों में मरीजों की नि:शुल्क जांच 7 अप्रैल, 2013 से लागू।

43. **मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना:–** 'यूनिवर्सल हैल्थ कवरेज' की दिशा में आगे बढ़ते हुए समस्त प्रदेशवासियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना 1 मई, 2021 से लागू।

44. **प्रशासन शहरों और गांवों के संग:–** आमजन को सरकारी काम के लिए विभिन्न अधिकारियों और विभागों के चक्कर न काटने पड़े, इस उद्देश्य से शिविरों का आयोजन कर सरकारी सेवा जनता तक पहुंचाई जा रही है।

45. **महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय:–** सरकारी स्कूलों में भी अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा मिले इसके लिए महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों की स्थापना।

46. **राजस्थान सूक्ष्म, लघु एवं मध्य उद्योग(स्थापना एवं संचालन सुविधा) अधिनियम, 2019:–** नए उद्योग स्थापित करने में विभिन्न अनुमति और अनापत्ति के प्रावधानों को खत्म कर, उन्हें प्रोत्साहित करने हेतु यह अधिनियम 17 जुलाई, 2019 को लागू।

47. **ई–मित्र:–** राजकीय सेवाओं की आपूर्ति में भौगोलिक बाधाओं को दूर करने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी और संचार से इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम उपलब्ध करवाई जा रही है।

48. **राजस्थान सम्पर्क:–** आमजन की शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए एकीकृत इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म, 181 पर फोन कर भी शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है।

49. **जन सूचना पोर्टल:–** सरकारी योजनाओं और इनके लाभार्थियों की जानकारी प्रदान करने के लिए 13 सितम्बर, 2019 को पोर्टल लॉन्च किया गया।

50. **जन कल्याण पोर्टल:–** सरकार से जुड़े दस्तावेजों को एक ही पोर्टल पर उपलब्ध कर के उद्देश्य से 18 दिसम्बर, 2021 को जन कल्याण पोर्टल लॉन्च किया गया।

51. **जन आधार कार्ड:–** प्रदेशवाशियों को ''एक कार्ड, एक नम्बर, एक पहचान'' देने के उद्देश्य से जन आधार कार्ड बनाए गए है। यह बायोमेट्रिक सूचना के आधार पर काम करता है।

52. **जयपुर मेट्रो:–** जयपुर के यातायात को सुगम बनाने के लिए 13 नवम्बर, 2010 को मानसरोवर से चांदपोल तक जयपुर मेट्रो के प्रथम फेज की शुरुआत की गई।

53. **खेल–खिलाड़ी:–** राजस्थान से अब तक 1 ओलम्पिक पदक और 4 पैरा ओलम्पिक पदक (श्री देवेन्द्र झांझड़िया, सुश्री अवनि लेखरा, श्री कृष्णा नागर, श्री सुन्दर सिंह गुर्जर) विजेता हुए।

54. **विश्व धरोहर:–** यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, आमेर दुर्ग, कुम्भलगढ़, चित्तौडगढ़, गागरोन दुर्ग, सोनार दुर्ग, रणथम्भौर दुर्ग, जंतर–मंतर, जयपुर शहर परकोटा ने अपना स्थान बनाया।

55. **केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केन्द्र:–** राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में शुष्क वनस्पति विकास हेतु काजरी की स्थापना वर्ष 1959 में जोधपुर में हुई।

56. **केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केन्द्र:–** भेड़ व पशुपालन के क्षेत्र

में अनुसंधान और विकास हेतु टोंक जिले के अविकानगर में राष्ट्रीय स्तर के केन्द्र की स्थापना।

57. **राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केन्द्रः–** कृषि और बागवानी में अनुसंधान और विकास हेतु अजमेर के तबीजी में राष्ट्रीय स्तर के केन्द्र की स्थापना।

58. **राष्ट्रीय राई–सरसों अनुसंधान केन्द्रः–** खाद्य तेल आपूर्ति की सुरक्षा एवं सरसों–राई की फसल की उन्नत किस्में तैयार कर उत्पादकता बढ़ाने हेतु 20 अक्टूबर, 1993 को भरतपुर के सेवर में स्थापना।

59. **राजस्थान का पहला कृषि बजटः–** कृषि व किसान की महत्ता को देखते हुए राजस्थान में पहली बार वर्ष 2022–23 के लिए कृषि बजट अलग से पेश किया गया।

60. **वन संरक्षणः–** वन सम्पदा और वन्यजीव संरक्षण के लिए प्रदेश में 3 राष्ट्रीय उद्यान एवं 27 अभयारण्य अधिसूचित किए गए।

61. **वन्यजीव संरक्षणः–** बाघों के संरक्षण के लिए रणथम्भौर, सरिस्का, मुकुन्दरा और रामगढ़ विषधारी बाघ संरक्षण क्षेत्र अधिसूचित किए गए।

62. **पैंथर संरक्षणः–** राजस्थान पैंथर संरक्षण करने वाला देश का पहला राज्य।

63. **दिल्ली–मुम्बई औद्योगिक गलियाराः–** दिल्ली और मुम्बई के बीच विकसित किए जा रहे औद्योगिक गलियारे का 39 प्रतिशत राजस्थान से गुजरता है। राजस्थान में इस गलियारे पर 5 औद्योगिक क्षेत्र और निवेश क्षेत्र विकसित किए जा रहे है।

64. **हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेडः–** अरावली क्षेत्र में कॉपर खनिज की उपलब्धता को देखते हुए वर्ष 1967 में झुंझुनूं के खेतड़ी में हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना की गई।

65. **हिन्दुस्तान सॉल्टस् लिमिटेडः–** जयपुर के सांभर में उपलब्ध नमक के विशाल भण्डार से नमक उत्पादन के लिए वर्ष 1958 में हिन्दुस्तान सॉल्टस् लिमिटेड की स्थापना की गई।

66. **निर्यात संवर्धन एवं औद्योगिक पार्कः–** निर्यात को प्रोत्साहित करने हेतु प्रदेश में जयपुर के सीतापुरा, जोधपुर के बोरानाड़ा और अलवर के नीमराणा में रिको द्वारा विशेष निर्यात पार्क विकसित किए गए।

67. **जापानी पार्कः–** जापानी कम्पनियों को भारत में उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु अलवर के नीमराणा में रीको द्वारा जापानी पार्क विकसित किया गया।

68. **शिक्षाः–** आजादी के समय केवल 5657 विद्यालय थे जो अब बढ़कर 103189 हो गए, तब केवल 1 विश्वविद्यालय और 51 महाविद्यालय थे, परन्तु वर्तमान में 27 विश्वविद्यालय और 2413 महाविद्यालय संचालित हो रहे हैं।

69. **साक्षरताः–** राजस्थान की साक्षरता 1951 में 8.02 प्रतिशत थी, जो 2011 में बढ़कर 66.1 प्रतिशत हुई।

70. **चिकित्साः–** 1951 में राजस्थान में केवल 234 चिकित्सालय थे जो अब बढ़कर 17,469 हो गए हैं, इसी का परिणाम है कि लोगों का जीवन स्तर सुधरा और औसत आयु में वृद्धि हुई।

71. **सिंचाईः–** प्रदेश में कृषि सिंचाई क्षेत्र वर्ष 1956–57 में 1693 हजार हैक्टेयर था जो वर्ष 2020–21 में 11,788 हजार हैक्टेयर हुआ। हमने कृषि सिंचाई क्षेत्र में 10 गुणा से अधिक की वृद्धि दर्ज की।

72. **खाद्यानः–** प्रदेश में वर्ष 1951 में कुल खाद्यान्न उत्पादन 29.46 लाख मैट्रिक टन था, जो वर्ष 2020–21 में बढ़कर 269.09 लाख मैट्रिक टन हुआ।

73. **विद्युतः–** आधारभूत ढांचे में हमारी अधिष्ठापित विद्युत क्षमता केवल 8 मेगावाट थी और 26 शहर व 16 गांव बिजली से जुड़े थे पर अब 23454 मेगावाट विद्युत क्षमता के साथ सभी शहर और लगभग 99 प्रतिशत गांव बिजली से जुड़ चुके हैं।

74. **सड़कः–** 1951 में केवल 18,749 कि.मी सड़कें और 6,684 गांव सड़कों से जुड़े थे। अब 2,72,969 कि.मी. सड़कें निर्मित हो चुकी हैं और करीब 38 हजार गांव सड़कों से जुड़ चुके हैं, जिससे यातायात के साधनों में वृद्धि हुई और अर्थव्यवस्था को गति मिली।

75. **एयरपोर्टः–** राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, जैसलमेर, बीकानेर और किशनगढ़ में कुल 7 एयरपोर्ट हैं।

जयपुर में संचालित मैट्रो

इंदिरा गाँधी मातृत्व पोषण योजना

गजाधर भरत
जनसम्पर्क अधिकारी, महिला एवं बाल विकास

राज्य के चार जनजातीय जिलों प्रतापगढ, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर तथा एक सहरिया बहुल जिला बारां सहित पांच जिलों में इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना की सफलता के आधार पर मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा वर्ष 2022-23 के बजट में योजना को राज्य के सभी 33 जिलों में लागू करने की घोषणा की गई है। राज्य में योजनान्तर्गत प्रतिवर्ष लगभग 3,50,000 महिलाओं को योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा वर्ष 2020-21 में की गई बजट घोषणा की पालना में पांच जिलों में इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना 19 नवम्बर 2020 से संचालित है। महिला लाभार्थियों के लिए यह योजना एक वरदान साबित हुई है। योजना अन्तर्गत महिला लाभार्थी को दूसरी संतान पर पांच चरणों में 6,000 रुपये का नकद लाभ दिया जाता है जो कि उन्हें पोषण संबल प्रदान कर रहा है। योजना अन्तर्गत अब तक 22 हजार से अधिक लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है।

पहली किस्त- इंदिरा गाँधी मातृत्व पोषण योजना में उक्त पांच जिलों में लाभार्थी को गर्भावस्था जांच व पंजीकरण होने पर रु. 1,000 राशि की पहली किस्त (अंतिम माहवारी तिथि से 120 दिनों के भीतर पंजीकरण होने पर) दी जाती है।

दूसरी किस्त- कम से कम प्रसव पूर्व दो जांचें (एएनसी) पूरी होने पर रु.1,000 की राशि है। (गर्भावस्था के 6 महीने के भीतर) दूसरी किस्त के रूप में दी जाती है।

तीसरी किस्त- लाभार्थी को बच्चे का जन्म होने पर (संस्थागत प्रसव पर) रु.1,000 राशि तीसरी किस्त के रूप में दी जाती है।

चौथी किस्त - बच्चे के 3 माह (105 दिवस) की उम्र तक के सभी नियमित टीके जन्म से 120 दिवस में लग जाने व नवजात बच्चे का जन्म पंजीकरण होने पर (टीकाकरण के अंतर्गत बच्चे को बीसीजी, ओपीवी, डीपीटी और हेपेटाइटिस-बी या इसके समकक्ष विकल्प की पहली खुराक मिलने पर) चौथी किस्त के रूप में रु. 2,000 की राशि दी जाती है।

पांचवी किस्त-द्वितीय संतान के उपरांत दंपती द्वारा संतान उत्पत्ति के 3 माह के भीतर स्थाई परिवार नियोजन साधन अपनाए जाने अथवा महिला द्वारा कॉपर टी (पीपीआईयूसीडी) लगवाया जाने पर रु.1,000 की राशि पांचवी किस्त के रूप में दी जाती है। इस प्रकार इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजनान्तर्गत महिला लाभार्थियों को कुल राशि 6,000 रु. की राशि दी जाती है।

योजना में 1 नवंबर 2020 एवं उसके बाद द्वितीय संतान से गर्भवती महिलाएं पात्र लाभार्थी हैं। यह योजना पूर्णतया पेपरलेस है, जिसमें लाभार्थियों को कहीं आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। स्वास्थ्य विभाग के पीसीटीएस सॉफ्टवेयर में दर्ज लाभार्थियों की जानकारी को विभाग के राजपोषण पोर्टल से ऑनलाइन सत्यापन उपरांत निर्धारित राशि सीधा उनके जनाधार से जुड़े बैंक खाते में जमा कर दी जाती है।

समूचे राज्य में महिलाओं को मिलेगा संबल

योजनान्तर्गत नए सम्मिलित 28 जिलों में ऐसी सभी महिलाओं को पात्र लाभार्थी माना जाएगा जो एक अप्रैल 2022 को या उसके पश्चात द्वितीय संतान हेतु गर्भवती है। साथ ही यदि महिला निर्धारित तिथि एक अप्रैल 2022 से पूर्व गर्भवती है, तो निर्धारित तिथि एक अप्रैल 2022 एवं इसके बाद वह योजना की जिस किस्त के लिए पात्र होगी, उसे योजना की शर्तो के अनुसार उस किस्त के साथ आगे की सभी किस्तों के लिए पात्र माना जाएगा।

मारवाड़ के प्रखर स्वतंत्रता सेनानी

श्री छोटमल सुराणा

लक्ष्मण पारंगी
स्वतंत्र पत्रकार

पूर्व राष्ट्रपति डॉ. शंकरदयाल शर्मा स्वतंत्रता सेनानी का सम्मान करते हुए

पाली जिले के बाली कस्बे में श्री सौभाग्यमल सुराणा के घर 7 जून 1902 को श्री छोटमल सुराणा का जन्म हुआ। इनके पिता वकील थे। जीवन में कुछ कर गुजरने की ठानते हुये वे भारत के स्वतन्त्रता संग्राम में कूद पड़े। उस समय गांधीजी से प्रेरित होकर उनके आदर्शो, सत्य व अहिंसावादी नीति से अंग्रेजों से भारत को मुक्त कराने व 1920 में गांधीजी के असहयोग आंदोलन की कडी में उन्होंने मारवाड़ गोडवाड़ को अपना कार्यक्षेत्र बनाया। श्री सुराणा सत्याग्रह को रामबाण औषधी की तरह अपने विचारों से अनुकूल समाज के स्वस्थ निर्माण हेतु लोक संगठन निर्माण में जुट गये।

अंग्रेजी हुकूमत के साथ सामन्त काल भी था। सम्पूर्ण भारत में जागीरी प्रथा पूरे चरम पर थी। जागीरदार किसानों के हितों की उपेक्षा कर गांवों का लाटा-बांटा, बैठ-बेगार, लाग-भाग की जबरन वसूली करते थे। जिनसे किसान अत्यधिक दु:खी थे। किसानों की ऐसी हालत के बारे में जब श्री सुराणा को पता चला तो उन्होंने किसानों को इस समस्या से सदैव के लिये छुटकारा दिलाने में सत्याग्रह, असहयोग व अंहिसावादी नीतियों के बल पर उनके साथ हो लिये। जब श्री सुराणा किसानों में नई ताकत भर रहे थे उस समय जागीरदार अंग्रेजी हुकूमत के सहारे मौज कर रहे थे। उस समय किसानों ने मोर्चा खोल दिया। भाटून्द के काश्तकारों ने संगठित कर उन्होंने सत्याग्रह में धरना शुरु कर दिया। किसानों ने लगातार जागीरदारों से असहयोग करना चालू रखा और श्री सुराणा के सहयोग से जागीरदारों ने अपने जुल्म की जाजम समेटली। भाटून्द गांव के इस सत्याग्रह ने श्री सुराणा को पूरे गोडवाड़ क्षेत्र में विख्यात बना दिया। श्री छोटमल सुराणा अनवरत संघर्ष के लिये कृत संकल्प रहे। अपने ही बिरादरी के सूदखोर सेठों के आखों की किरकीरी बन चुके श्री सुराणा के साथ लूट व प्रताड़ना की घटना को भी विरोधियों

द्वारा अंजाम दिया गया। लम्बे संघर्ष के बाद श्री सुराणा को 1940 में राजद्रोह का मुकदमा दायर कर बाली किले की जेल में डाल दिया। उन्हें वहां प्रताडित कर यातनायें दी गईं। जीवन में उन्होंने गांधी टोपी व खादी की पोशाक को ही अपना वस्त्र माना। अपने साथ वे भोजन ले जाते थे। स्वयं अर्जित आय से ही खाना खाते थे। उन्हें कबीर व रहीम के भजन बहुत प्रिय थे। मारवाड़ गोड़वाड़ में जागीरदारों, सूदखारों, जमाखोरों व अत्याचारों के विरुद्ध अपनी आवाज बुलन्द कर सदैव आम जन के हित में अपना लोहा मनवाने वाले श्री छोटमल सुराणा का निधन 1 मार्च 1978 को हुआ।

राजस्थान: स्वतन्त्रता आंदोलन की पत्रकारिता के प्रमुख व्यक्तित्व

डॉ. सपना शाह
जनसम्पर्क अधिकारी

देश की आजादी के संघर्ष को जन-जन तक पहुंचाने और इसे जन आंदोलन में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका समाचार पत्रों और पत्रिकाओं ने निभाई। इन सभी क्रांतिकारी समाचार पत्रों के सम्पादक और प्रकाशक भारतीय स्वतंत्रता के वे वीर सेनानी थे, जिन्होंने हर सम्भव प्रयास कर संघर्ष की मशाल को जलाए रखा।

राजस्थान में तत्कालीन निरंकुश एवं शोषक व्यवस्था के विरुद्ध जितने भी राजनीतिक सुधार आंदोलन हुए, उन आंदोलनों के लिए वैचारिक पृष्ठभूमि तैयार करने और उनके लिए राष्ट्रीय चेतना की भावना के विकास में तत्कालीन समय में प्रकाशित विभिन्न समाचार पत्र-पत्रिकाओं ने महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। भारत में पहला समाचार पत्र 'बंगाल गजट' मन एवं विचार की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की उद्घोषणा करता हुआ सन् 1780 में बंगाल से प्रारंभ हुआ। लेकिन राजपूताना में इसके 69 वर्ष बाद सन् 1849 में समाचार पत्रों की शुरूआत हुई। भरतपुर से प्रकाशित मासिक 'मजह-उल-सरूर' पहला पत्र था। राजस्थान में पत्रकारिता के प्रारंभिक काल में मुख्यत: सरकारी सूचना से परिपूर्ण राजकीय राजपत्रों का जन्म हुआ, जिनकी सामग्री मुख्यत: सुधारवादी होती थी।

राजस्थान की पत्रकारिता के प्रमुख व्यक्तित्व

स्वतंत्रता आंदोलन रूपी यज्ञ में आहुति देने, सामंतवादी व्यवस्था के खिलाफ बिगुल बजाने और अंग्रेजी शासन को समाप्त कर स्वतंत्रता का आह्वान करने वाले कुछ प्रमुख व्यक्तित्वों का उल्लेख किया जा रहा है

श्री विजय सिंह पथिक

जन्म- सन् 1882, स्थान- उत्तर प्रदेश में बुलन्दशहर जिले के गुठावली ग्राम में। श्री पथिक राजस्थान के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी पत्रकार और लेखक थे। बिजौलिया आंदोलन का सूत्रपात करने का श्रेय श्री पथिक को ही जाता है। अक्टूबर 1920 में वर्धा से उन्होंने 'राजस्थान केसरी' साप्ताहिक पत्र प्रकाशित किया। 1921 में अजमेर से प्रकाशित साप्ताहिक नवीन राजस्थान का जन्म हुआ जिसका आदर्श वाक्य ही यह था- **यश वैभव सुख की चाह नहीं, परवाह नहीं जीवन न रहे। यदि इच्छा है यह है, जग में स्वेच्छाचार दमन न रहे।।** यह राजस्थान की दबी कुचली जनता की आवाज बन गया। इस पत्र ने 'बिजौलिया सत्याग्रह' को पूरा समर्थन प्रदान किया। यही पत्र बाद में 'तरुण राजस्थान' के नाम से प्रकाशित हुआ।

> **देश की आजादी के संघर्ष को जन-जन तक पहुंचाने और इसे जन आंदोलन में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका समाचार पत्रों और पत्रिकाओं ने निभाई। इन सभी क्रांतिकारी समाचार पत्रों के सम्पादक और प्रकाशक भारतीय स्वतंत्रता के वे वीर सेनानी थे, जिन्होंने हर सम्भव प्रयास कर संघर्ष की मशाल को जलाए रखा।**

श्री केसरी सिंह बारहठ

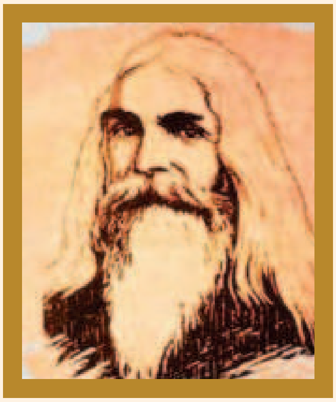

जन्म- सन् 1872, स्थान- शाहपुरा रियासत का देवपुरा गांव। श्री केसरी सिंह के देश के शीर्ष क्रांतिकारियों के साथ घनिष्ठ संबंध थे। श्री बारहठ द्वारा रचित 'चेतावनी रा चुंगट्या' नामक सौरठे पढ़कर मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने लॉर्ड कर्जन द्वारा आयोजित दिल्ली दरबार में ना जाने का निश्चय किया। वर्ष 1920 -21 में सेठ जमनालाल बजाज के आमंत्रण पर श्री बारहठ वर्धा चले गए। वर्धा में उनके नाम से 'राजस्थान केसरी' साप्ताहिक शुरू किया गया, जिसके संपादक श्री विजय सिंह पथिक थे। वर्धा में श्री बारहठ महात्मा गांधी के सम्पर्क में आए। 'चेतावनी रा चुंगट्या' उनकी अंग्रेजों के विरूद्ध भावना की स्पष्ट अभिव्यक्ति है।

कैप्टन दुर्गाप्रसाद चौधरी

जन्म- सन् 1906, स्थान- सीकर जिले का नीमकाथाना कस्बा। श्री दुर्गाप्रसाद चौधरी ने स्वाधीनता संग्राम और आन्दोलनों में सक्रियता से भाग लिया, साथ ही पत्रकारिता के क्षेत्र में भी महत्त्वपूर्ण कार्य किया। 2 अक्टूबर सन् 1936 से साप्ताहिक पत्र 'नवज्योति' का प्रकाशन श्री रामनारायण चौधरी ने किया। श्री दुर्गाप्रसाद इसके प्रमुख सहयोगी रहे। इस पत्र ने राष्ट्रीय चेतना

जागृत करने, जन आन्दोलनों को आगे बढ़ाने, ब्रिटिश सामन्तवादी जुल्मों को प्रकाश में लाने और आजादी की लड़ाई को ताकत देने का कार्य किया। पत्र के मुखपृष्ठ पर छपा होता था- 'फूंकने निष्प्राणों में प्राण, कराने दुखितों को निजभान, जगाने को आई नवज्योति, जनों में त्याग और बलिदान।' कप्तान दुर्गाप्रसाद ने अपनी कलम को तलवार बनाकर आजादी की लड़ाई में भाग लिया। उस समय एक मात्र यही ऐसा पत्र था जिसने ब्रिटिश साम्राज्यवाद और सामंतशाही के विरुद्ध कठोर प्रहार किए।

श्री रामनारायण चौधरी

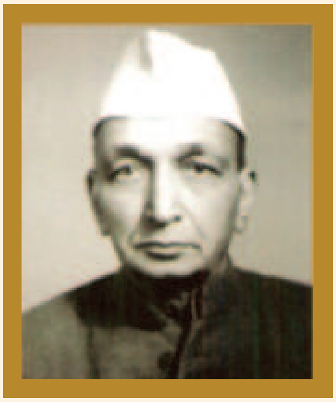

जन्म- सन् 1895, स्थान- सीकर जिले का नीमकाथाना कस्बा। श्री रामनारायण चौधरी, विजय सिंह पथिक द्वारा स्थापित राजस्थान सेवा संघ के मंत्री बने और संघ द्वारा प्रकाशित 'राजस्थान केसरी' के सह संपादक और प्रकाशक नियुक्त हुए। सन् 1921 में चौधरी जी के संपादकत्व में अजमेर से 'नवीन राजस्थान' साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन हुआ जो बाद में 'तरुण राजस्थान' के नाम से निकलने लगा। सन् 1929 में ब्यावर से अंग्रेजी साप्ताहिक 'यंग राजस्थान', सन् 1930 में हस्तलिखित अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र 'दि मैन' का प्रकाशन किया। सन् 1936 में अजमेर से साप्ताहिक पत्र 'नवज्योति' और सन् 1947 में दैनिक 'नया राजस्थान' के प्रकाशन का श्रेय भी आपको ही जाता है।

श्री अचलेश्वर प्रसाद शर्मा

जन्म- सन् 1907, स्थान- जोधपुर। कर्मठ पत्रकार और स्वतंत्रता सेनानी श्री अचलेश्वर प्रसाद शर्मा ने सदैव अपनी लेखनी से जनसमस्याओं को उजागर कर अंग्रेजी शासन पर प्रहार किया। तत्कालीन राजस्थान की डेढ़ करोड़ जनता की आवाज बने पत्र 'तरुण राजस्थान' के आप सह संपादक रहे। सन् 1930 में अजमेर में 'राजस्थान', सन् 1931 में आगरा में 'सैनिक' और सन् 1933-37 तक आकोला में 'नव राजस्थान' का संपादकीय कार्य किया। सन् 1940 में आपने जोधपुर से प्रकाशित 'प्रजासेवक' नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन, संपादन और संचालन किया।

पंडित झाबरमल्ल शर्मा

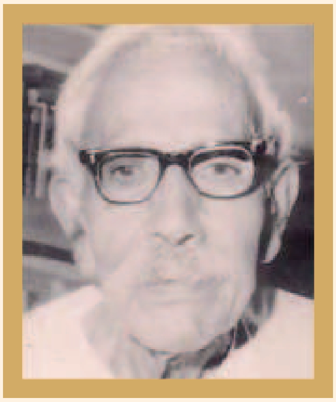

जन्म- सन् 1888, स्थान- खेतड़ी का जसरापुर गांव। राजस्थान की पत्रकारिता के भीष्म पितामह का उद्देश्य देश व जनता की सेवा करना था। प्रमुख प्रकाशन- सन् 1907 में मासिक 'ज्ञानोदय' का संपादन, सन् 1909 में बम्बई से प्रकाशित साप्ताहिक पत्र 'भारत', सन् 1910 में नागपुर से प्रकाशित 'मारवाड़ी' का संपादन तथा सन् 1914 में कलकत्ता से दैनिक 'कलकत्ता समाचार' का प्रकाशन- संपादन किया।

श्री जयनारायण व्यास

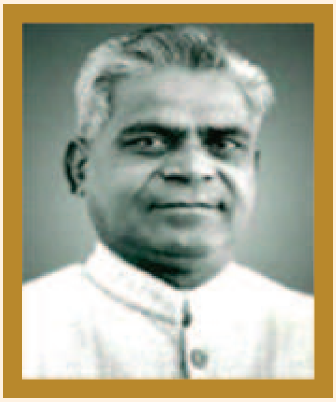

जन्म- सन् 1899, स्थान- जोधपुर। श्री व्यास ने सन् 1927 में 'तरुण राजस्थान' का प्रकाशन एवं संपादन कर क्रांति का अलख जगाया। सन् 1933 में बम्बई से दैनिक पत्र 'अखण्ड भारत' का प्रकाशन और सन् 1937 में ब्यावर से राजस्थानी भाषा के प्रथम पाक्षिक पत्र 'आगीवाण' का प्रकाशन व संपादन किया।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय

जन्म- सन् 1892, स्थान- ग्वालियर। श्री हरिभाऊ उपाध्याय प्रख्यात समाचार पत्र-पत्रिकाओं से जुड़े रहे। उन्होंने 'सरस्वती', 'प्रताप', 'हिन्दी नवजीवन', 'प्रभा', 'मालवा मयूर' जैसे प्रख्यात पत्र-पत्रिकाओं का संपादन कार्य किया। अजमेर से सन् 1927 में 'त्यागभूमि' और 1940 में 'जीवन साहित्य' का प्रकाशन एवं संपादन किया। श्री उपाध्याय सदैव देशवासियों में राष्ट्र निर्माण एवं राजनीतिक चेतना की भावना जागृत करने में रत रहे।

सर्वश्री हरिदेव जोशी, कनक मधुकर, केशरलाल अजमेरा जैन, नन्दकिशोर पारीक, पद्मसिंह शर्मा, ऋषिदा मेहता, शोभालाल गुप्त, सिद्धराज ढड्ढा जैसे अनेकों नाम राजस्थान की पत्रकारिता के बुलंद नाम है।

दीदी की कैंटीन, कुछ मीठी कुछ नमकीन

मेन्यु में जुड़े नए व्यंजन, बढ़ी आय, अब तक 61 कैंटीन स्थापित

डॉ. रजनीश शर्मा
उपनिदेशक, जनसम्पर्क

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा संचालित दीदी की कैंटीन में प्रशिक्षण के बाद अब ब्रेड सेंडविच, उत्तपम, इडली-सांभर के साथ, पकोड़े और जलेबी भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। प्रदेश में कुल 61 दीदी की कैंटीन संचालित हैं जिनमें से करीब एक दर्जन इसी वर्ष प्रारम्भ हुई हैं।

जिला एवं ब्लॉक स्तर के राजकीय कार्यालय परिसरों में ये कैंटीन राजीविका के अन्तर्गत स्वयं सहायता उत्पादन समूह की 5 से 10 महिलाओं द्वारा मिलकर संचालित की जा रही हैं। इनमें चाय-पानी, रिफ्रेशमेंट के लिए अलग-अलग प्रकार के मैन्यु पर आगंतुकों को खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाये जाते हैं। चिह्नित महिलाओं का समूह पाक कला में निपुण होने के साथ साथ उत्पाद विक्रय करने में भी समर्थ हैं।

इन कैंटीन में अन्य रेस्टोरेंट की भांति ही नाश्ते में समोसा, कचौरी, पोहा, चाय, काफी, दूध एवं घर में बने शुद्ध छाछ, राबड़ी, नमकीन एवं मीठी लस्सी, कोल्ड ड्रिंक्स आदि विक्रय किए जाते हैं। लंच में स्थानीय स्वादानुसार सब्जी-रोटी आदि बनाये एवं खिलाये जाते हैं।

दीदी की कैंटीन योजना का उद्देश्य इसे संचालित करने वाले स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त बनाना था जो पहले कभी अत्यावश्यक कार्यो से भी गांव के बाहर नहीं जा पाती थीं। वहीं अब ये महिलाएं सामाजिक बंधन के इस पड़ाव को पार कर, राजीविका द्वारा प्रदत्त मंच का लाभ उठाते हुए राजकीय कार्यालयों में आमजन के लिए कैंटीन के माध्यम से रिफ्रेशमेंट उपलब्ध कराने का कार्य कर रही हैं।

आधारभूत संरचना (INFRASTRUCTURE & MAINTANENCE) की व्यवस्था सम्बन्धी कार्य राजकीय स्तर पर सम्पूर्ण किये जाते हैं एवं CLF@ BANKS आदि से वित्त पोषण के द्वारा सामान्य रसोई के बर्तन एवं कच्चा माल आदि क्रय किये जाते हैं। प्राय: 5 से 10 महिलाओं का संगठन इसे भली-भांति क्रियान्वित कर रहा है।

प्रत्येक कैंटीन को मासिक रूप से आरंभिक तौर पर 10 से 25 हज़ार रुपए का मुनाफा हो रहा है। धीरे-धीरे उत्पादों की रेंज बढ़ने के साथ-साथ यह आय और बढ़ने की संभावना है। इस प्रकार के कार्य से उनके रोजगार में बढ़ोतरी के साथ ही उनको स्वाभिमान से जीने एवं

बच्चों के बेहतर पालन-पोषण में मदद प्राप्त हुई है। साथ ही सामाजिक बंधनों एवं कुरीतियों से निजात भी मिली है।

विभाग की योजना है कि इस प्रकार की कैंटीन समस्त जिला मुख्यालयों एवं ब्लॉक्स पर प्रारम्भ की जाएं। मॉडल कैंटीन के लिए आवश्यक वित्त प्रबंधन एवं सपोर्ट राजीविका द्वारा किया जायेगा, जिससे एक व्यवस्थित आदर्श कैंटीन के लिए आवश्यक सामान क्रय किये जा सकें। इनमें भविष्य में फोटो स्टेट मशीन भी इंस्टाल करवाई जा सकेगी। इस वित्तीय वर्ष में राज्य में करीब एक दर्जन कैंटीन खोले जा चुके हैं, जो सभी सुचारू रूप से चल रही हैं। आज तक खोले गए कुल 61 कैंटीन में से 54 पंचायत समितियों में एवं 7 जिला स्तर पर स्थापित हैं।

कहां-कहां संचालित हैं दीदी की कैंटीन

दीदी की कैंटीन चूरू में जिले में सात स्थानों पर बीदासर, सुजानगढ़, रतनगढ़, तारानगर, चूरू, सावन एवं जिला कलक्ट्रेट में, भरतपुर जिले में सात स्थानों जिला कलक्ट्रेट, कामां, कुम्हेर, सेवर, रूपबास, बयाना और पहाड़ी में, जयपुर में आठ जगह सांगानेर, शाहपुरा, बस्सी, जालसू, कोटपूतली, कोटखावदा, गोविन्दगढ़ एवं किशनगढ़ रेनवाल, दौसा में लवाण, बांदीकुई, पाली में जिला कलक्ट्रेट, अलवर में कठूमर एवं जिला परिषद में, कोटा में सांगोद, टोंक में मालपुरा एवं जिला कलक्ट्रेट में, उदयपुर में 11 जगह लसाड़िया, खैरवाड़ा, झाड़ोल, गोगुन्दा, सलूम्बर, रिषभदेव, फलासिया, सराड़ा, कोटड़ा, खैरबाद, सेमारी में करौली में दो जगह मासलपुरा एवं मंडरायल, प्रतापगढ़ में प्रतापगढ़, राजसमन्द में राजसमन्द जिला परिषद आमेट एवं जिला कलक्ट्रेट में, अजमेर में केकड़ी, अरांई और सिलोरा में, भीलवाड़ा में छह जगह, बनेडा, शाहपुरा, मांडल, बिजौलिया, कोटड़ी में, बांसवाड़ा में चार जगह सज्जनगढ़, अरथूना एवं बांसवाड़ा में चार, डूंगरपुर में कलक्ट्रेट कैम्पस, सागवाड़ा, दोबडा, गलियाकोट एवं बाड़मेर में चोहटन में ये केंटीन खोली गई हैं।

इनमें इस वर्ष शाहपुरा में मार्च में, सिलोरा में मई, बस्सी में जून में, जालसू, कोटपूतली, कोटखावदा, गोविन्दगढ़, बांदीकुई, मासलपुर, चोहटन, किशनगढ़ रेनलवाल एवं गलियाकोट में अगस्त में दीदी की कैंटीन प्रारम्भ हुई है।

"पहले मैं छोटा-मोटा काम करके अपनी आजीविका चला रही थी, लेकिन अब अलवर जिला परिषद में राजीविका की कैंटीन संचालित कर रही हूं। इसके बाद मेरे हालात बदले हैं, अच्छा रोजगार मिलने से परिस्थिति बदली, आय बढ़ी है जिससे अब बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा रही हूं।

श्रीमती अंजू, राजीविका कैंटीन संचालिका, अलवर

E waste scenario in Rajasthan

Bhunesh Chandra Mathur
Professor (Business Administarion)

The units handling E waste are classified by Rajasthan state pollution control board in RED CATEGORY in the State. Hence the dismantler, recycler, refurbisher and manufacturer have to take consent and authorization by concerned department.

For establishing E waste handling unit , the land must be converted to industrial use. Even the plot of land allotted by RIICO requires the change of land use and information in form of a notice board "FOR E WASTE" is mandatory .

Rajasthan E waste policy is under consideration, recently Rajasthan government has inverted the suggestions asked the opinion of general public.

Under the able leadership of CM Shri Ashok Gehlot, the state will look after scientific management of E waste by maximizing the E waste collection, ensuring that all collected E waste is processed and recycled to have minimum impact on environment.

Rajasthan State Pollution Control Board has authorized 25 E waste handling units. E waste collection centres have come up in many districts of Rajasthan.

E waste collection and processing in Rajasthan in metric tons is as follows:

1. 2018-2019 8478.24MT
2. 2019-2020 17028.17MT
3. 2020-2021 20816.74MT

Rajasthan State Pollution Control Board is regularly examining the scientific inventory of E waste, handled in the state.

The Rajasthan government wants to promote circular economy besides RIPS 2019. The state government will consider giving a package to E waste recycle units established in E waste recycling park Jaipur (growth of employment opportunities).

Rajasthan government will register the labour involved in E waste handling in informal sector on the portal of Rajasthan State labour department .The workers will be trained to handle hazards and processing of E waste .

Rajasthan State Pollution Control board will come out with mobile application to support E waste collection by funding under the start up policy of RSPSCB. Now school, college and university curriculum will carry chapters on E waste. A "GREEN CO" rating system for E waste processing units will be launched by Rajasthan State Pollution Control Board.

E-WASTE means the used electronic devices like desktop computers cell phone etc. After China our country is 3rd largest E waste producer. E waste is divided into two broad categories, like Information Technology and Communication devices and consumer durables.

There are laws for management of E waste, but their implementation is very difficult. E waste contains dangerous chemicals like Lead, Polychlorinated biphenyls, Polybrominated biphenyl mercury, and brominated flame retardants.

When E waste is burnt it emits Toxic chemicals, smoke which adversely effects Kidneys, Blood, nervous system and heart. When it is thrown in Landfill, the toxic chemicals get mixed up in ground water, land and harms marine life too.

E waste management Rule came in 2016-2017, the producers were made responsible for E waste collection and exchange of E waste. In India, 95% of E waste is in informal sector, the recycling is done in private sector, the scrap dealers burn it away in acids or use it though unscientific methods.

Against the target of 1.54 lakh tons in 2018-2019 the e waste collection was 78000 tons. E waste contains not only toxic chemicals like lead, mercury, cadmium, chromium but also polybrominated biphenyl and polybrominated depenil.

Lung cancer, breathing problems, Bronchitis, Mental disorders, and Asthma occurs due to toxic smoke and adverse effects on overall health of air quality index. E waste problem is an environmental issue leading to land water pollution, acidification of soil, ground water pollution and by burning PVC pipes(plastics), the air is polluted.

There are only 312 recycler plants in our country of which annual capacity is 800 kilo tons. In India about 10 lakh people are engaged in recycling E waste by hand. The labor in these factories is not registered so the rights of labor are not exercised, like wages, safety, and tracking is not possible.

So the solution is that first the adequately arranged and manage the manpower working in this sector should be their training, safety, old age, wages, pensions, working hours, job assurance, should be taken in account for better management of E waste.

देववाणी एप

संस्कृत शिक्षा में संचार तकनीक

मनीषी लालस
उप निदेशक, संस्कृत शिक्षा

संस्कृत दिवस के एक समारोह में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत

शिक्षा में सूचना एवं संचार तकनीक (ICT) का प्रयोग शिक्षण – अधिगम प्रक्रिया को आसान व प्रभावी बनाता है। ICT के प्रयोग से जटिल शिक्षण बिन्दुओं को बेहतर तरीके से समझाया जा सकता है। इसके अलावा शिक्षा में ICT का प्रयोग कोरोना महामारी जैसी स्थिति में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ शिक्षण को जारी रखने के लिए आवश्यक संसाधन भी मुहैया कराता है।

राज्य संस्कृत शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण संस्थान, महापुरा द्वारा देववाणी एप के रूप एक शैक्षिक नवाचार किया गया है। देववाणी एप कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों को संस्त सहित सभी विषयों के ई–कंटेट अध्याय अनुसार उपलब्ध कराता है।

एप के ई–कंटेट का निर्माण विभाग के तकनीकी रूप से दक्ष शिक्षकों द्वारा किया गया है जबकि एप मैनेजमेंट व ई–कंटेट चयन की समस्त प्रक्रिया राजस्थान राज्य संस्कृत शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान द्वारा की जा रही है। देववाणी एप की खास विशेषता यह है कि इसमें कोई सरकारी खर्च नहीं किया गया है। यह संस्कृत शिक्षा विभाग में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए संस्कृत शिक्षा विभाग के शिक्षकों द्वारा निर्मित एप है।

स्व मूल्यांकन की सुविधा

इस एप में शिक्षण बिन्दु पर आधारित वीडियो देखने पश्चात ऑनलाइन टेस्ट देने की सुविधा प्रदान की गई है जिससे छात्र स्व–मूल्यांकन कर सकें। टेस्ट के पश्चात टेस्ट का रिव्यू भी किया जा सकता है । किसी भी टेस्ट को सीधे सोशल मीडिया पर साझा भी किया जा सकता है ।

कक्षा एवं विषय अनुसार ई–कन्टेंट

देववाणी एप में कक्षा 1 से 12 तक सभी विषयों की शिक्षण सामग्री वीडियो, ऑनलाइन टेस्ट और पीडीएफ के रूप में प्रदान की गई हैं। वीडियोज में प्रजेन्टेशन और स्क्रीन रिकॉर्डिंग का प्रयोग किया गया है जो शिक्षकों द्वारा मोबाईल फोन के माध्यम से बनाए गए हैं ।

एप पंजीयन व प्रोफाइल सुविधा

देववाणी एप विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के लिए सिंगल क्लिक गूगल साइन इन और प्रोफाइल निर्माण सुविधा प्रदान करता है। प्ले स्टोर से एप इंस्टॉल करने के बाद आसानी से पंजीयन किया जा सकता है । पंजीयन के समय जिला ब्लॉक, विद्यालय व कक्षा का चयन किया जाता है ।

शिक्षकों को ई–कंटेंट जोड़ने की सुविधा

देववाणी एप में नवीन शिक्षण सामग्री जोड़ने के लिए शिक्षकों को सीधे एप से प्रश्न–उत्तर और वीडियो जोड़ने की सुविधा प्रदान की गई है। जोड़ी गई सामग्री को विद्यार्थियों को उपलब्ध कराने से पूर्व विभागीय टीम द्वारा जांचा जाता है।

वर्तमान में देववाणी एप पर 66 हजार यूजर्स पंजीकृत हैं। एप में 2400 वीडियोज और 12900 प्रश्नों का समावेश किया गया है। कोरोना लॉक डाउन के दौरान स्माइल लिंक्स को नियमित रूप से एप में जोड़ा गया और एप के माध्यम से रियल टाइम अलर्ट विद्यार्थियों को भेजे गए। एप की उपयोगिता प्ले स्टोर पर मौजूद फीडबैक एवं रेटिंग से लगाया जा सकता है। एप की रेटिंग 5 मे से 4.5 है।

देववाणी एप पर सर्वाधिक 9828 यूजर्स जयपुर के हैं। विद्यालयों में राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय, कुण्ड गेट सांवर, अजमेर प्रथम स्थान, राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय, जयपुर (जयपुर) द्वितीय जबकि राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय, गुढ़ा पदमसिंह (पाली) तीसरे स्थान पर है।

20 अगस्त: सद्भावना दिवस

पूर्व प्रधानमंत्री स्व. श्री राजीव गांधी की जयंती पर विशेष

आधुनिक भारत में सूचना क्रांति के शिल्पकार

डॉ. आशीष खण्डेलवाल
सहायक निदेशक, जनसम्पर्क

इक्कीसवीं सदी के भारत को सूचना एवं संचार क्रांति के माध्यम से दुनिया का सबसे मजबूत राष्ट्र बनाने का सपना संजोने वाले पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी आधुनिक सोच और निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता वाले असाधारण व्यक्तित्व के धनी थे। वे देश को दुनिया की अत्याधुनिक तकनीकों से लैस कर इसे ताकतवर विकसित देशों की श्रेणी में जल्द से जल्द लाना चाहते थे। आधुनिक भारत के शिल्पकार के रूप में दुनिया में मशहूर पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ऐसे दूरदर्शी नेता थे, जिन्होंने 21वीं सदी के आधुनिक भारत के निर्माण की आधारशिला रखी थी।

श्री राजीव गांधी ने दूरदर्शी सोच और कुशल नेतृत्व से अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल की शुरुआत से ही सूचना एवं संचार क्रांति की दिशा में युद्धस्तर पर कार्य करना शुरू कर दिया था। जिस कंप्यूटर और फोन के संचार तंत्र की बदौलत आज भारत ने तकनीक के क्षेत्र में अपना मजबूत स्थान बनाया है, वह संचार तंत्र देश को श्री राजीव गांधी ने ही दिया है। भारत के निर्माण का श्रेय जिस तरह पं. जवाहर लाल नेहरु को दिया जाता है, उसी तरह आधुनिक भारत के निर्माता श्री राजीव गांधी को माना जाता है। आधुनिक सोच के धनी श्री राजीव गांधी ने 20वीं सदी में ही भारत को 21वीं सदी का उन्नत राष्ट्र बनाने का सपना संजोया था, जो आज यथार्थ होता नजर आ रहा है।

श्री राजीव गांधी ने देश में शिक्षा, चिकित्सा और विज्ञान सहित कई क्षेत्रों में नई पहल की, जिनमें संचार क्रांति और कम्प्यूटर क्रांति, शिक्षा का प्रसार, 18 साल में युवाओं को मताधिकार, पंचायती राज, महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण, 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन की आधारशिला के रूप में पंचायती राज का सुदृढ़ीकरण महत्त्वपूर्ण है। जब कम्प्यूटर क्रांति का श्री राजीव गांधी ने सूत्रपात किया, तब रूढ़ीवादी सोच ने उनका विरोध किया, लेकिन उन्होंने भारत को मजबूत, आत्मनिर्भर और तकनीकी विकास के मार्ग के माध्यम से तेज रफ्तार से दौड़ता मुल्क बनाए रखने का कर्तव्य अंतिम सांस तक निभाया, जिसके दम पर आज भारत की तकनीक जगत की प्रतिभाएं विश्व में अपना परचम लहरा रही हैं।

श्री राजीव गांधी ने शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। वर्ष 1986 की शिक्षा नीति में दशकों से चले आ रहे शिक्षा के ढर्रे में क्रांतिकारी परिवर्तन किए गए। विद्यार्थी को न केवल अकादमिक ज्ञान, अपितु समाज के लिए उपयोगी बनाने की दिशा में विद्यालय स्तर से ही जुड़ाव, शारीरिक शिक्षा का पाठ्यक्रम में समावेश, जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना इनमें प्रमुख है।

श्री राजीव गांधी का जीवन परिचय

श्री राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त, 1944 को मुंबई में हुआ था। नाना पंडित जवाहर लाल नेहरु के भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बनने के बाद श्री राजीव गांधी ने बचपन अपने नाना के साथ तीन मूर्ति हाउस में बिताया था, जहां श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री नेहरु का सहयोग करती थीं। वे कुछ समय के लिए देहरादून के वेल्हम स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी गए, लेकिन जल्द ही उन्हें हिमालय की तलहटी में स्थित आवासीय दून स्कूल में भेज दिया गया। इसके बाद श्री राजीव गांधी लंदन के इम्पीरियल कॉलेज चले गए। वहां उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। उनकी संगीत में भी दिलचस्पी थी और उन्हें पश्चिमी और हिन्दुस्तानी शास्त्रीय और आधुनिक संगीत पसंद था। उन्हें

श्री राजीव गांधी ने अपने कार्यकाल में देश के निर्माण के लिए काफी महत्त्वपूर्ण कार्य किये। उन्हें देश में कंप्यूटराइजेशन और टेलीकम्युनिकेशन क्रांति का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल में देश में आईटी और टेलीकॉम क्षेत्र में जबरदस्त क्रांति लाने का काम किया।

फोटोग्राफी और रेडियो सुनने का भी शौक था, हवाई जहाज उड़ाना उनके जीवन का जुनून था। इंग्लैंड से घर लौटने के बाद उन्होंने दिल्ली फ्लाइंग क्लब की प्रवेश परीक्षा पास की और व्यावसायिक पायलट का लाइसेंस हासिल किया। इसके बाद वे इंडियन एयरलाइंस के सफल पायलट बन गए। उत्तर प्रदेश के अमेठी लोकसभा क्षेत्र से उपचुनाव लड़कर विजयी बने। फिर उन्हें नवंबर, 1982 में भारत में हुए एशियाई खेलों से संबंधित महत्त्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई, जिसे उन्होंने उल्लेखनीय उपलब्धियों के साथ पूरा किया।

31 अक्टूबर, 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद मात्र चालीस वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले युवा राजीव गांधी देश के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे। जब वे देश के प्रधानमंत्री बने, तो उस समय देश के सामने बहुत सारी ज्वलंत विकराल समस्याएं खड़ी थीं, जैसे पंजाब, असम और मिजोरम की अंदरूनी हिंसा। श्री राजीव गांधी ने अपनी व्यवहार कुशलता, सादगी और दूरदर्शिता से समस्याओं का समाधान शुरू किया। उन्होंने अपने इक्कीसवीं सदी के भारत के सपने को साकार करने के लिए देश के कई क्षेत्रों में बहुत तेजी से नई पहल करने की शुरुआत की, जिनमें संचार क्रांति, कंप्यूटर क्रांति, शिक्षा का प्रसार, 18 साल के युवाओं को मताधिकार आदि मुख्य रूप से शामिल हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यकाल में कई ऐसे महत्त्वपूर्ण फैसले किए, जिसका असर आज देश के विकास में स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। आज हर हाथ में दिखने वाला मोबाइल फोन व हर घर में मौजूद कम्प्यूटर श्री राजीव गांधी के उन्हीं शानदार फैसलों का नतीजा है।

श्री राजीव गांधी ने अपने कार्यकाल में देश के निर्माण के लिए काफी महत्त्वपूर्ण कार्य किये। उन्हें देश में कंप्यूटराइजेशन और टेलीकम्युनिकेशन क्रांति का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल में देश में आईटी और टेलीकॉम क्षेत्र में जबरदस्त क्रांति लाने का काम किया। वे सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की भूमिका को बहुत अहम मानते थे। उन्होंने ही देश में सबसे खास तकनीक यानी कंप्यूटर के इस्तेमाल को आम आदमी तक पहुंचाने की शुरुआत की थी। साइंस और टेक्नॉलोजी को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने सरकारी बजट बढ़ाए। इसके चलते आज भी देश में रोजगार के भरपूर अवसर हम सभी भारतवासियों को सम्पूर्ण विश्व में मिल रहे हैं, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को लगातार मजबूती मिल रही है।

श्री राजीव गांधी ने ही वर्ष 1986 में शिक्षा का स्तर सुधारने के उद्देश्य से राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ऐलान किया। इसके तहत देश में जवाहर नवोदय विद्यालयों का निर्माण किया गया, जिनके माध्यम से आज लाखों ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को अच्छी उच्च गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा मिल रही है। साथ ही उनके नेतृत्व में वर्ष 1986 में महानगर टेलीफोन

श्री राजीव गांधी ने दूरदर्शी सोच और कुशल नेतृत्व से अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल की शुरुआत से ही सूचना एवं संचार क्रांति की दिशा में युद्धस्तर पर कार्य करना शुरू कर दिया था। कम्प्यूटर और फोन के संचार तंत्र की बदौलत आज भारत ने तकनीक के क्षेत्र में अपना मजबूत स्थान बनाया है, वह संचार तंत्र देश को श्री राजीव गांधी ने ही दिया है। भारत के निर्माण का श्रेय जिस तरह पं. जवाहर लाल नेहरू को दिया जाता है, उसी तरह आधुनिक भारत के निर्माता श्री राजीव गांधी को माना जाता है।

निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) की स्थापना की गई थी। इसके तहत पीसीओ के जरिए एक तरफ जहां देश के शहरी व ग्रामीण इलाकों में संचार सेवा का बहुत तेजी से विस्तार हुआ था, वहीं दूसरी तरफ लोगों के लिए रोजगार के नये अवसर मिले थे। उनका सपना था कि हमारे देश के गांव-गांव में टेलीफोन पहुंचे और कंप्यूटर शिक्षा का देश में जमकर प्रचार-प्रसार हो।

अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल में श्री राजीव गांधी ने देश की युवाशक्ति को अत्यधिक महत्त्व दिया था, क्योंकि उनका मानना था कि देश का विकास युवाओं के द्वारा ही हो सकता है। देश के युवाओं को रोजगार मिले, इसके लिए वो हमेशा प्रयासरत रहे और उन्होंने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जवाहर रोजगार योजना शुरू की थी, जिसने देश के युवाओं को बड़ा संबल दिया था। श्री राजीव गांधी ने स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत रिजर्वेशन दिलवाने की दिशा में भी काम किया। मतदाता की उम्र 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष तक के युवाओं को चुनाव में वोट देने का अधिकार दिलवाने में भी श्री राजीव गांधी अग्रदूत रहे हैं। उन्होंने अपने 'पावर टू द पीपल' आइडिया के चलते ही देश में पंचायती राज व्यवस्था लागू करवाने की दिशा में कई कदम उठाये थे।

श्री राजीव गांधी ने अपने कार्यकाल में कई साहसिक कदम उठाए, जिनमें श्रीलंका में आईपीकेएफ (शांति सेना) का भेजा जाना, असम समझौता, पंजाब समझौता, मिजोरम समझौता आदि शामिल हैं। इसकी वजह से ही कुछ चरमपंथी ताकतें उनकी दुश्मन बन गयी थी। श्रीलंका में सलामी गार्ड के निरीक्षण के वक्त उन पर हमला किया गया, जिसमें वे बाल-बाल बच गए थे। श्री राजीव गांधी जब देश में आम चुनाव के प्रचार के लिए 21 मई, 1991 को तमिलनाडु के श्रीपेरम्बुदूर गए, जहां एक आत्मघाती हमले में उनकी मृत्यु हो गई।

श्री राजीव गांधी भारतीय इतिहास के ऐसे अप्रतिम प्रगति पुरुष हैं, जिन्हें निर्विवाद रूप से परंपरा और प्रगति को जोड़ने वाला 'अग्रपुरुष' स्वीकार किया जा सकता है।

राजनैतिक आख्यान संग्रहालय का लोकार्पण

राजनैतिक आख्यान संग्रहालय

राजस्थान के राजनैतिक आख्यानों का वर्णन करने वाला देश का अनूठा म्यूजियम

डॉ. लोकेश चन्द्र शर्मा
उप निदेशक, जनसम्पर्क

विधानसभा भवन के ऊपरी व निचले भूतल में 21 हजार स्क्वायर फीट में राजस्थान आख्यान संग्रहालय का निर्माण किया गया है। यह विशाल संग्रहालय अत्याधुनिक तकनीकी माध्यमों से राजस्थान की गौरवमयी गाथा और राजनैतिक आख्यानों को प्रस्तुत कर रहा है। संग्रहालय में वर्तमान राजस्थान व उसकी संरचना, राज्य के निर्माण में सहभागी रहे जन नेताओं और निर्माताओं के योगदान को आम नागरिक देख सकते हैं। कलात्मकता और आधुनिकता के पर्याय इस संग्रहालय में विधानसभा की कार्यप्रणाली और विभिन्न प्रक्रियाएं, राजस्थान के

मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष, विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों और विधायकगण के बारे में जानकारी भी प्रदर्शित की गई है। मंत्रिमंडल, विपक्ष के नेता और अन्य जनप्रतिनिधियों की भूमिका को प्रदर्शित करता यह संग्रहालय पूरे देश में उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है।

डिजिटल म्यूजियम में आगंतुक अत्याधुनिक तकनीकी माध्यमों से लोकतंत्र, विधानसभा के कार्य और प्रशासन प्रणाली तथा सामान्य नागरिक से जनता के सर्वोच्च प्रतिनिधि तक की यात्रा का सफर देख सकते हैं। चालीस से अधिक इंस्टॉलेशन और विभिन्न टेक्नोलॉजी से सुसज्जित यह डिजिटल म्यूजियम नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा का सतत स्रोत होगा। संग्रहालय में आधुनिकतम तकनीकों का प्रयोग किया गया है।

यह संग्रहालय राज्य की शानदार विरासत और परम्पराओं का अमूल्य संग्रह है। विधानसभा में बना ये अनूठा संग्रहालय आने वाली पीढ़ियों को राजस्थान के राजनैतिक आख्यानों से परिचित कराएगा।

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सी.पी. जोशी के अनुसार विधानसभा के इस डिजिटल संग्रहालय में राजस्थान के निर्माण और राजनैतिक आख्यानों को कालातीत कलात्मकता और आधुनिक तकनीकी संचार के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। इसके निर्माण का उद्देश्य राजस्थान के गौरवशाली राजनैतिक इतिहास को प्रदर्शित करने के साथ लोगों को राजनैतिक कार्यवाहियों और व्यवस्थाओं से अवगत कराना है।

राजस्थान विधानसभा भवन में उकेरे गये इस विशाल संग्रहालय में राजस्थान की राजनीतिक विरासतों का डिजिटल प्रदर्शन रोचक तरीके से किया गया है। विधान सभा में विधेयक कैसे पारित होते हैं और कैसे ये कानून में परिणीत होते हैं, इनके जवाबों के साथ विधानसभा अध्यक्ष, सदन के नेता और विपक्ष के नेता के अधिकारों व भूमिकाओं का विस्तृत विवरण भी इस म्यूजियम में प्रदर्शित किया गया है।

दो मंजिलों में विस्तारित इस भव्य म्यूजियम में विधानसभा अध्यक्षों एवं मुख्यमंत्रियों सहित विभिन्न गण्यमान्य के जीवन बिन्दुओं से

भी लोग परिचित हो सकेंगे। यह संग्रहालय राज्य की शानदार विरासत और परम्पराओं का अमूल्य संग्रह है। विधान सभा में बना ये अनूठा संग्रहालय आने वाली पीढ़ियों को राजस्थान के राजनैतिक आख्यानों से परिचित कराएगा। राजस्थान विधानसभा के सचिव श्री महावीर प्रसाद शर्मा के अनुसार विधानसभा भवन में जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा

संग्रहालय में प्रदर्शित विभिन्न तकनीक

3डी प्रोजेक्शन मैपिंग	एनिमेटेड डायोरामा
इंटेरेक्टिव कियोस्क	होलोग्राम
वर्चुअल रियालिटी	टॉकबैक स्टूडियो
फिल्म्स ऑन स्क्रीन	मैकेनाईज्ड इंस्टोलेशन
डायनमिक इंस्टोलेशन	

डिजिटल संग्रहालय का निर्माण किया गया है। इसका उद्घाटन भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री एन.वी. रमणा ने किया। संग्रहालय में राजस्थान की गौरवमयी गाथा, राजनैतिक अतीत और वर्तमान राजस्थान व उसकी संरचना को डिजिटल माध्यम से प्रस्तुत किया गया

छाया: पुष्पेन्द्र व्यास

है। संग्रहालय में राजस्थान की राजनैतिक और ऐतिहासिक विशेषताओं के साथ-साथ राज्य की समृद्ध संस्कृति को भी प्रदर्शित किया गया है। संग्रहालय मात्र एक भवन ही नहीं बल्कि यह राज्य के भूतकाल और भविष्य का सुदृढ़ सेतु है। यह संग्रहालय निःसंदेह युवाओं को जिज्ञासु बनाने में सहायक होगा।

राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल

सफल आयोजन के लिए निचले स्तर तक पुख्ता कार्य योजना तैयार

लीलाधर
सहायक निदेशक, जनसम्पर्क

राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन 29 अगस्त से होगा। इसमें राजस्थान के 30 लाख खिलाड़ी शामिल होंगे। इसका मुख्य उद्देश्य राजस्थान में खेलों का माहौल बनाकर ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ियों को आगे लाना है। सभी जिलों में ओलंपिक खेल की मशाल पहुंच चुकी है। जिलों के बाद विजेता टीमों के बीच राज्य स्तरीय खेल जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में होंगे।

स्थानीय स्तर पर इस आयोजन का पर्याप्त प्रचार की योजना बनाई गई है। राज्य सरकार खेल एवं खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए कई महत्त्वाकांक्षी योजनाएं चला रही है। ग्रामीण ओलंपिक खेलों से न केवल नए खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा, बल्कि आमजन की खेलों में रुचि भी जाग्रत होगी।

29 अगस्त से शुरू हो रहे ग्रामीण ओलंपिक का क्रियान्वयन बेहतर हो, इसके लिए कार्ययोजना बनाकर प्रत्येक स्तर पर जिम्मेदारी दी गई है। ये खेल वृहद स्तर पर आयोजित किए जा रहे हैं। इसलिए ग्राम पंचायत स्तर, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर तथा राज्य, सभी स्तरों पर आयोजन के लिए विस्तृत रूपरेखा बनाई गई है। ग्राम पंचायत सहित सभी स्तरों पर चयन समिति बनाई गई है ताकि टीमों का गठन सही तरीके से हो सके। ग्राम पंचायत, ब्लॉक तथा जिला स्तर पर खेल उपकरणों की खरीद तथा विजेता टीमों को अगले स्तर पर भेजने की व्यवस्था सुचारु रूप से किया जाना सुनिश्चित किया जा रहा है। प्रतियोगिता में पुरुष वर्ग के 20 लाख एवं महिला वर्ग में 10 लाख खिलाड़ी शामिल होंगे। ग्राम स्तर पर खेल प्रतिभाओं की खोज के मकसद के लिए राज्य खेलों की तर्ज पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर इन खेलों का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश के 11 हजार 341 पंचायत और 352 ब्लॉक स्तर पर खेलों का आयोजन हो रहा है। ग्राम स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर पर आयोजन कमेटियों का गठन हो गया है। पंचायत स्तर पर सरपंच को कमेटी का संयोजक बनाया गया है। उपखंड अधिकारी कमेटी के संयोजक होंगे।

ग्रामीण ओलंपिक खेलों के तहत 6 प्रकार के खेलों को शामिल किया गया है। इन खेलों में कबड्डी, शूटिंग बॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, खो-खो तथा टेनिस बॉल क्रिकेट की प्रतियोगिताएं होंगी। ग्राम पंचायत स्तर पर 29 अगस्त से लेकर चार दिनों तक नॉकआउट मैचों का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद ब्लॉक स्तर पर 12 सितंबर से चार दिवस तक तथा जिला स्तर पर 22 सितंबर से तीन दिन तक मैचों का आयोजन होगा। राज्य स्तर पर 2 अक्टूबर से चार दिवस तक मैचों का आयोजन होगा। ●

राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल किसी भी राज्य द्वारा आयोजित सबसे बड़ा ऐतिहासिक खेल आयोजन होगा। इसमें कोई विचारधारा नहीं होगी। यह आयोजन राजस्थान में अभूतपूर्व खेल वातावरण तैयार करेगा। राजस्थान के गांव-ढाणी की खेल प्रतिभाओं को राज्यस्तरीय मंच मिलेगा और प्रदेश को भविष्य के लिए उभरते खिलाड़ी मिलेंगे। मित्रतापूर्ण खेलों से ग्रामीणों में आपसी सामंजस्य और सद्भाव बढ़ेगा। मैदान पर जब दादा-पोता और चाचा-भतीजा खेलने उतरेंगे तो रिश्तों में और मजबूती आएगी तथा गांवों में खेल भावना का विकास होगा।

अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री, राजस्थान

मानगढ़ धाम, बांसवाड़ा

राजस्थान का जनजाति बहुल दक्षिणांचल वागड़ (बांसवाड़ा व डूंगरपुर जिला) न सिर्फ अपनी आदिम संस्कृति के लिए देश-प्रदेश में जाना-पहचाना जाता है अपितु यह अंचल आजादी के इतिहास की एक ऐसी घटना का भी साक्षी है जिसमें महान संत गोविन्द गुरु के नेतृत्व में 1500 आदिवासी गुरुभक्तों ने अपना बलिदान दिया। बांसवाड़ा जिलान्तर्गत आनंदपुरी से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित मानगढ़ धाम पहाड़ ही वह स्थान है जहां पर 17 नवंबर, 1913 मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर गुरु का जन्मदिन मनाने के लिए एकत्र हुए हजारों गुरुभक्तों को ब्रिटिश सेना ने मौत के घाट उतार दिया था। बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले सहित सरहदी क्षेत्रों में गोविन्द गुरु और शिष्यों द्वारा स्थापित धूणियां आज भी उस बलिदान की साक्षी हैं। वर्तमान में इस स्थान पर गुरुभक्तों के बलिदान की याद दिलाता विशाल स्तंभ, गोविंद गुरु की प्रस्तर प्रतिमा, पत्थरों पर उत्कीर्ण बलिदान गाथा के चित्र, धूणी, गोविंद गुरु पैनोरमा और उद्यान आकर्षण का केन्द्र हैं।

आलेख एवं छाया : डॉ. कमलेश शर्मा

Postal Regd. No. Jaipur City/413/2020-22
Registered with Registrar of Newspapers of India under R. No. 56175/1991

राजस्थान सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रम और अन्य योजनाओं की विस्तृत जानकारी
https://jankalyan.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।

#DIPRRajasthan

प्रकाशक व मुद्रक – सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशक, पुरुषोत्तम शर्मा द्वारा सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के लिए, शासन सचिवालय, जयपुर (राजस्थान) से प्रकाशित सम्पादक – श्रीमती अलका सक्सेना, मै. कृष्णा प्रिन्टर्स, डी–14, सुदर्शनपुरा, जयपुर से मुद्रित, 'राजस्थान सुजस'–पृष्ठ संख्या 60, लागत मूल्य 30.56 रुपये ● 5,00,000 प्रतियां